चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

25 फरवरी–03 मार्च 2013

मूल्य 5 रुपये

मधुबनी कांड : आख़िर इस लड़के का गुनाह क्या है?

पेज : 6

शेखावटी उत्सव

पेज : 7

परमाणु हथियार की होड़ का ज़िम्मेदार कौन है?

पेज : 11

पारंपरिक खेलों को सहेजता शेखावटी उत्सव

पेज : 15

फोटो–प्रभात पाण्डेय

बिहार में अधिकारियों का राज

मनीष कुमार

बिहार में अधिकारियों की तानाशाही है और वहां के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं. राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. भ्रष्टाचार ख़त्म करने की सिर्फ़ बातें होती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अंततः नहीं होती. दरअसल, पिछले कार्यकाल की जो भी उपलब्धि थी, उसका असर धीरे–धीरे ख़त्म हो रहा है. बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की हालत ख़राब है और सरकार की साख संकट में है. लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की आंखों पर अधिकारियों ने पट्टी बांध दी है या फिर वह सब कुछ जानते हुए भी इसे नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. वह जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा अधिकारियों की सुनते हैं. नीतीश कुमार जननेता हैं और कुछ लोग उन्हें एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं. इसलिए ऐसी ग़लती की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती.

पटना के चाणक्य होटल के नज़दीक आर ब्लाक का गेट है. यहां सप्ताह में तीन चार विरोध प्रदर्शन होते हैं. बिहार सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों के लिए यह आखिरी पड़ाव है. वे इससे आगे नहीं जा सकते. गेट को बंद कर दिया जाता है. भारी संख्या में पुलिस होती है. वाटर कैनन होता है. प्रदर्शनकारी अगर उग्र होने की ज़रा–सी भी कोशिश करते हैं, तो यह इलाक़ा तुरंत कुरुक्षेत्र में बदल जाता है. फिर क्या, प्रदर्शनकारियों का शरीर होता है और पुलिस का डंडा. पटना में विरोध प्रदर्शन और उन पर लाठी चार्ज की घटना आम है. पटना के लोग कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास से इतनी दूर इसलिए रोक दिया जाता है, ताकि लोगों की आवाज़ नीतीश कुमार के कानों तक न पहुंच सके और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यह समझते रहें कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है.

बिहार का राजनीतिक माहौल बदल रहा है. लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं. नीतीश सरकार से लोग निराश होने लगे हैं. निराशा की कई वजहें हैं. एक, सरकारी भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं. भ्रष्टाचार से ज़्यादा सरकारी दफ्तरों के रवैये से लोगों में गुस्सा है. नीतीश सरकार ने सड़कें बनाकर लोगों का दिल ज़रूर जीता था, लेकिन अब वे सड़कें भी जर्जर होने लगी हैं, जो सड़क नहीं बन सके, वे अब तक नहीं बने. पानी की समस्या है. बिजली की समस्या का अब तक कोई निदान नहीं हुआ. लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आशाएं थीं, जो अब निराशा में तब्दील होने लगी हैं और इसलिए वे अब सरकार के ख़िलाफ़ संगठित होने लगे हैं. शायद, नीतीश कुमार को भी लोगों के मूड का आभास है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह बिहार में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं और उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन सिर्फ बयान देने से बात नहीं बनती. बिहार के लोग, ग़रीब ज़रूर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं, इसलिए बयानों के महत्व को वे भली–भांति समझते हैं.

नीतीश कुमार की सरकार से सबसे ज़्यादा परेशान जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं. वे मुख्यमंत्री से सीधे नहीं मिल सकते. मुख्यमंत्री जी को भी यह पता है, लेकिन अगर उनसे इस मसले पर कोई सवाल पूछता है, तो वह तुरंत पार्टी अनुशासन और राजनीतिक विवशता की वजह से कोई मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के विधायक ख़ुद को कमज़ोर महसूस इसलिए करते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने भी विधायकों की बातों को सुनना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में विधायकों को अपने वोटरों के सामने लज्जित होना पड़ता है. यही वजह है कि वे किसी अधिकारी को फोन करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते.

नीतीश कुमार ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से दूरी बना ली है, बल्कि जनता से भी दिन–ब–दिन दूर होते चले जा रहे हैं. उनको जनता ने जिस तरह समर्थन दिया, उन्हें जितनी सीटें दिलाईं, वह ऐतिहासिक है, लेकिन पिछले दिनों संपन्न अधिकार रैली की भीड़ देखकर नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर सवाल उठता ही है. जेडीयू के विधायक बताते हैं कि रैली पर बहुत पैसा ख़र्च हुआ, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख लोग गांधी मैदान पहुंचे.

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उदासीनता छाई है. मुख्यमंत्री के सामने न कोई मंत्री मुंह खोलने की हिम्मत करता है और न ही विधायक को बेधड़क मिलने की आज़ादी है. वहीं ज़्यादातर कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री की झलक तक नहीं ले पाते हैं. जेडीयू के लोग नीतीश कुमार को अब राजा कहकर संबोधित करने लगे हैं.

नीतीश कुमार से लोगों की आशाएं बंधी हैं. नीतीश को दिल खोल कर लोगों ने वोट दिया. अब बिहार में निराशा का दौर है. नीतीश कुमार के सामने किसी विपक्ष की चुनौती नहीं है. उन्हें तो लालू यादव को धन्यवाद देना चाहिए कि आज भी लोग लालू यादव के शासनकाल के बारे में सोच कर ही थर्रा उठते हैं.

नाराज हो जाते हैं. हक़ीक़त यही है कि 52 विधायक अब तक मुख्यमंत्री से मुलाक़ात भी नहीं कर पाए हैं. कई लोगों का अभी तक उनसे आमना–सामना भी नहीं हुआ. यह भी एक अविश्वसनीय सच्चाई है कि मुख्यमंत्री अपने सभी विधायकों को नहीं पहचानते. वैसे भी जिन विधायकों की मुलाक़ात उनसे होती है, वे भी उनसे मिलने के बाद निराश ही लौटते हैं. बताया यह भी गया कि इसमें सिर्फ एक विधायक ने क़रीब एक लाख लोगों को गांधी मैदान पहुंचाने का इंतज़ाम किया था. अधिकार रैली में जो भी लोग आए, उसकी व्यवस्था मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, कौशल यादव, सुनील पांडे और धूमल सिंह ने की थी. कहने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

क्या बिहार में अघोषित सेंसरशिप है

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस काटजू ने एक कमेटी बनाकर नया विवाद शुरू किया है. उनका मानना है कि बिहार में अघोषित सेंसरशिप लागू है. मीडिया पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं और इसलिए वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है. दरअसल, जो बात जस्टिस काटजू आज कह रहे हैं, उसे चौथी दुनिया ने सबसे पहले 2009 में हूबहू छापी थी. उन दिनों चौथी दुनिया ने लिखा था- मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है. लेख छपने के बाद बिहार में बड़ा हंगामा हुआ था. विपक्ष ने विधानसभा के अंदर चौथी दुनिया अख़बार को लेकर हंगामा किया. लालू यादव और रामविलास पासवान ने अख़बार की प्रति लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी की. जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं, इसलिए प्रेस के अधिकारों के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि इसमें नीतीश कुमार की सरकार का दोष कम है. मीडिया अगर ख़ुद ही पत्रकारिता छोड़ चाटुकारिता करने लग जाए, तो इसमें किसी सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं. चौथी दुनिया अब तक सच्चाई को छापती आई है. बिहार की हर गड़बड़ियों को बेधड़क छापा है. इमरजेंसी होती, तो हम पर भी प्रतिबंध लगता. सरकार तंग करती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. न ही हमारे ख़िलाफ़ नीतीश सरकार ने कुछ किया और न ही कोई प्रलोभन दी. हम आज भी नीतीश कुमार की सरकार की कमियों को बेधड़क लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे.

पिछले चुनाव के दौरान चौथी दुनिया ने यहां तक छापा कि नीतीश अहंकारी हो गए हैं. यह लेख नीतीश कुमार के काम करने के तरीक़े पर लिखी गई थी. नीतीश नाराज़ हुए और उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को ही बदल दिया. हां, चुनाव जीतने के बाद अपने पहले प्रेस कांफ्रेंस में चौथी दुनिया के संवाददाता को नीतीश कुमार ने यह ज़रूर कहा कि चौथी दुनिया को वह इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि यह अकेला अख़बार है, जिसे बिहार में सिर्फ बुराई नज़र आती है. नीतीश कुमार की सरकार में बहुत कमियां हैं, जिन्हें हर अख़बार को उजागर करना चाहिए. अगर अख़बार विज्ञापन के लालच में चारण बन जाए, तो दोष किसका है. प्रेस की आज़ादी की बात तो तब आती है, जब न्यूज चैनल और अख़बार स्वयं आज़ाद होना चाहें. इसलिए प्रेस काउंसिल को इस बात की जांच करनी चाहिए कि कौन अख़बार नीतीश कुमार या केंद्र की यूपीए सरकार की चाटुकारिता में लगी हुई है और उसके कारण क्या हैं. उन एडिटरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो केंद्र और राज्य सरकारों से फ़ायदा उठाकर प्रेस की आज़ादी को बेचते हैं. जस्टिस काटजू के सामने बड़ी चुनौती है. देश में पत्रकारिता की साख दांव पर लगी है. सरकार के एजेंट की तरह काम करने वाले पत्रकारों और एडिटरों की लिस्ट काफी लंबी है. यही वजह है कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है. जस्टिस काटजू को ऐसे पत्रकारों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए, जो जन पत्रकारिता छोड़ सरकार के लिए पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं.■

CHAUTHI DUNIYA

Now in English

Rs 5

Available at your nearest news stand

प्रधान सचिव सुमित मल्लिक ने एक साल की छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि आबकारी विभाग के अतिरिक्त प्रभार वापस लिए जाने की उनकी अपील ख़ारिज कर दी गई है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

पृथ्वीराज चह्वाण की चुनौती

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी की समस्या तो हर राज्य में है. एक अनुमान के अनुसार, क़रीब 3000 अधिकारियों की कमी है. महाराष्ट्र में तो इसकी स्थिति और भी बदतर है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए राज्य का कामकाज प्रभावित भी हो रहा है. महाराष्ट्र में अभी केवल 298 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि इसे 352 आईएएस अधिकारी आवंटित किए गए हैं. अधिकारियों की कमी के कारण कई अधिकारियों को एक से अधिक विभाग संभालने पड़ रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि काम के बोझ के कारण कई अधिकारी छुट्टी पर जाना चाहते हैं. प्रधान सचिव सुमित मल्लिक ने एक साल की छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि आबकारी विभाग के अतिरिक्त प्रभार वापस लिए जाने की उनकी अपील ख़ारिज कर दी गई है. हालांकि मुख्यमंत्री ने उनकी छुट्टी के आवोदन को एक साल से घटाकर छह महीने कर दिया है. कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति दूसरे विभागों की भी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी अपने काम से ख़ुश नहीं हैं, जिसके कारण वह तीन महीने की मेडिकल लीव पर थे. वरिष्ठ अधिकारी मालिनी शंकर ने भी अपनी मेडिकल लीव की अवधि बढ़ा दी है, क्योंकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री ने उनके साथ ग़लत भाषा का इस्तेमाल किया था. अब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण के सामने यह कड़ी चुनौती है कि वह अधिकारियों को कैसे ख़ुश करते हैं और उनसे कैसे काम लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों की कमी की समस्या फ़िलहाल ख़त्म होती नहीं दिखाई पड़ रही है. ■

क़ानून मंत्रालय की समस्या

सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन नरीमन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. महत्व-पूर्ण बात यह है कि नरीमन ने इस्तीफ़ा क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार के साथ काम करने में कुछ परेशानी के कारण दिया है. अश्विनी कुमार के सामने एक और समस्या है. कई विधि अधिकारियों को मंत्रालय में हुई सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति से न केवल परेशानी है, बल्कि दुखी भी हैं. सूत्रों का कहना है कि बाबुओं के दुखी होने का कारण यह है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति नियम क़ानून को ताख़ पर रखकर की गई है. मंत्रालय के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अभी यहां कई पद ख़ाली पड़े हैं. सूत्रों का कहना है कि लॉ सचिव बीए अग्रवाल भी नाख़ुश दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के लिए आवेदन किया है. ग़ौरतलब है कि लॉ सचिव के तौर पर बीए अग्रवाल भी सीईआरसी (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) के चेयरमैन पद की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी के सदस्य हैं. अब अश्विनी कुमार इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, यह तो समय ही बताएगा. ■

कर्नाटक का अगला मुख्य सचिव

कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को मुख्य सचिव की नियुक्ति का निर्णय लेना है, जबकि उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है. राज्य के निवर्तमान मुख्य सचिव एसवी रंगनाथ इसी साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जगदीश शेट्टार को उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर फ़ैसला लेना है, क्योंकि अगर चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा. सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में सामन्यतः अतिरिक्त मुख्य सचिव को ही अगला मुख्य सचिव बनाया जाता रहा है. अगर ऐसा किया गया, तो एलवी ना-गराजन, अरविंद जाधव, कौशिक मुखर्जी और सुधीर कृष्णा में से किसी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है. मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए अभी इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन जगदीश शेट्टार को जल्दी निर्णय लेना है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद परेशानी होगी. ■

dilipcherian@gmail..com

बिहार में अधिकारियों का राज

पृष्ठ एक का शेष

का मतलब यह है कि यह रैली आम जनता की नहीं थी. ख़ैर, पर्दे के पीछे का सच जो भी हो, लोगों की संख्या के हिसाब से इस रैली को सफल कहा जा सकता है. हालांकि इस रैली से अगर नीतीश कुमार की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जाए, तो यह रैली कई सवालों को जन्म देता है. इस रैली की तैयारी में स्वयं नीतीश कुमार को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर उन्हें कार्यक्रमों को भी रद्द करना पड़ा था.

नीतीश कुमार की पार्टी में संजय झा के दख़ल से बड़ा रोष है. लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने इस बात को उठाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती. संजय झा के बारे में बताया जाता है कि वह पार्टी के सभी नेताओं पर भारी पड़ते हैं. उनकी हैसियत इन दिनों वैसी हो गई है, जैसी कभी ललन सिंह की होती थी. यह सबको पता है कि संजय झा पहले अरुण जेटली के दफ्तर में काम करते थे, इसलिए उन्हें भाजपा के कामकाज को देखने के लिए बिहार भेजा गया. वह नीतीश कुमार को इतना भाए कि वह बीजेपी छोड़ जेडीयू में आ गए और सर्वेसर्वा बन गए. जेडीयू के नेता इस बात से परेशान हैं कि आख़िर संजय झा की ख़ासियत क्या है. उनका क्या जनाधार है. नेताओं, विधायकों और सांसदों की यह नाराजगी फ़िलहाल सार्वजनिक ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, यह भी एक सवाल है. क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए, यह किसी को पता नहीं होता.

नीतीश कुमार जनता से भी दूर हो रहे हैं. उनका जनता दरबार सिर्फ दिखावा भर रह गया है. आश्चर्य की बात तो यह है कि लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई तो होती ही नहीं, उल्टा शिकायत करने वाले ही परेशान हो जाते हैं. दरअसल, होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी की शिकायत लेकर जाता है और अपनी दास्तां सुनाता है, तो मुख्यमंत्री जी उनकी शिकायत को अधिकारियों को सौंप देते हैं. और वह अधिकारी वापस उसे अपने जूनियर अधिकारी को दे देता है. इस तरह वह शिकायत वहीं पहुंच जाता है, जिसके ख़िलाफ़ शिकायत होती है. अब जब उस अधिकारी को पता चलता है कि उसके ख़िलाफ़ फलां व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, तो उसे सबक सिखाने के लिए वह अधिकारी उसे जलील करना शुरू कर देता है. ऐसे कई उदाहरण हैं. एक कटु सत्य यह भी है कि जिन लोगों को नीतीश कुमार से उम्मीद थी, वे अब निराश हो रहे हैं, इसलिए उनके जनता दरबार में लोगों की भीड़ धीरे-धीरे कम होती जा रही है.

जब कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी को कोसने लगे, उस पार्टी का तो अल्लाह ही मालिक है. दरअसल, जिस पार्टी में सांसदों को अपनी राय रखने की अनुमति न हो या उनकी रायों को सुनने वाला कोई न हो, ऐसी पार्टियों को आप क्या कहेंगे. जिस पार्टी के विधायक को अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़े, उस पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी खुश नहीं रह सकते. जब विधायक अपनी ही पार्टी की सरकार से निराश हो जाए, तो यह मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार का नियंत्रण पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब नहीं रह गया है. जब कोई मुख्यमंत्री, अपने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद यहां तक कि मंत्रियों से दूरी बना ले, तो यह मान लेना चाहिए कि उस पार्टी का भविष्य सुनहरा नहीं है. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उदासीनता छाई है. मुख्यमंत्री के सामने न कोई मंत्री मुंह खोलने की हिम्मत करता है और न ही विधायक को बेधड़क मिलने की आज़ादी है. वहीं ज़्यादातर कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री की झलक तक नहीं ले पाते हैं. जेडीयू के लोग नीतीश कुमार को अब राजा कहकर संबोधित करने लगे हैं. उनकी मीठी-मीठी बातें और विकास के दावे को लोग अब खोखला समझने लगे हैं.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

एक टीवी चैनल ने पिछले दिनों बिहार में एक सर्वे किया. सवाल था कि वे किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. इस सर्वे के मुताबिक़, 55 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि सिर्फ 35 फ़ीसदी लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई. नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त का अंदाज़ा है. नीतीश कुमार पहले बीजेपी पर हावी रहते थे, लेकिन अब बीजेपी एग्रेसिव है. इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब भी कोई जेडीयू का नेता बीजेपी या नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बयान देता है, तो उसे फटकार ज़रूर लगती है. पार्टी की तरफ से यह पाबंदी लगा दी गई है कि बिना मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी नेता या कार्यकर्ता बयान नहीं देगा. यहां तक कि प्रवक्ताओं पर भी बैन लगा दिया गया है. इसका उदाहरण बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह हैं. उन्होंने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे. यह सुनते ही नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर फटकार लगाई. उन्होंने भीम सिंह को साफ कहा कि आप इस्तीफ़ा दीजिए या फिर माफ़ी मांगिए. भीम सिंह ने प्रेस कांफ्रेस की और अपना बयान वापस लिया. कहा, मेरे बयान से मुख्यमंत्री आहत और दुखी हैं. इसलिए मेरे बयान की ऐसी की तैसी.

नीतीश कुमार से लोगों की आशाएं बंधी हैं. जब वह मुख्यमंत्री बनें, तो लोगों को लगा कि बिहार में बदलाव होगा. पहले कार्यकाल में बदलाव दिखा भी, इसलिए धीरे-धीरे लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ीं. नीतीश को दिल खोल कर लोगों ने वोट दिया. अब बिहार में निराशा का दौर है. नीतीश कुमार के सामने किसी विपक्ष की चुनौती नहीं है. उन्हें तो लालू यादव को धन्यवाद देना चाहिए कि आज भी लोग लालू यादव के शासनकाल के बारे में सोच कर ही थर्रा उठते हैं. राज्य में लॉ एंड आर्डर पहले से बेहतर है, दिनदहाड़े लूट नहीं होती और गुंडाराज भी नहीं है. लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग अब त्रस्त हैं. बिहार सरकार की योजनाओं का असर नहीं दिख रहा है. केंद्रीय योजनाओं में भी भ्रष्टाचार है. शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कोई और विभाग, हर विभाग में गड़बड़ियां चल रही हैं. बिहार में निवेश नहीं हो रहा है. उद्योग नहीं लग रहे. पावर सेक्टर की स्थिति दयनीय है. नीतीश कुमार के सात साल के शासनकाल में नक्सलियों का प्रभाव 10 ज़िलों से बढ़कर 23 ज़िलों तक पहुंच चुका है. बिहार सरकार के पास इस विपदा से निपटने की कोई योजना ही नहीं है. शहरों की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है. युवाओं के लिए न तो रोज़गार है और न ही भविष्य में कोई अवसर नज़र आ रहा है. लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बदहाली को ही बिहार के लोगों ने अपनी नियति मान ली है. इसके बावजूद बिहार के लोग आज भी नीतीश कुमार के शासनकाल को लालू यादव के शासनकाल से बेहतर मानते हैं. बिहार की जनता की उम्मीदों पर ख़रा उतरना नीतीश कुमार का दायित्व है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि वह इस दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं. सच तो यह है कि जिस ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, उससे यह उम्मीद ज़रूर जगी थी कि वह एक कामयाब और असाधारण मुख्यमंत्री साबित होंगे और आगे चलकर देश का नेतृत्व भी करेंगे. ऐसा बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोग चाहते हैं, लेकिन बिहार में इन दिनों जो हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार ने ख़ुद को एक साधारण मुख्यमंत्री के दायरे में सीमित कर लिया है. ऐसा लगता है कि उन्होंने पटना से दिल्ली का सफ़र मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बना लिया है. ■

manish@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

अमरदीप सिंह संयुक्त सचिव बनेंगे

1993 बैच के आईएएस अधिकारी अमरदीप सिंह भाटिया को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह अविनाश कुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे. उन्हें कृषि एवं सहकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

संदीप दवे भू-संसाधन विभाग गए

1987 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप दवे को भू-संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह सुरेंद्र कुमार की जगह लेंगे.

चिरावयुर विश्वनाथ अतिरिक्त सचिव बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी चिरावयुर विश्वनाथ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

संजीव नागपाल उप महानिदेशक बने

1993 बैच के आईटीएस अधिकारी संजीव नागपाल को यूनिक आइडेंटीफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) का उप महानिदेशक बनाया गया है. यह पद देविन्दर कुमार के जाने के बाद ख़ाली हुआ था.

दिप्तिविलास को अतिरिक्त प्रभार

1981 बैच के आईएएस अधिकारी देवेरकोंडा दिप्तिविलास, जो शहरी विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

मृणाल कांत निदेशक बने

1998 बैच केआईएएस अधिकारी मृणाल कांत त्रिपाठी को शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह वीना कुमारी मीणा की जगह लेंगे. उन्हें गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 51
दिल्ली, 25 फरवरी-03 मार्च 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
6452888
011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

वित्त मंत्रालय के द्वारा ख़र्चों को कम करने के लिए कसरत करना सही दिशा में उठाया गया एक क़दम हो सकता है.

इस बार का बजट लोकलुभावन नहीं होगा

देश की तरक्क़ी आम जनता को हाशिए पर रखकर नहीं हो सकेगी, इसलिए वित्त मंत्री चिदंबरम को आम लोगों को दो वक़्त का खाना मिले, यह सुनिश्चत करना ही होगा. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे इस बार का बजट लोकलुभावन बना पाएंगे? क्या वे देश में मौजूद कालेधन को मुख्यधारा में लाकर उसका उपयोग देश के विकास में कर पाने में सक्षम होंगे? क्या कहती है चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

सतीश सिंह
feedback@chauthiduniya.com

वैसे तो वित्त बजट अभी पेश होना बाक़ी है, लेकिन मोटे तौर पर बजट के स्वरूप का आकलन तो किया ही जा सकता है. यदि हम वित्त मंत्री पी चिदंबरम के हालिया बयानों पर ग़ौर करें, तो वित्त वर्ष 2013–14 के बजट में मौजूदा कर क़ानूनों को पारदर्शी बनाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर ज़ोर दिया जा सकता है. दरअसल, वोडाफोन से संबंधित 14000 करोड़ रुपये के कर विवाद में वित्त मंत्रालय की अच्छी–ख़ासी फ़ज़ीहत हो चुकी है. इसलिए अब मंत्रालय यही चाहता है कि कराधान के क़ानून को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो. दरअसल इसी वजह से प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को लागू करने में भी वह जल्दबाज़ी नहीं कर रहा है. वित्त मंत्रालय के नए सलाहकार पार्थसारथी शोम का मानना है कि कर में किसी को राहत नहीं दिया जाना चाहिए. उनका कहना है कि पिछली तारीख़ से ज़्यादा कर वसूलने से सरकार के ख़ज़ाने में और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है. जल्द ही सरकार इस मामले पर विमर्श करने वाली है. यह भी माना जा रहा है कि आगामी बजट में कर दर को बढ़ाया जा सकता है. अमीर लोगों पर थोड़ा और ज़्यादा कर आरोपित करने के प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है. चिदंबरम चाहते हैं कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत के दायरे में रहे और अगले वित्त वर्ष में इसे घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया जाए. सूत्रों के अनुसार, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट और स्पेक्ट्रम नीलामी की धीमी गति के बावजूद राजकोषीय घाटा को 5.3 प्रतिशत के स्तर पर रखने के लिए क़वायद की जा रही है.

सरकारी ख़ज़ाने को भरने के लिए वित्त मंत्रालय हर तरह की संभावना तलाश कर रहा है. ज्ञातव्य है कि स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में टेलीकॉम कंपनियां पहली क़िस्त के रूप में तक़रीबन 8000 करोड़ रुपये सरकार के ख़ज़ाने में जमा करने वाली हैं. इस मद में वोडाफोन को 2093 करोड़ रुपये, एयरटेल को 1758 करोड़ रुपये, भारत संचार निगम लिमिटेड को 1282.98 करोड़ रुपये, आइडिया सेल्युलर को 810 करोड़ रुपये, एयरसेल को 584 करोड़ रुपये, रिलायंस कम्युनिकेशन को 63 करोड़ रुपये, स्पाइस कम्युनिकेशन को 84.45 करोड़ रुपये, लूप मोबाइल को 607 करोड़ रुपये और एमटीएनएल को 916 करोड़ रुपये जमा करने हैं. सरकार फ़िलहाल टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित स्पेक्ट्रम शुल्क ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है, पर ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी ख़ज़ाने को भरने के लिए जल्द ही इस फ़ैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है. इसी क्रम में सरकार यह मानकर भी चल रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश से उसकी झोली में 30000 करोड़ रुपये आ सकते हैं. इस मामले में ऑयल इंडिया में विनिवेश किया जा चुका है. एनटीपीसी और नालको का विनिवेश फ़रवरी, 2013 में किए जाने की संभावना है और एमएमटीसी, सेल एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का विनिवेश मार्च, 2013 में किया जा सकता है. रेलवे एवं पोर्ट ट्रस्ट के पास मौजूद ज़मीनों को बेचकर राजकोषीय घाटे को कम करने के मुद्दे पर भी विचार–विमर्श किया जा रहा है. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के ख़र्च को कम करने के लिए भी मशक्क़त कर रहा है. अपने प्रस्ताव में मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ख़र्च को 24 प्रतिशत तक कम करने की बात कही है. कृषि मद में ख़र्च किए जाने वाले प्रस्तावित 20000 करोड़ रुपये में से 3000 करोड़ रुपये कम कर दिए गए हैं. रक्षा बजट के ख़र्च प्रस्ताव में से भी 10000 करोड़ रुपये कम किए गए हैं. राज्य सरकारों को बीजों के लिए सब्सिडी मुहैया कराने वाले बीज निगम को भी पहले की तरह पूरा आवंटन नहीं किया जाएगा. चिदंबरम ने सभी मंत्रियों को ताक़ीद करते हुए कहा है कि वे अपने ख़र्चों को कम करें. अदरअसल, ख़र्च कम करने के बाबत मंत्रियों से सुझाव भी मांगे गए हैं.

वित्त मंत्रालय के द्वारा ख़र्चों को कम करने के लिए कसरत करना सही दिशा में उठाया गया एक क़दम हो सकता है. इस संदर्भ में स्पेक्ट्रम की नीलामी या स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में वसूले धन को भी समीचीन माना जा सकता है, परंतु राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकारी संपत्ति को बेचना और आम ज़रूरत की चीज़ों पर लगातार सब्सिडी को कम करना देश और जनता के हित में नहीं है. कालेधन के मामले में सरकार का चुप रहना भी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा की जा रही कोशिशों को हास्यासप्रद इसलिए बनाता है, क्योंकि आज की तारीख़ में देश में मौजूद कालेधन की उगाही से राजकोषीय घाटे की समस्या से निजात पाई जा सकती है.

भले ही वर्ष 2014 में आम चुनाव होने वाले हैं, फिर भी आगामी बजट के लोक लुभावन होने की संभावना बहुत ही कम है. माना जा रहा है कि इस बजट में राजकोषीय घाटे को कम करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी. ईंधन के मद में दी जा रही सब्सिडी में की जा रही कटौती को जारी रखा जाएगा. रसोई गैस के मद में और राहत की गुंजाइश नहीं है.

ग़ौरतलब है कि काला धन हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है. ग़लत तरीक़े से अकूत धन जमा करके भ्रष्ट लोग समाज के शीर्ष पर पहुंच गए हैं और देश में काले धन से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है. एक अनुमान के मुताबिक़, भारत में काले धन की मात्रा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के क़रीब 30 प्रतिशत (अंदाज़न 26 लाख करोड़ रुपये) के आसपास है, जो कि वर्ष 1999 में 22.9 प्रतिशत और वर्ष, 2006 में 25.1 प्रतिशत था. उल्लेखनीय है कि अभी हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एनआईएफएम) और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाएड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) को देश में मौजूद काले धन का पता लगाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी. उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अभी वित्त मंत्रालय के पास रखी है, जिसे आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 1985 के बाद काले धन पर पेश की गई यह पहली सरकारी रिपोर्ट है. उसके पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के द्वारा वर्ष 2011 में पेश की गई एक रिपोर्ट में देश में 27.5 लाख करोड़ रुपये से 74 लाख करोड़ रुपये के बीच काला धन होने का अनुमान लगाया गया था. इसी विषय पर जारी अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका की थिंकटैंक ग्लोबल फाइनेंस इंटेग्रिटी (जीएफआई) ने पाया कि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 के बीच भारत के भ्रष्टाचारियों के द्वारा लगभग 6.76 लाख करोड़ रुपये का कालाधन विदेश भेजा गया. ग़ौरतलब है कि काले धन की अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति मूलत: सभी प्रकार की बाज़ार आधारित वस्तुओं और सेवाओं को ग़लत तरीक़े से उत्पादित करने, जानबूझकर आयकर सरकारी खाते में जमा नहीं करने, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, अन्यान्य कर वंचना, कामगारों को न्यूनतम वेतन देने, काम करने के अधिकतम घंटे, भविष्य निधि की चोरी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने आदि से होती है. इसके मद्देनज़र वित्त मंत्री बजट सत्र में कालेधन को सफ़ेद बनाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा कर सकते हैं. इस प्रस्तावित योजना के तहत 30 प्रतिशत टैक्स प्रभारित करके काले धन को सफ़ेद बनाने की इजाज़त सरकार के द्वारा भ्रष्ट लोगों को दी जा सकती है. ज़ाहिर है, इस योजना को व्यवहारिक बनाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा.

बीते सालों से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (सप्रंग) सरकार लोक लुभावन बजट से बचने की ज़रूरत पर बल दे रही है. उसका मानना है कि विविध मदों में दी जा रही सब्सिडी के कारण राजकोषीय घाटे में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. इसके आलोक में अब देखने की बात यह है कि सरकार के पास राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय कौन–कौन से हैं और इस क़वायद में किसे आसानी से बलि का बकरा बनाया जा सकता है? क़ायदे से राजस्व संग्रह के द्वारा सरकार को इस घाटे को कम करना चाहिए, लेकिन इस फ्रंट पर वह बेबस और लाचार ही दिखती है. ले–देकर वेतनभोगी कर्मचारी पर वह अपना चाबुक़ चला पाती है, लेकिन इस वर्ग से वसूल किया जाने वाला कर इतने बड़े देश को चलाने के लिए नाकाफ़ी है. छोटे–बड़े सभी कारोबारी कर वंचना में माहिर हैं. इस समस्या का दूसरा पहलू है देश में घोर भ्रष्टाचार का व्याप्त होना. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे इस देश में सब कुछ मैनेज हो जाता है. उसके बाद सरकार के पास दो ही विकल्प बचते हैं. पहला, या तो वह सरकारी संपत्ति को बेचे या फिर आम जनता को मुहैया की जाने वाली सब्सिडी को कम करे. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश करना सरकारी संपत्ति को बेचने का ही दूसरा नाम है. सब्सिडी के मामले में ध्यान देने की बात यह है कि कॉरपोरेट्स को भी भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, जिसका पता सामान्यत: अशिक्षित जनता को नहीं चल पाता है. आमतौर पर यह सब्सिडी आयात–निर्यात में संतुलन बनाए रखने का तर्क देकर, औद्योगिक इकाई शुरू करने की बात कहकर, स्पेशल इकनॉमिक जोन (सेज) के विकास को लेकर या फिर कॉरपोरेट्स को घाटे से उबारने के लिए उनके ऋण खातों को कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) में अंतरित करने के नाम पर दी जा रही है. इस बाबत यह बताना अहम है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, मसलन, डीजल, जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन फायदा अमीर तबके के लोग उठा रहे हैं. आर्थिक विकास के नाम पर कार उद्योग को सरकार की तरफ़ से विशेष सुविधा एवं रियायत दी जा रही है. डीजल कारों के अंतिम उपभोक्ता कौन हैं, यह जानते हुए भी डीजल कारों के निर्माण की इजाज़त कॉरपोरेट्स घरानों को देना सरकार की मंशा को जनविरोधी बनाता है. अस्तु डीजल के वितरण में राशनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अमीर वर्ग इसका लाभ न ले पाएं, पर क्या कॉरपोरेट्स या अमीर तबक़े को नाराज़ करने की हिम्मत सरकार में है? चूंकि आम जनता सभी के लिए हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है, इसलिए सरकार के आक्रमण का केंद्रबिंदु भी वही होता है और इसी तथ्य को ध्यान में रख करके आम ज़रूरत के सामानों पर दी जा रही सब्सिडी को सबसे पहले कम या समाप्त किया जा रहा है.

भले ही वर्ष 2014 में आम चुनाव होने वाले हैं, फिर भी आगामी बजट के लोक लुभावन होने की संभावना बहुत ही कम है. माना जा रहा है कि इस बजट में राजकोषीय घाटे को कम करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी. ईंधन के मद में दी जा रही सब्सिडी में की जा रही कटौती को जारी रखा जाएगा. रसोई गैस के मद में और राहत की गुंजाइश नहीं है. हो सकता है कि समावेशी विकास की सभी योजनाओं को फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए. हां, सामाजिक दायित्व के मुद्दे पर सरकार थोड़ी दरियादिली ज़रूर दिखा सकती है. उम्मीद है कि सरकार खाद्य सुरक्षा के मद में, नक़द सब्सिडी अंतरण और महिला केंद्रित योजनाओं पर बजटीय आवंटन दिल खोलकर करेगी. यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सप्रंग सरकार ऐसी उदारता चुनावी मजबूरी के तहत दिखा सकती है, क्योंकि वह जानती है कि इस मामले में कटौती की कैंची चलाने पर वर्ष 2014 के आम चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है.

भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश में आम जनता को हाशिए पर रख करके तरक्क़ी नहीं की जा सकती है. इस वस्तुस्थिति के मद्देनज़र सरकार को उनकी ज़रूरत को समझना होगा और उनको दो वक़्त का खाना मिलता रहे, इसे भी सुनिश्चित करना पड़ेगा. लिहाज़ा, सरकार को चाहिए कि वह देश में मौजूद काले धन को मुख्यधारा में लेकर आए, ताकि देश का पैसा देश के विकास में ख़र्च हो सके. इसके बरअक्स अमीरों को प्रदान की जाने वाली विविध प्रकार के आर्थिक लाभ में कटौती एवं काले धन को समाप्त करने के लिए कड़े फ़ैसले लेने से संबंधित प्रस्ताव को आगामी बजट सत्र में ज़रूर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी का भला हो सके. वैसे, ऐसा करने से ग़रीबों से अधिक फ़ायदा वर्ष 2014 के चुनाव में सप्रंग सरकार को मिलेगा. ■

एक और अहम बात यह है कि राज्यपाल ज़्यादातर बिहार से बाहर ही रहते हैं. वह ज़्यादातर दिल्ली या फिर अपने गृह प्रदेश असम के दौरे पर होते हैं.

बिहार

आसान नहीं वाम एकता की राह

महेश कुमार feedback@chauthiduniya.com

बिहार में एक बार फिर वाम एकता की ज़मीन तैयार करने की क़वायद तेज़ हो गई है, लेकिन अभी हालात काफ़ी मुश्किल हैं. इस बात का अहसास वाम नेताओं को भी है. दरअसल, राज्य में उनके सामने जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, इसे देखते हुए उनके सामने एक साथ आने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है. इसी के मद्देनज़र वाम एकता की नींव गत वर्ष पटना में हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के 21वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में डाली गई. भाकपा के किसी राष्ट्रीय महाधिवेशन में पहली बार भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव को खुले सत्र में आमंत्रित किया गया. इस मंच से भाकपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव एबी बर्धन, माकपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश करात, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव देवव्रत विश्वास ने वाम एकता की वकालत की. इसके बाद बिहार में नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ जो भी आंदोलन हुए, सभी में वाम दलों की संयुक्त भागीदारी हुई. हालांकि बिहार में वामदलों की एकता के इतिहास को यदि देखें, तो संघर्ष के नाम पर सभी वामपंथी पार्टियां एक मंच पर तो ज़रूर आती हैं, लेकिन चुनाव आते-आते कुछ सीटों को लेकर गठबंधन आख़िर टूट ही जाता है.

गत लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने मिलकर लड़ा, लेकिन फिर भी वाम दलों के बीच पूर्ण समझौता नहीं हो पाया. भाकपा-माकपा के बीच सभी सीटों पर समझौता हुआ. भाकपा-माकपा उम्मीदवारों को कई सीटों पर भाकपा माले के उम्मीदवारों से टकराव हुआ. अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाकपा और भाकपा माले के बीच एक-दो सीटों पर टकराव की संभावना व्यक्त की जा रही है. नौ नवंबर, 2012 को भाकपा माले ने नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ गांधी मैदान में परिवर्तन रैली आयोजित की. इस रैली में माले ने भाकपा और माकपा के राज्य सचिव को आमंत्रित किया. इसके बाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सवाल पर जनशक्ति परिसर में भाकपा, माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी द्वारा संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया गया था. इसमें भाकपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एबी बर्धन और माकपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश करात आए हुए थे. इस कन्वेंशन में भाकपा माले के राज्य सचिव को भी आंमत्रित किया गया. इसी कन्वेंशन में भाकपा-माकपा ने केंद्रीय मज़दूर संगठनों के आह्वान पर 20-21 फ़रवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में 48 घंटों के बिहार बंद की घोषणा की है. अब भाकपा माले भी इस बंद में शामिल हैं. इसकी तैयारी को लेकर तीन फ़रवरी को भाकपा, माकपा और भाकपा माले द्वारा पटना में राज्यस्तरीय संयुक्त जन कन्वेंशन आयोजित किया गया. इस कन्वेंशन में भी भाकपा में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एबी बर्धन, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और माकपा के राष्ट्रीय कमेटी सदस्य एवं पूर्व सांसद मो. सलीम ने वाम एकता की वकालत की, लेकिन बिहार में यह वाम एकता कितनी दूर जाएगी, यह तो वक़्त ही बताएगा. माना जा रहा है कि वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजद, लोजपा, भाकपा और माकपा के बीच गठजोड़ हो सकता है. इस गठजोड़ में भाकपा माले के शामिल होने की कम ही संभावना है. इसके अलावा, भाकपा और भाकपा माले के बीच जहानाबाद सीट को लेकर भी आपसी तक़रार हो सकता है. पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह की फिर से भाकपा में वापसी हो गई है. पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट पर सिंह को उतारना चाहेगी. भाकपा की राज्य कार्यकारिणी ने सिंह को जहानाबाद में तैयारी शुरू कर देने का निर्देश भी दिया है. इसी के आलोक में भाकपा से संबंध बिहार राज्य महिला समाज का राज्य सम्मेलन दो-तीन फ़रवरी को जहानाबाद में आयोजित किया गया. वहीं भाकपा माले किसी भी स्थिति में जहानाबाद सीट छोड़ना नहीं चाहेगी. ऐसी स्थिति में इस सीट को लेकर भाकपा और भाकपा माले आमने सामने होगी. बिहार में वामपंथी पार्टियों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. भाकपा के चंद्रशेखर सिंह ने बिहार विधानसभा में वर्ष 1956 में हुए तेघरा सीट के लिए उपचुनाव में जीत दर्ज कर प्रवेश किया था. इसके बाद बिहार विधानसभा में भाकपा की ताक़त लगातर बढ़ती गई, लेकिन वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर भाकपा 1956 वाली स्थिति में आ गई है. अगर चुनावी नतीजे पर नज़र डालें, तो वर्ष 2010 में हुए पंद्रहवीं बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश लहर के आगे वामदलों की एक नहीं चली थी. भूमि सुधार सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं को उठाने वाले वामदलों के नौ में से एक भी विधायक इस बार विधानसभा नहीं पहुंचे. सिर्फ़ भाकपा को बछवाड़ा में कामयाबी मिली थी. एक तरह से विधानसभा में वामपंथी पार्टियों की स्थिति प्रथम विधानसभा वाली हो गई है. वर्ष 1969 के बाद यह पहला मौक़ा है, जब कोई माकपाई विधानसभा नहीं पहुंच पाया है. भाकपा माले का विधानसभा में सूपड़ा साफ़ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में वामदलों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है. नीतीश लहर के बावजूद 11 विधानसभा में वामदलों के उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे थे और बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जीत मिली थी. तेघरा, विभुतिपुर, बलरामपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र में तीस हज़ार से अधिक वोट लाने के बाद भी वामदलों के उम्मीदवारों को जीत हासिल नहीं हो पाई. इसके साथ ही हरलाखी, धौरैया, काराकाट, अगिआंव गया शहर, और केसरिया, विधानसभा क्षेत्र में बीस हज़ार से अधिक वोट लाने में वाम दलों के उम्मीदवार सफल रहे. इनमें से हरलाखी केसरिया और गया शहर में भाकपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे. इस चुनाव में भाकपा को 4, 92, 815 माकपा को 2, 06, 601 और भाकपा माले को क़रीब 5.20 लाख वोट मिले थे. ऐसी स्थिति में बिहार में वामदलों की एकता लाज़मी हो गई. यह एकता कितनी दूरी तय करेगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वाम दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता फ़िलहाल वाम एकता की जमकर वकालत कर रहे हैं. ■

विवादों के घेरे में राज्यपाल देवानंद कुंवर

अशरफ़ अस्थानवी feedback@chauthiduniya.com

यूजीसी नियम के विरुद्ध नियुक्तियां करने के कारण राज्यपाल देवानंद से न केवल सत्तापक्ष, बल्कि विपक्ष भी नाराज़ है. राज्यपाल विवादों के घेरे में हैं. क्या है सच्चाई? एक रिपोर्ट...

राज्यपाल देवानंद कुंवर जब से बिहार आए हैं, तब से कई मामलों को लेकर राज्य सरकार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं. अभी ताज़ा विवाद राज्य के आठ विश्वविद्यालयें में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है. उन्होंने डॉ. शंभूनाथ सिंह को पटना विश्वविद्यालय, प्रो. अरुण कुमार को मगध विश्वविद्यालय, मो. शम्शुजोहा को मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, प्रो. विमल कुमार को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, प्रो. राम विनोद सिंह को बीएन मंडल विश्वविद्यालय, प्रो. शिवशंकर सिंह को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, कमलेश प्रसाद सिंह को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय तथा डॉ. अरविंद पांडेय को कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है. इन नियुक्तियों में 7 पुराने तथा 1 नया चेहरा है. इन नियुक्तियों में फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि इनमें से तीन कुलपतियों को उनके पुराने विश्वविद्यालयों में ही रखा गया है, जबकि चार कुलपतियों के विश्वविद्यालय बदल दिए गए हैं.

ग़ौरतलब बात यह है कि पटना उच्च न्यायालय ने कई अनियमितताओं के आरोपों के चलते पूर्व में नियुक्त किए गए, कई कुलपति एवं प्रतिकुलपति को हटाने का आदेश देते हुए कहा था कि नए कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर ही नियुक्त किए जाएं. अदालत के आदेश को देखते हुए एक लंबे समय बाद कुलाधिपति कार्यालय ने कुलपतियों की सूची राज्य सरकार के विमर्श के लिए भेजी. इस सूची को देखकर शिक्षा विभाग भी हैरान हो गया, क्योंकि इस सूची में उन्हीं पुराने नामों को शामिल किया गया था, जिन पर गंभीर आरोप होने के कारण अदालत ने उन्हें हटाया था. राज्य सरकार ने इसमें शामिल कई नामों पर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए उनके सामने उन पर लगे आरोपों के तथ्य भी जोड़कर राजभवन को भेज दिए, लेकिन राज्य सरकार की इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राजभवन ने अपनी ही सूची को फाइनल कर अधिसूचना जारी कर दी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को कुलपति नियुक्त किया गया है, उनमें कई के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और वे जांच के घेरे में हैं. इनमें विमल कुमार पर सबसे गंभीर पैसे लेकर शिक्षकों की पदोन्नति देने तथा पृष्टिसूची में हेराफेरी करने का आरोप है. इसकी जांच निगरानी में चल रही है. पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभूनाथ सिंह पर अगस्त 2011 से अक्टूबर 2012 के बीच गलत टीए और डीए लेने का आरोप है. उन पर आवास के रखरखाव मद में 16 लाख रुपये से अधिक ग़लत ढंग से ख़र्च करने तथा सुप्रीम कोर्ट में ग़लत ढंग से क़ानूनी मदद के एवज में लाखों रुपये का भुगतान करने का आरोप है. इसी तरह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए अरविंद पांडेय पर संस्कृत कॉलेजों में नियुक्ति में अनियमितता बरतने का आरोप है.

एक और अहम बात यह है कि राज्यपाल ज़्यादातर बिहार से बाहर ही रहते हैं. वह ज़्यादातर दिल्ली या फिर अपने गृह प्रदेश असम के दौरे पर होते हैं. ऐसे में, ज़रूरी सरकारी काम लटक जाते हैं. इससे पूर्व भी राज्यपाल पर कई आरोप लग चुके हैं. नीतीश सरकार के साथ उनके मतभेद दो विधेयकों पर उनके द्वारा सहमति दिए जाने में अड़ंगा लगाए जाने को लेकर शुरू हुए. राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक तथा शैक्षणिक स्थिति में ठोस सुधार करने तथा इसमें सरकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश बनाने के लिए सरकार ने पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक एवं बिहार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधान मंडल से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा, मगर ये दोनों विधेयक वहां जाकर लटक गए. राज्यपाल के अड़ियल रवैये के ख़िलाफ़ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने न सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ तीखी टिप्पणी की, बल्कि केंद्र सरकार से उनकी शिकायत करते हुए उन्हें वापस बुलाने तक की मांग भी कर दी. इधर, चर्चा यहां तक है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्यों का मामला भी वह पेंडिंग रखे हुए हैं. ये सभी सीटें अभी परिषद में ख़ाली पड़ी हैं. राज्यपाल के ख़िलाफ़ बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में भी विभिन्न सत्रों में सत्तापक्ष तथा विपक्ष के सदस्य नाराज़गी जताते रहे हैं.

बात उस समय और गंभीर हो गई, जब राज्यपाल की कार्यशैली के ख़िलाफ़ गंभीर टिप्पणी पटना उच्च न्यायालय तथा महालेखाकार द्वारा की गई. महालेखाकार की रिपोर्ट में कहा गया कि पटना विश्वविद्यालय सहित दूसरे विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के अनुसार नहीं की गई. साथ ही नियम के मुताबिक़, इन नियुक्तियों में सरकार की सहमति भी नहीं ली गई. रिपोर्ट में इस नियम को अनदेखी के तहत पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभूनाथ सिंह बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुज़फ्फ़रपुर के कुलपति डॉ. राजेंद्र मिश्रा, एमएमएच अरबी और फ़ारसी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस जोहा, जेपी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉ. राम विनोद सिन्हा, केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार पांडेय तथा बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति डॉ. अरुण कुमार के अलावा पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ जेपी सिंह, एमएमएचए विश्वविद्यालय पटना के प्रति कुलपति डॉ. एसके जबीं, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रति कुलपति डॉ. कुमारेश प्रसाद तथा बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के प्रतिकुलपति डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वर्मा की नियुक्ति को भी नियम विरुद्ध बताया गया है. रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि सर्च कमेटी का गठन किए बिना नियुक्ति करना यूजीसी नियम के विरुद्ध है. ■

महालेखाकार ने भी उठाए सवाल

महालेखाकार की रिपोर्ट में राजभवन में वित्तीय अनियमितता के भी कई मामले उजागर किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, राजभवन सचिवालय के वर्ष 2009-12 तक के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि नई दिल्ली स्थिति बिहार निवास में न तो राज्यपाल का कोई कार्यालय था और न वहां पोस्टिंग के लिए कोई कैडर ही था, पर पटना स्थित राजभवन में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में बताया गया कि उनकी प्रतिनियुक्ति दिल्ली के निवास में की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ग़लत पोस्टिंग पर 40.19 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया. महालेखाकार ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना बजट प्रावधान के इन कर्मचारियों को नई दिल्ली के रेट पर अतिरिक्त वेतन कैसे दिया गया? इनमें अनुबंध पर कार्यरत तीन कर्मचारियों के वेतन को भुगतान किस मद से किया जाता रहा है? रिपोर्ट में बिजली बिल के रीइम्बर्समेंट देने में भी गड़बड़ी पाई गई है. नियम के विपरीत राजभवन कैम्पस में रहने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया. महालेखाकार ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा विवेकाधीन फंड से लाभ देने में गड़बड़ी का ख़ुलासा भी किया है. राज्यपाल द्वारा 75 आवेदकों को इस फंड से लाभ दिया गया. इनमें 7 को एक-एक लाख रुपये दिए गए, जिनमें 5 आवेदक उनके गृह प्रदेश असम के ही थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संबंध में आवेदक की ओर से प्राप्ति रसीद नहीं दिया जाना संदेह उत्पन्न करता है. हैरत की बात यह है कि एक संस्था महिला इमदाद कमेटी को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई. इस संस्था की प्रमुख हैं राज्यपाल की पत्नी. महालेखाकार का कहना है कि यह उच्च पद का दुरुपयोग है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आपत्तियों पर राज्यपाल के सचिव का जवाब अस्पष्ट और उलझाने वाला मिला. ■

हादसे के बाद कुछ रिपोर्टों में आया था कि पुल पर आने और जाने का एक ही रास्ता था, यानी इसी पुल से यात्री न केवल आ रहे थे, बल्कि जा भी रहे थे.

कुंभ

व्यवस्था पर दाग़ लाशों पर राजनीति

अजय कुमार

इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली मौनी अमावस्या के स्नान को पहुंचे तीन दर्जन श्रद्धालुओं की मौत और क़रीब चालीस लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की ख़बर ने कुंभ के माथे पर दाग़ लगा दिया. व्यवस्था के सरकारी दावे खोखले साबित हो गए. यह एक कड़वा सच है कि हादसों को रोका नहीं जा सकता है. साथ ही एक सच यह भी है कि मौत चाहे जब भी और जिस भी रूप में आए, वह दुख का ही कारण होती है. दरअसल, यह दुख तब और बढ़ जाता है, जब किसी के ऊपर मौत का साया अपने परिवार और शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मंडराता है, जहां आपके आंसू पोंछने वाला अपना कोई भी नहीं होता है. अक्सर ऐसी मौतों की वजह सरकारी लापरवाही ही होती है. कुंभ में तीन दर्जन मौतों का कारण भी सरकारी मशीनरी की विफलता ही रही. हादसा मेला स्थल पर हुआ या फिर रेलवे स्टेशन पर, यह बात मायने नहीं रखती है. न ही किसी को इस बात से सरोकार है कि केंद्र या राज्य सरकार की लापरवाही हादसे की वजह बनी. जनता को हक़ीक़त पता है. यह सही है कि हादसा स्टेशन पर ही हुआ, लेकिन इस बात को भी कैसे नज़रंदाज़ किया जा सकता है कि इसकी वजह कुंभ में होने वाली वह उद्घोषणा नहीं थी, जिसमें लगातार भीड़ को मेला स्थल से रवाना करने के लिए दो–हराया जा रहा था कि स्टेशन पर ट्रेनें आपके इंतज़ार में खड़ी हैं. यह घोषणा सुनकर भीड़ स्टेशन की तरफ़ चल दी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई बड़ा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं था.

इसमें कोई दो राय नहीं कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर बने फुटओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ जाने के परिणामस्वरूप यह हादसा हुआ. सवाल यह उठता है कि विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ चल रहा है और महीनों पहले से तैयारियों का दावा किया जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में यह अव्यवस्था क्यों? क्या रेलवे प्रशासन को यह पहले से ज्ञात नहीं था कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने संगम पर पहुंचते हैं. इस बार इत्तेफ़ाक़ से मौनी अमावस्या रविवार को पड़ी, तो ऐसे में भीड़ की संख्या में कुछ ज़्यादा ही वृद्धि हो गई? दुख इस बात का भी है कि महाकुंभ में स्नान करके पुण्य कमाने में हमारे देश के नेता, मंत्री, नौकरशाह, पुलिस के अधिकारी भी सबसे आगे रहे. विडंबना तो यह है कि इन्हें यहां भी वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई गईं, लेकिन किसी का ध्यान आम जनता की परेशानियों की तरफ़ नहीं गया. रेल प्रशासन को आम दिनों की अपेक्षा ऐसे ख़ास आयोजन वाले दिनों में अतिरिक्त सुरक्षा बरतनी चाहिए थी. दुख की बात यह भी थी कि जिस समय रेल मंत्री का ध्यान कुंभ मेले में आने वालों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था पर होना चाहिए था, उस समय रेलमंत्री किराया बढ़ाकर और यात्रियों पर सरचार्ज लगाकर रेलवे का ख़ज़ाना भरने के लिए विचारमग्न थे.

हादसे के बाद कुछ रिपोर्टों में आया था कि पुल पर आने और जाने का एक ही रास्ता था, यानी इसी पुल से यात्री न केवल आ रहे थे, बल्कि जा भी रहे थे. ऐसी स्थिति में यह चूक बेहद आम थी. रेल प्रशासन को चाहिए था कि बैरीकेडिंग की व्यवस्था करके पुल और स्टेशन की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को स्टेशन के अंदर आने के लिए अनुमति देता. लापरवाही का इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है कि जिस पुल पर हादसा हुआ, उस पर अस्थाई डिवाइडर भी नहीं बनाया गया था. और अगर ऐसा हो जाता, तो कम से कम आने जाने–वाले लोगों की कतार अलग–अलग रहती. रेल प्रशासन की लापरवाही इसी से ज़ाहिर हो गई कि इलाहाबाद स्टेशन पर घटी इस घटना से क़रीब दो घंटे पहले ही कुंभ मेले के सेक्टर 12 क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भगदड़ में दो लोगों की मृत्यु की दुखद घटना से किसी ने भी कोई सबक़ नहीं लिया. इस दुर्घटना की सूचना के बाद निश्चित तौर पर रेल प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन अफ़सोस कि ऐसा नहीं हुआ. शर्म की बात यह भी है कि रेलमंत्री से लेकर रेल अधिकारी–कर्मचारी घटना के कारणों को लेकर न केवल पल्ला झाड़ते दिखे, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखे, लेकिन असलियत यही थी कि रेल प्रशासन की तैयारियां फुलप्रूफ नहीं थीं. ग़ौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पहली बार नहीं हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन इन घटनाओं से सबक़ नहीं लिया गया.

बहरहाल, महाकुंभ की बात छोड़ भी दी जाए, तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि रेल प्रशासन ऐन वक़्त पर स्टेशन पर पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के ठहरने वाले प्लेटफार्म की संख्या बदल देता है. ऐसी स्थिति में इस रेलगाड़ी विशेष से जाने वाले यात्री हड़बड़ी में उस प्लेटफार्म पर जाने को मजबूर हो जाते हैं. ज़ाहिर है प्लेटफार्म बदलने के लिए यात्रियों को पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर कहीं भूमिगत रास्ते का प्रावधान है, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में भागमभाग मचती ही है. कहा तो यहां तक जाता है कि ऐन वक़्त पर ट्रेन का प्लेटफार्म बदलने के पीछे कुछ साज़िशें छिपी होती हैं. प्लेटफार्मों पर उद्घोषणा करने के लिए जो उपकरण लगे होते हैं, उसमें एनाउंसर क्या बोल रहा है, न तो सुनाई देता है और न ही समझ में आता है. कई बार तो इसी चक्कर में लोगों की गाड़ियां तक छूट जाती हैं. ट्रेनों के आउटर पर खड़े रहने की समस्या से यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ता है. सीढ़ियों की मरम्मत पर किसी का ध्यान जाता नहीं है और बड़े से बड़े स्टेशनों पर भी एक नंबर प्लेटफार्म को छोड़कर अन्य प्लेटफार्म अपनी दुर्दशा पर आसूं बहाते रहते हैं. किराया बढ़ाने के साथ रेल प्रशासन को इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए. ऐसा लगता है कि जनता को सुविधा देने के लिए बने विभागों में कार्य करने वाले लोग केवल अपनी नौकरी करते हैं, सेवा नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस दर्द की कोई दवा नहीं...

इलाहाबद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अपने क़रीबियों को खोने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आस्था का महाकुंभ उन्हें ऐसी कड़वी यादें और दर्द दे जाएगा, जिसकी कोई दवा नहीं है. किसी ने भगदड़ में अपनी मां को, तो किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया. जिस मां ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भगदड़ में मज़बूती से उनका हाथ भी नहीं थाम सकने का मलाल उन्हें जीवन भर सालता रहेगा. जिस बेटी की किलकारी से सारा घर गूंज उठा था, आज उसकी चीख़ भी नहीं सुनाई दी. दिल्ली एयरपोर्ट पर सार्जेंट के पद पर तैनात पीके मिश्र अपनी मां जयंती मौनी को अमावस्या के मौक़े पर स्नान कराने लाए थे, लेकिन वह मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में हमेशा के लिए मौन हो गईं. संगम पर स्नान करने के बाद उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाने के लिए जो भी ट्रेन मिलेगी, उससे चले जाएंगे. लेकिन प्लेटफार्म नंबर 6 की भगदड़ में उनकी मां बिछड़ गईं. जैसे ही वह रेलमंत्री पवन कुमार बंसल से मिले, उनके सामने रोने लगे. उन्होंने कहा कि सर प्लीज, मेरी मां का भी पता लगवा दीजिए. वह कल रात मुझसे बिछड़ गई थीं, मैं उनके बिना घर नहीं लौट सकता. मैं भी यहीं मर जाऊंगा, सर प्लीज, कुछ करिए न. भगदड़ के दस मिनट बाद जब भीड़ नियंत्रित हुई, तो पीकेने अपनी मां की खोजबीन की. लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका.

उन्होंने बताया कि हादसे के बाद वह 45 लाशें देख चुके हैं, लेकिन उनकी मां का शव उन्हें नहीं मिल सका. हादसे का शिकार हुई कांताबाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उनकी पसलियां टूटकर चूर-चूर हो गई थीं. भगदड़ में न जाने कितने लोग उन्हें कुचलते हुए चले गए. शायद वह ठीक से चीख़ भी नहीं सकीं और उनकी जान चली गई. इस तरह महज़ आठ साल की मुस्कान के शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं. नाक और कान से अत्यधिक ख़ून बहने के कारण उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक़, उसके हर अंग पर चोट लगी थी. इतने बड़े हादसे के बाद एक बार फिर मानवता ताख़ पर रख दी गई, लोगों को अपनों के कफ़न के लिए भी एसआरएन अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में 12 सौ रुपये देने पड़े. मृतकों के परिवारजनों से ही कफ़न मंगवाया गया. पहले तो प्लेटफार्म पर लापरवाही से भगदड़ मची, उसके बाद अस्पताल में भी अव्यवस्था. मृतकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था. निजी एंबुलेंस वाले मृतकों के परिजनों से हज़ारों रुपये की मांग कर रहे थे. भगदड़ में पत्नी, भाई, बहन की जानें चली गईं, उनका सामान खो गया, ऐसे में लोगों के पास पैसा कहां से आए. इसका ख्याल किसी को नहीं था. ■

आंखों देखी, कानों सुनी

बांदा निवासिनी घायल लक्ष्मी देवी के नाती अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि वह अपनी नानी के साथ प्लेटफार्म नंबर चार पर घर जाने के लिए ट्रेन पर सवार होने के लिए मौजूद थे. अचानक लाउडस्पीकर से आवाज़ आई कि बांदा की तरफ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर छह पर आएगी. यह सुनते ही प्लेटफार्म नंबर चार पर मौजूद लोग प्लेटफार्म छह की तरफ़ भागे. इसी बीच अचानक ओवर ब्रिज पर भगदड़ मच गई. लोग एक दूसरे पर गिरने लगे. कई लोग ओवर ब्रिज की रेलिंग टूटने से सीधे नीचे आ गए. कटनी बड़गांव निवासी ज्योति के चाचा पूरन ने बताया कि ट्रेन पर सवार होने के लिए वह परिजनों एवं गांव के लोगों के साथ प्लेटफार्म नंबर छह पर ओवरब्रिज से भाग रहे थे. पुलिसकर्मी भीड़ को रोक रहे थे और जब भीड़ नहीं रुकी, तो पुलिसकर्मियों ने लाठी चला दी, जिससे भगदड़ मच गई. वह तो बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी भतीजी ज्योति एवं भाभी सकुन बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं. सोनीपत निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने ऐसा हादसा कभी नहीं देखा. प्लेटफार्म अचानक बदलने के कारण भीड़ जब दौड़ी, तो पुलिसकर्मियों ने लाठी चला दी, जिससे भगदड़ गची और हादसा हुआ. फ़तेहपुर निवासी प्रकाश तिवारी की पत्नी लक्ष्मी घायल हुई थीं. प्रकाश ने बताया कि ओवरब्रिज पर अचानक आगे जा रही भीड़ भागी, तो भगदड़ मच गई. उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया. उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी. सतना के बेटा लाल का कहना है कि ओवरब्रिज पर वह अपनी पत्नी बिट्टन एवं गांव के अन्य लोगों के साथ थे, तभी अचानक भगदड़ मची. ■

पहले ही मिल गई थी बदइंतज़ामी की आहट

मौनी अमावस्या पर कुंभ में स्नान के लिए जाने वाली भीड़ ने शनिवार रात (9 फ़रवरी) से लेकर रविवार शाम (10 फ़रवरी) तक कई जगहों पर हंगामा किया. चार घंटे तक अटरामपुर स्टेशन पर प्रयाग पैसेंजर खड़ी रहने से नाराज़ लोगों ने ड्राइवर को अग़वा कर लिया. हरिद्वार से कुंभ के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पर रायबरेली में डंडों एवं लोहे की राड से कई डिब्बों की खिड़कियां तोड़ डालीं. भीड़ ने ऊंचाहार एक्सप्रेस के ड्राइवर को पथराव के बाद इंजन में ही बंधक बना लिया. ट्रेनों को बीच रास्ते में घंटों रोके जाने से नाराज़ लोगों ने फाफामऊ प्रतापगढ़, किवेत एवं फरवई जैसे कई स्टेशनों के कर्मचारियों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया. अटरामपुर में जब बरेली प्रयाग पैसेंजर चार घंटे तक खड़ी रही, तो नाराज़ यात्री ड्राइवर को इंजन से उतारकर अपने साथ लेकर चले गए. प्रयाग फ़ैज़ाबाद पैसेंजर के ड्राइवर से फरवई स्टेशन पर लोगों ने मारपीट की थी. ■

पहले भी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं

1954 में इलाहाबाद महाकुंभ में मची भगदड़ में क़रीब आठ सौ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था.

उत्तर प्रदेश में मथुरा ज़िले के राधा रानी मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठी हो जोने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इसमें एक महिला की मौत हृदयाघात और दूसरी की सीढ़ियों से गिर जाने से हुई. हज़ारों श्रद्धालु राधा अष्टमी पर वहां एकत्र थे.

नवंबर 2011 में हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी के तट पर हज़ारों श्रद्धालुओं के एकत्र होने के दौरान मची भगदड़ में 16 लोगों की जान चली गई थी.

4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृपालुजी महाराज आश्रम में प्रसाद वितरण के दैरान 63 लोग मारे गए थे, जबकि 15 घायल हो गए थे.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सवाल है कि जब इतने सारे साक्ष्य सोनू झा के पक्ष में जाते हैं, तब भी उसे गिरफ्तार क्यों किया गया?

जेल में बंद सोनू झा

आख़िर इस लड़के का गुनाह क्या है?

यह बिहार है. यहां सुशासन है. क़ानून का राज है. पुलिस क़ानून का शासन स्थापित करवाती है और क़ानून सबूत मांगता है और सबूत के आधार पर ही फ़ैसले होते हैं, लेकिन जब पुलिस ही सबूत की अनदेखी कर दे, तब क्या होगा? तब फ़ैसला कैसे होगा? तब न्याय कहां मिल पाएगा? मधुबनी के अरेड़ गांव के सोनू झा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. सोनू झा जेल में बंद है, उस गुनाह के लिए, जो उसने किया ही नहीं. कम से कम उपलब्ध सबूत प्रथम दृष्टा तो यही कहते हैं. चौथी दुनिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट :

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

सोनू झा की कहानी को समझने के लिए पहले बिहार के मधुबनी कांड को जानना ज़रूरी है. मधुबनी ज़िले के अरेड़ गांव के राजीव कुमार झा का बेटा प्रशांत झा एक दिन घर से ग़ायब हो गया. पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. कुछ ही दिन बाद एक सिरकटी लाश मिली. प्रशांत के परिवार के मुताबिक़, यह लाश प्रशांत की थी. इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और 12 अक्टूबर, 2012 को मधुबनी ज़िला मुख्यालय में जमकर बवाल मचा. थाना, कलेक्टेरिएट में आगज़नी हुई, पथराव हुआ और पुलिस ने फायरिंग की, तो गोलीबारी में कुछ लोग मारे गए. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया, जब प्रशांत एक लड़की के साथ दिल्ली के महरौली में पाया गया, यानी वह सिरकटी लाश किसी और की थी. बहरहाल, प्रशांत और उस लड़की को पुलिस कस्टडी में बिहार लाया गया. अभी प्रशांत रिमांड होम में है और लड़की अपने घर.

इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है, जिसका संबंध अरेड़ गांव के सत्रह साल के लड़के सोनू झा से है. मधुबनी में 12 अक्टूबर को भड़की आग, तोड़फोड़ एवं आगज़नी के मामले में पुलिस ने सैकड़ों अज्ञात एवं कुछ नामज़द लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की. ग़ौरतलब है कि इस उपद्रव की घटना में सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचा था, सरकारी दस्तावेज़ जलाए गए थे. इसके बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ. पहले 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद 25 अक्टूबर, 2012 को अरेड़ गांव में रात में पुलिस पहुंची और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार होने वालों में सत्रह साल के सोनू झा का नाम भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक़, उसे 12 अक्टूबर को हुए पथराव एवं आगज़नी की घटना में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया. अभी सोनू झा जेल में बंद है. सोनू झा के साथ उसके पिता घनश्याम झा और एक भाई मोनू झा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घनश्याम झा पान की एक दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन-यापन करते हैं.

बिहार - मधुबनी कांड

बहरहाल, चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए सोनू झा के एक संबंधी संतोष कुमार झा (सोनू झा के जीजा) बताते हैं कि सोनू झा को जिस आगज़नी की घटना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, यह ग़लत है, क्योंकि असल में सोनू उस दिन शहर में था ही नहीं. वह बताते हैं कि सोनू झा निर्दोष है और वह 10 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच शहर ही क्या, बिहार से भी बाहर था. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ के मुताबिक़, सोनू झा 13 अक्टूबर को एक परीक्षा के लिए जालंधर में उपस्थित था. सोनू को इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) की शारीरिक परीक्षा के लिए बुलावा भेजा गया था. दस अक्टूबर को सोनू झा ने शहीद एक्सप्रेस से इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस की परीक्षा देने के लिए मधुबनी से ट्रेन पकड़ी. उसके ट्रेन टिकट का पीएनआर नंबर है 660-6879001, टिकट संख्या है 66844694, कोच संख्या एस-5 और सीट नंबर है 36. सोनू झा 13 अक्टूबर को इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल भी हुआ, लेकिन वह शारीरिक परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी लंबाई की अहर्ता को पूरी नहीं कर पाया. इस वजह से उसका चयन नहीं हो पाया. इस संबंध में आईटीबीपी जालंधर के कमांडेंट विजय कुमार देसवाल ने अपना हस्ताक्षरयुक्त एक रिजेक्शन स्लिप (पर्ची) भी जारी की, जिसमें चयन न होने का कारण भी बताया गया है. इस पर्ची पर साफ़-साफ़ 13 अक्टूबर की तारीख़, जगह का नाम यानी जालंधर, चयन न होने के कारण और कमांडेंट एवं ख़ुद सोनू झा के हस्ताक्षर हैं, यानी कुल मिलाकर रिजेक्शन स्लिप यह साबित करने में सक्षम है कि 13 अक्टूबर, 2012 को सोनू झा जालंधर में आईटीबीपी की परीक्षा देने के लिए मौजूद था. इसके अलावा, सोनू झा के जीजा संतोष झा बताते हैं कि जालंधर जाते वक़्त सोनू अपने साथ एक मोबाइल (नंबर-9534952425) भी ले गया था. उनका कहना है कि यदि 10 से 15 अक्टूबर 2012 के बीच की कॉल डिटेल निकलवाई जाए, तो उससे भी पता चल जाएगा कि सोनू झा इन पांच दिनों के बीच बिहार से बाहर रहा है. इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि मधुबनी से जालंधर एवं जालंधर से मधुबनी आने-जाने का समय एवं तारीख़ क्या थी.

सवाल है कि जब इतने सारे साक्ष्य सोनू झा के पक्ष में जाते हैं, तब भी उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? और यदि गिरफ्तारी हो भी गई, तो उसे जेल भेजने से पहले पुलिस ने इन साक्ष्यों पर ग़ौर क्यों नहीं किया. इस संबंध में सोनू के जीजा संतोष झा बताते हैं कि वह इन साक्ष्यों के साथ पुलिस से भी मिले. एसपी से भी मिले, इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक, राज्य एवं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कहीं से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और न ही कोई आश्वासन मिला. वह बताते हैं कि पुलिस वाले आईटीबीपी की रिजेक्शन स्लिप को साक्ष्य नहीं मान रहे हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसा स्लिप तो कोई भी बनवा सकता है. आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस ने ट्रेन टिकट एवं मोबाइल कॉल डिटेल को भी साक्ष्य मानने से इंकार कर दिया.

बहरहाल, सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्रालय के तहत आने वाले आईटीबीपी के दस्तावेज़ को भी सबूत नहीं माना जा सकता है? संतोष झा बताते हैं कि वह इस मामले में आईटीबीपी के कमांडेंट विजय कुमार देसवाल से भी मिले हैं और उन्होंने एक पत्र लिखकर मुझे दिया है. पत्र में यह लिखा हुआ है कि सोनू कुमार झा 13 तारीख़ को जालंधर में आईटीबीपी की परीक्षा के लिए मौजूद था. ज़ाहिर है, आईटीबीपी के एक कमांडेंट का लिखा पत्र, जो सोनू झा की बेगुनाही का शायद सबसे बड़ा दस्तावेज़ होगा, अदालत में मान्य हो सकता है, लेकिन आईटीबीपी की रिजेक्शन स्लिप को पुलिस ने सबूत मानने से इंकार कर दिया. नतीजतन, सत्रह साल का एक लड़का पिछले चार महीनों से जेल में उस गुनाह के लिए बंद है, जो उसने किया ही नहीं. इस पूरे मामले में एक सवाल राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है. यह सही है कि किसी भी तरह की हिंसा को जायज़ नहीं माना जा सकता, क्योंकि मधुबनी कांड में जो कुछ भी हुआ, वह ग़लत था. आगज़नी की घटना, पथराव, सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाना, ये सब ग़लत था, लेकिन क्या एक निर्दोष को गिरफ्तार करना सही था? क्या पुलिस प्रशासन द्वारा सबूतों की अनदेखी करना सही था? ■

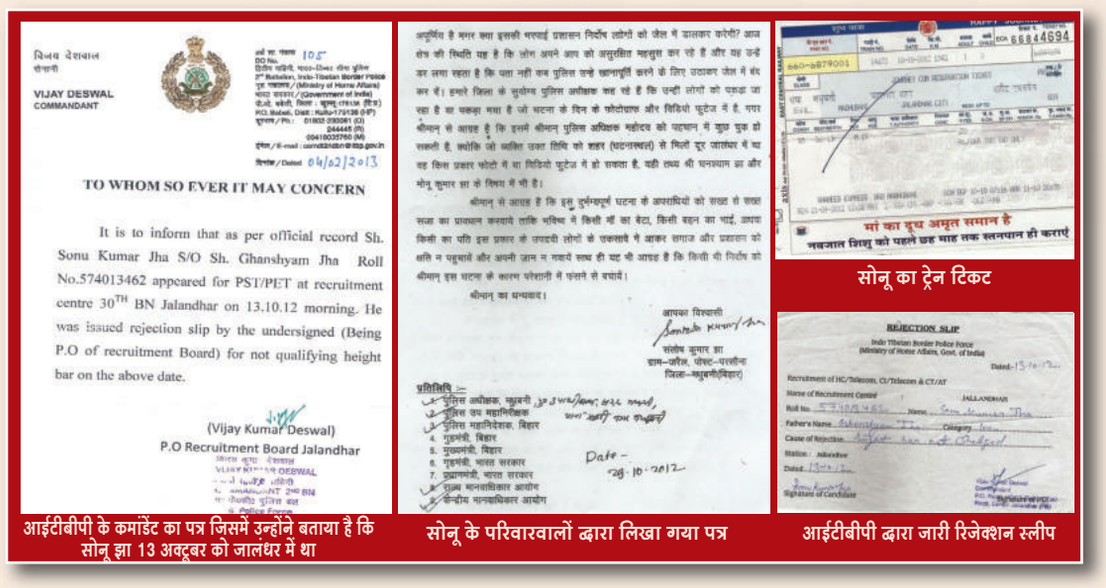

आईटीबीपी के कमांडेंट का पत्र जिसमें उन्होंने बताया है कि सोनू झा 13 अक्टूबर को जालंधर में था

सोनू के परिवारवालों द्वारा लिखा गया पत्र

सोनू का ट्रेन टिकट

आईटीबीपी द्वारा जारी रिजेक्शन स्लिप

आईटीबीपी जालंधर के कमांडेंट विजय कुमार देसवाल ने अपना हस्ताक्षरयुक्त एक रिजेक्शन स्लिप (पर्ची) भी जारी की, जिसमें चयन न होने का कारण भी बताया गया है. इस पर्ची पर साफ़-साफ़ 13 अक्टूबर की तारीख़, जगह का नाम यानी जालंधर, चयन न होने के कारण और कमांडेंट एवं ख़ुद सोनू झा के हस्ताक्षर हैं, यानी कुल मिलाकर रिजेक्शन स्लिप यह साबित करने में सक्षम है कि 13 अक्टूबर, 2012 को सोनू झा जालंधर में आईटीबीपी की परीक्षा देने के लिए मौजूद था.

मेरी दुनिया.... नीतीश की ग़लतफहमी

18वाँ शेखावाटी उत्सव 2013
Morarka Organic

शेखावाटी उत्सव 2013

मिट्टी की महक...

इंद्रधनुष में तो सात रंग होते हैं, लेकिन राजस्थान की कला संस्कृति में न जाने कितने रंग छिपे हैं. उनमें से फीके पड़ते कुछ रंगों को शेखावाटी उत्सव पिछले 18 साल से सहेजने में जुटा है. 18 वें शेखावाटी उत्सव में एक बार फिर शेखावाटी खान-पान, गीत, नृत्य और खेलों की झलक दिखाई दी. यह समारोह अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़े रहने का एक बहाना है. यहां की मिट्टी की महक अनायास ही सबको अपनी ओर खींच लाती है. फोटो जर्नलिस्ट प्रभात पांडेय की नज़र से शेखावाटी उत्सव की एक झलक...

ग्रामीण भारत की अवस्था के बारे में पिछले सौ सालों में काफी संशोधन हुए हैं और साहित्य प्रकाशित हुआ है.

क्या अगर ये भारतीय संगीत गातीं या बजातीं, तो सब कुछ अच्छा होता. ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरह लड़कियों को रोका ही जाता.

यूपीए के लिए बुरा वक़्त जारी है

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका
feedback@chauthiduniya.com

यूपीए 2 के लिए बुरा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है. पहले सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन फली नरीमन ने इस्तीफ़ा दिया. इस्तीफ़ा इसलिए, क्योंकि क़ानून मंत्री के साथ उनके किसी मुद्दे पर मतभेद थे. सत्ता के गलियारों में यह चर्चा थी कि उनके विचारों में मतभेद का कारण कॉरपोरेट हाउस से संबंधित था. ज़ाहिर तौर पर क़ानून मंत्रालय एक ख़ास तरह का विचार उनसे चाहता था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल होने के नाते रोहिंटन फली नरीमन ने अपने विचार को बदलने से मना कर दिया. ज़ाहिर है कि यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था. सच तो यह है कि अगर अच्छे लोग सरकार से बाहर निकलते हैं, तो यह केवल सरकार के लिए क्षति नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के लिए भी नुक़सानदेह है.

दूसरी बात, राष्ट्रपति ने लंबे समय से अफ़जल गुरु की लंबित दया याचिका पर फ़ैसला लेते हुए याचिका ख़ारिज कर दी. दरअसल, यह ठीक ज़रूर है, लेकिन उसके बाद साधारण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए था. परिवार वालों को समय रहते सूचित किया जाना चाहिए था. अगर परिवार वालों को सही समय पर सूचना दी गई होती, तो उसके बाद अफ़जल का परिवार सुप्रीम कोर्ट जा सकता था. कई मामलों में लोग दया याचिका ख़ारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. देश का क़ानून इसकी इज़ाज़त देता है.

आख़िर उसे फांसी पर लटकाने की इतनी जल्दी क्या थी कि उसका परिवार अदालत भी नहीं जा सका. इससे भी बुरा यह हुआ कि परिवार वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया, यह बर्बर और अमानवीय है. यह भारतीय परंपरा नहीं है. संविधान को एक तरफ रख दें, तो हज़ारों सालों की भारतीय परंपरा भी इस बात की इज़ाज़त नहीं देता है. आज़ाद भारत में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी. असल में यह एक ऐसा मामला था, जिसमें राष्ट्रपति उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अफ़जल के ख़िलाफ़ प्रत्यक्ष सबूत नहीं थे. ख़ैर, यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, लेकिन साधारण प्रक्रिया का पालन नहीं होना, अफ़जल के परिजनों को उससे नहीं मिलने देना और गृह मंत्रालय का यह कहना कि हम आगे की अदालती कार्यवाही से बचना चाहते थे, ग़लत है. यह सब कुछ सरकार के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता.

किसी एयरचीफ या किसी नौकरशाह को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन सही जवाब तो राजनीतिक नेतृत्व को ही देना है. सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जब 11 महीने पहले यह घोटाला सामने आया था, तभी जांच के आदेश दे दिए गए होते, तो और बेहतर होता.

तीसरी बात, अचानक हेलिकॉप्टर घोटाले का सामने आना. इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कब नियम और प्रक्रियाएं बदली गईं. सच यह है कि यूपीए सरकार के समय ऑर्डर दिए गए. इस बार भी मसला यह नहीं है कि आयात किया जा रहा सामान ठीक है या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि इस डील में रिश्वत दी गई और यह रक़म बहुत बड़ी है. बोफोर्स से जुड़ी रक़म आज भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन उस वक्त के लिए यह बहुत बड़ी रक़म थी और आज हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़ी रिश्वत की रक़म बहुत बड़ी है. आज भारत में कोई भी यह समझ सकता है कि इतनी बड़ी रक़म की रिश्वतख़ोरी ऊंचे स्तर की राजनीतिक तंत्र के शामिल हुए बिना बिल्कुल नहीं हो सकती. इसलिए किसी एयरचीफ या किसी नौकरशाह को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन सही जवाब तो राजनीतिक नेतृत्व को ही देना है. सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जब 11 महीने पहले यह घोटाला सामने आया था, तभी जांच के आदेश दे दिए गए होते, तो और बेहतर होता. इस तरह की स्थितियां ज़ाहिर तौर पर सरकार के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती. इसलिए जितनी जल्दी वे चुनाव करवा लें, उतना ही अच्छा होगा. ■

गांवों की पुरातन व्यवस्था

ठाकुरदास बंग
feedback@chauthiduniya.com

गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत का वर्ष भर दौरा किया. भारत के ग्रामीणों की दुर्दशा देखी. उनके मुंह से वेदनापूर्ण उद्गार निकले, हमारे गांव पैमाल (तुच्छ) हो गए हैं, क्योंकि हम सच्चा अर्थशास्त्र एवं सच्चा समाजशास्त्र जानते नहीं है. बापू का यह कथन बीसवीं सदी के दूसरे दशक के गांवों को जितना लागू था, उससे कहीं अधिक स्वराज्य के 34 बरस बाद आज अपने देश के गांवों को लागू होता है. तो सहज ही सवाल उठता है कि 18वीं और 19वीं सदी के भारत के गांवों की यानी अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत के गांवों की क्या स्थिति थी?

ग्रामीण भारत की अवस्था के बारे में पिछले सौ सालों में काफी संशोधन हुए हैं और साहित्य प्रकाशित हुआ है. इनके अध्ययन से और बहुत बूढ़े लोगों से बातचीत करने से पता चलता है कि उस समय भारत के गांव काफी हद तक स्व-शासित थे और गांवों का जीवन उन्नत था. हम लोगों में से कई, खासकर कई शिक्षित लोग ऐसा समझते हैं कि भारत अंग्रेजों के आगमन के पहले अंधकार में था और पश्चिमी ज्ञान के कारण प्रकाश की किरण अंग्रेजों के साथ में यहां आई. भारत में राजा या नवाब निरंकुश शासन करते थे, यहां तानाशाही थी और पश्चिम के आगमन के कारण यहां उदारमतवाद आया, लोकतंत्र की कल्पना आई और नागरिक अधिकार की बातें चलने लगीं, ऐसा लोग सोचते हैं. यह ख्याल काफी हद तक ग़लत है कि ऐसा कहा जा सकता है. तो फिर भारत की शासन पद्धति क्या थी? पर चूंकि भारत ग्राम प्रधान देश था और आज भी है, इसलिए भारत के गांवों के शासन का स्वरूप क्या था?

न केवल 17वीं, 18वीं सदी में, शुरू से ही भारत में शासन की इकाई गांव थे. संस्कृति के केंद्र भी गांव ही थे. भारत के राष्ट्रीय जीवन में नगरों का स्थान गौण था. वेद मंत्रों में गांव के कल्याण की प्रार्थना कई जगह की गई है, लेकिन नगरों के कल्याण के बारे में शायद ही कोई वेद मंत्र हो. वेदों में ग्रामीणी शब्द आया है, जिसका अर्थ सरपंच या गांव का नेता होता है. बुद्धकालीन जातक कथाओं में राज्य की उन्नति का वर्णन करते समय उन्नत गांवों की विशाल संख्या का अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है, लेकिन जातक कथाओं में नगरों का कोई उल्लेख नहीं है. मौर्य वंश का इतिहास हो या गुप्त वंश का, सर्वदा भारत के जनजीवन में गांवों का ही प्राधान्य रहा.

गांव के सभी निवासी गांव की विधानसभा के यानी ग्रामसभा के सदस्य थे. नालंदा में इन ग्रामसभाओं की या ग्राम-जनपदों की विविध मोहरें मिली हैं, जिन्हें लगाकर ग्रामसभाओं ने नालंदा विद्यापीठ को पत्र भेजे थे. तमिलनाडु के चिंगलपुट ज़िले के उत्तरमेरूर (जिसका नाम अपभ्रंश होकर अब उत्तरमल्लूर हो गया है) गांव के ग्रामसभा के कार्यकलापों का तफसीलवार वर्णन वहां के शिलालेख में मिला है. इस शिलालेख के अनुसार ग्रामसभा अपना काम पांच समितियों द्वारा करती थी. समिति के सब सदस्य नि:शुल्क काम करते थे और उनका कार्यकाल एक बरस का होता था. ग़लत व्यवहार के लिए उन्हें कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता था. सभी ग्राम निवासियों को शासन का अनुभव हो, इसलिए ग्रामसभा का एक नियम यह था कि एक बार उप-समिति पर नियुक्ति हो जाने के बाद तीन साल तक उसकी नियुक्ति फिर से हो नहीं सकती थी. सरकारी कर्मचारी इन उप-समितियों के सदस्य नहीं हो सकते थे. हर ग्रामसभा अपना संविधान स्वयं ही बनाती थी. उप-समितियों के सदस्य गोटियां डालकर चुने जाते थे. कहीं-कहीं सभी लोगों के नाम अलग-अलग टिकटों पर या विभिन्न रंगों की तूलिकाओं पर लिखे जाते थे और इनमें से एक टिकट या तूलिका को उठाने को किसी मासूम बच्चे को बुलाया जाता था. इसलिए इस पद्धति में दलीय राजनीति या मत प्रचार को कोई स्थान नहीं था.

कृषि, बागवानी, ग्राम की सिंचाई का प्रबंध, विवादों का निपटारा, स्वर्ण तौलना और उसकी शुद्धता को प्रमाणित करना इत्यादि भिन्न कामों के लिए विभिन्न समितियां रहती थीं. गुप्तकाल में इन समितियों के कई सदस्य ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों के भी पाए गए हैं. मराठाकाल में कई ग्राम पंचायतों में ग्राम-अदालतों के निर्णयों पर न्यायाधीशों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से कई ब्राह्मणेतर थे और कुछ हरिजन भी थे. ये ग्रामसभाएं क़र्ज़ लेना, बैंकिंग, शिक्षा, आरोग्य, रास्ते आदि का प्रबंध, मंदिरों की व्यवस्था, अकाल में सबका भरण-पोषण, गांव की सुरक्षा, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप, धार्मिक समारोह मनाना, सफाई, केंद्रीय सरकार की कर वसूली आदि कई काम करती थीं. केंद्रीय सरकार इन ग्रामसभाओं की कार्यवाहियों पर सामान्य देखभाल करती थी और अभिक्रम का दायित्व ग्रामसभा का रहता था. ग्रामसभाओं का यह उन्नत शासन अंग्रेजी साम्राज्य के आगमन तक था. प्रसिद्ध इतिहासकार सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने लिखा है, भारत पर अनेक विजेताओं ने बाहर से आकर हमले किए हैं और भारत को जीता है, लेकिन जैसे कुछ घास या बांस ज़मीन में गड़ा रहता है, वैसे ही भारत की ग्रामसभाएं हैं. बर्डवुड ने लिखा है, भारत पर पर्वतों के खुश्की मार्ग से सिथियन, ग्रीक, हूण, अफगान एवं मोगलों के हमले हुए और समुद्री मार्ग से पुर्तगाली, डच एवं फ्रेंच आए और अपना राज्य जमाया, लेकिन भारत की ग्राम-व्यवस्था पर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ. सन् 1930 के प्रसिद्ध नोट में भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, भारत के गांव छोटे-छोटे गणतंत्र हैं, जिनके भीतर निवासियों को लगने वाली सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती थीं. दुनिया की सब चीजें नाशवान हैं, लेकिन भारत का यह ग्राम-समाज स्थायी है. राजवंश आए और गए, एक के बाद एक क्रांतियां हुईं, लेकिन ग्राम-समाज पर उसका कोई असर नहीं हुआ. भारतीयों के स्थायित्व के लिए सबसे बड़ा कारण ये ग्राम-समुदाय हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि इन ग्राम-समुदायों को विचलित न किया जाए और इनमें हस्तक्षेप करने वाली किसी भी शक्ति से मैं घबराता हूं.

इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का पुराना गणराज्य या ग्राम- शासन आदर्श था. जात-पांत, ऊंच-नीच, अस्पृश्यता, पुरुषों के साथ महिलाओं की ग़ैर-बराबरी आदि कई दोष उनमें मौजूद थे. इनको हमें हटाना होगा. पश्चिम से आई हुई तफसील की बातें हमें आज के ग्रामीण जीवन में लानी होंगी. पुराने गणराज्यों के अस्तित्व का इतना ही अर्थ है कि भारत में स्व-शासन की प्राचीन परंपरा अनादिकाल से रही है और यह यहां के ख़ून में समाई हुई व्यवस्था है. धर्मपाल ने बताया कि 17वीं, 18वीं सदी में अंग्रेजों के आगमन के समय गांव बहुत मज़बूत थे और राजा की अन्यान्य इच्छा के विरुद्ध असहयोग एवं बहिष्कार आदि शस्त्रों का ग्राम- समाज उपयोग कर केंद्रीय सत्ता को झुकाता था और लोगों की इच्छा के सामने झुकने में राजा भी अपनी हेठी नहीं समझता था, बल्कि गौरव अनुभव करता था. धरमपाल ने बनारस के राज्य का 19वीं सदी का एक प्रसंग देकर एवं कई अन्य उदाहरणों से यह बात सप्रमाण सिद्ध की है.

लेकिन दस हज़ार किलोमीटर दूर से भारत आए हुए इन अंग्रेज विदेशियों ने सदियों से चलने वाली ग्राम-व्यवस्था को आख़िर तोड़ ही डाला. ज़मीन की व्यवस्था, वन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कृषि एवं उद्योगों में हस्तक्षेप और अपनी सर्वग्रासी कर नीति के द्वारा समूची ग्राम-व्यवस्था को अंग्रेजी शासकों ने तहस-नहस कर डाला. बदले में इन गांवों पर ज़बरदस्ती कलकत्ता से चलने वाला केंद्रीय शासन थोप दिया गया. उससे ग्रामीणों की प्रतिभा का उपयोग उनके स्व-शासन में होना बंद हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण होने से स्वावलंबन टूटा, स्वाश्रयी व्यवस्था खंड-खंड हो गई और सारी ग्रामीण जनता परमुखापेक्षी यानी केंद्रीय शासन की मोहताज हो गई. सारा ग्रामीण भारत सत्वहीन और नपुंसक सा हो गया. ■

प्रस्तुत अंश ठाकुरदास बंग द्वारा लिखित एवं वर्ष 1983 में प्रकाशित पुस्तक-गांव की सत्ता गांव के हाथ में से उद्धृत है. यह पुस्तक हमें बताती है कि सत्ता-शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कैसे हो और उसे जनकल्याणकारी कैसे बनाया जा सकता है.

-संपादक

पाठकों की दुनिया

दवा कंपनियां और मरीज़

दवा कंपनियां दवाओं को मनचाही क़ीमत तय करके मरीज़ों को लूटती आई हैं, लेकिन अब ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि दवा कंपनियों के लिए आंकड़े देना ज़रूरी हो गया है. आवश्यक दवाओं की क़ीमतें तय करने के लिए 1 फ़ीसद से अधिक बाज़ार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडों की औसत क़ीमत को आधार बनाया जाएगा. दवा कंपनियों के लिए दवाओं के बारे में आंकड़े भेजना अनिवार्य हो सकता है. फार्मास्युटिकल विभाग नई ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर (डीपीसीओ) पॉलिसी में इसके लिए प्रावधान करने पर विचार कर रहा है. इस क़दम का मक़सद नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को (एनपीपीए) को देश भर में बन रही दवाओं के भरोसेमंद डाटा बेस से लैस करना है. फार्मास्युटिकल विभाग नई दवा नीति के तहत बाज़ार आधारित फार्मूले के आधार पर आवश्यक दवाओं की क़ीमतें तय करने के लिए एक वैकल्पिक डाटा बेस तैयार करना चाहता है. बताया जा रहा है कि नई डीपीसीओ पॉलिसी के तहत आवश्यक दवाओं की क़ीमतें तय करने के लिए दवाओं के बारे में जून 2011 के आईएमएस हेल्थ के डाटा बेस को आधार बनाया जाएगा, लेकिन फार्मास्युटिकल विभाग भविष्य के लिए सिर्फ़ आईएमएस हेल्थ के डाटा बेस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है.

विभाग का मानना है कि एनपीपीए के पास दवाओं के बारे में भरोसेमंद डाटा बेस होना चाहिए. एनपीपीए मौजूदा डीपीसीओ पॉलिसी के तहत लागत आधारित फार्मूले के आधार पर क़ीमतें तय करने के लिए दवा कंपनियों से आंकड़े मंगाता है, लेकिन कई बार दवा कंपनियां आंकड़े नहीं भेजती हैं. ऐसे में नई डीपीसीओ पॉलिसी के तहत दवा कंपनियों के लिए आंकड़े भेजना अनिवार्य बनाने पर विचार किया जा रहा है. दरअसल ऐसा करने से भारत में दवाओं के सभी ब्रांड के बारे में सटीक डाटा बेस तैयार किया जा सकेगा. फार्मास्युटिकल विभाग नई दवा नीति के तहत आवश्यक दवाओं की खुदरा क़ीमतें तय करने के लिए नई तैयार डीपीसीओ पॉलिसी तैयार कर रहा है. विभाग ने नई डीपी-सीओ पॉलिसी लागू करने की समय सीमा 2 अप्रैल तय की है. मौजूदा समय में देश में दवाओं के 90 हज़ार से अधिक ब्रांड बिक रहे हैं. आवश्यक दवाओं की क़ीमतें तय करने के लिए 1 फ़ीसद से अधिक बाज़ार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडों की औसत क़ीमत को आधार बनाया जाएगा. विश्लेषकों का कहना है कि 90 हज़ार से अधिक ब्रांड और उनकी क़ीमतों के बारे में सटीक आंकड़े जुटाना आसान नहीं होगा.

-आशुतोष कुमार सिंह, *मुंबई, महाराष्ट्र*

मिसाल हैं जोधपुर के शकील

देश में जहां एक ओर भ्रष्टाचार चरम पर है और लोग दूसरों का हक़ छीन रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो अपनी जायदाद जनहित के लिए दान दे देते हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं जोधपुर के शकूर. उन्होंने अपनी 40 लाख रुपये की ज़मीन डिस्पेंसरी बनाने के लिए सरकार को दान में दी है. इसके लिए उन्हें पांच साल तक नगर निगम के चक्कर लगाने पड़े. इससे पहले वह अपनी 60 लाख रुपये की दो ज़मीनें दान कर चुके हैं. एक ज़मीन मदरसे के लिए और दूसरी मस्जिद के लिए उन्होंने दान में दी. डिस्पेंसरी में मरीज़ों का इलाज होगा, स्कूल में बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे और मस्जिद में लोग इबादत करेंगे. लोगों, ख़ासकर भ्रष्टाचारियों को ऐसे लोगों से सबक़ हासिल करना चाहिए. उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें हमेशा ही इस दुनिया में नहीं रहना है. एक न एक दिन उन्हें ईश्वर को अपना मुंह दिखाना है. फिर क्यों वे लोगों का हक़ मारकर अपने लिए गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं.

-सरफ़राज़ ख़ान, *हिसार, हरियाणा*

पैकिंग और जनता

पिछले दिनों दिल्ली के एक कॉलेज के कार्यक्रम में अपने भाषण में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की असलियत का बखान कर गए. मोदी ने कहा कि किसी भी माल को बेचने के लिए अच्छी पैकिंग की ज़रूरत होती है यानी माल की गुणवत्ता और असलियत के कोई मायने नहीं? ठीक उसी तरह जैसे भाजपा ने ऊपरी तौर पर राम मंदिर निर्माण की पैकिंग लगाकर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन असल में उसका पार्टी की नीयत से कोई वास्ता नहीं. मोदी का भाषण उनकी उस पैकिंग की पोल खोल गया, जिसे दिखाकर गुजरात की जनता को पिछले एक दशक से गुमराह किया जा रहा है और विकास के नाम की नक़ली पैकिंग दिखाकर जनता से वोट लिया जा रहा है. ■

-राजा ज़ैड ख़ान, *दिल्ली*

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संसद की गंभीरता कितनी है

संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है. यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बजट बहुत सख्त होगा, जैसा कि अमेरिका चाहता है. विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का मानना है कि हिंदुस्तान में हर तरह की सब्सिडी या आर्थिक सहायता बंद होनी चाहिए. दरअसल, अमेरिका भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता है, जिसका जीना या मरना अमेरिकी हितों से सीधे जुड़ा हुआ हो.

बीच में यह ख़तरा पैदा हो गया था कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी होकर उतनी ताक़तवर हो जाए कि वह चीन का मुक़ाबला करने लगे, लेकिन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को लगा कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तरह मज़बूत होने के रास्ते पर चल पड़ी, तो वह कभी अमेरिका को उसी तरह चुनौती देगी जैसे आज चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है. इसलिए भारत सरकार के आर्थिक सुधारों के नाम पर उठाए गए आत्मघाती क़दमों को अमेरिकी आदेश के पालन के रूप में देखना चाहिए. इस बार कठोर बजट की आशा करनी चाहिए.

अगर बजट कठोर न हुआ, तो मानना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव की ओर जा रही है, लेकिन इस बार यह तय है कि कांग्रेस चाहकर भी लोगों को राहत देने वाला बजट नहीं ला सकती. इसके पीछे अर्थ शास्त्रियों का मानना यही है कि सरकार ने फ़ैसले ही ऐसे कर लिए हैं, जो उसे आसान बजट की राह पर नहीं ले जाते हैं. इसलिए हमें यह जरूर मान लेना चाहिए कि आने वाला बजट महंगाई के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए न केवल रास्ते खोल देगा, बल्कि भ्रष्टाचार को क़ानूनी संरक्षण मिले, इसका दरवाज़ा भी खोलेगा.

सच तो यह है कि संसद के इसी बजट सत्र में संसद को अपनी बेशर्मी पर ताली बजाते देखने का सौभाग्य हमें मिलेगा. आश्चर्य की बात तो यह है कि जब अन्ना हजारे के अनशन को समाप्त करवाने के लिए संसद की बैठक हुई थी और उसमें जिस सर्वसम्मत प्रस्ताव को पास किया गया था, उसकी अवहेलना का ध्यान संसद को आज तक नहीं आया है. दरअसल, प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को ख़त लिखकर जिन-जिन विषयों को लोकपाल बिल में शामिल करने का वादा किया था, अब वे विषय भी लोकपाल बिल में शामिल नहीं हैं. ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि राजनीतिक दलों को लोकपाल के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है. तुर्रा यह कि कॉरपोरेट सेक्टर भी लोकपाल के दायरे से बाहर है. और तो और, लॉ इंफोर्समेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई तो लोकपाल के दायरे में हैं ही नहीं. तब यह लोकपाल क्यों आ रहा है?

भारत की संसद प्रस्ताव पास करे और बाद में इससे मुकर जाए, तो देश की जनता ऐसी संसद को क्या समझे? 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री अगर लिखित वादे करे और उन वादों पर अमल न करे, तो उसे प्रधानमंत्री की बेईमानी माना जाना चाहिए या नहीं? सरकार की साख आख़िर कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है, इसके बारे में अगर कोई एक उदाहरण सामने रखना हो, तो भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों के उदाहरण काफ़ी हैं.

यहां सवाल यह भी उठता है कि भारत की संसद प्रस्ताव पास करे और बाद में इससे मुकर जाए, तो देश की जनता ऐसी संसद को क्या समझे? 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री अगर लिखित वादे करे और उन वादों पर अमल न करे, तो उसे प्रधानमंत्री की बेईमानी माना जाना चाहिए या नहीं? सरकार की साख आख़िर कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है, इसके बारे में अगर कोई एक उदाहरण सामने रखना हो, तो भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों के उदाहरण काफ़ी हैं. संसद में कही गई बातों पर इंदिरा गांधी जितनी चिंतित रहती थीं और उन बातों को अमल में लाने में जितनी रुचि लेती थीं, यह अब तक लोगों को याद है. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सिर्फ़ इसलिए इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि उनसे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अयोध्या में अगर वह पांच ईंटें रखने दें, तो वह सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे. लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनसे कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का मैं पालन नहीं करा सका, तो मैं किस बात का प्रधानमंत्री. भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने सिर्फ़ इसलिए त्यागपत्र दे दिया था कि वह भारत के प्रधानमंत्री को रोज़ाना आदेश लेने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे. हालांकि जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तो चंद्रशेखर जी के पास श्री राजीव गांधी का संदेश पहुंचा कि वह इस्तीफ़ा न दें, कांग्रेस उनका फिर से समर्थन करेगी. चंद्रशेखर ने इस संदेश वाले काग़ज़ के टुकड़े को फाड़कर फेंक दिया. अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को एक पवित्र मंदिर माना और इसीलिए उन्होंने संसद का हमेशा वैसा ही सम्मान भी किया.

लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि न संसद, न प्रधानमंत्री और न संसद में बैठे उसके सदस्य अपनी कही बातों पर क़ायम रहते हैं. शायद इसीलिए स्थिति को देखकर कहावत बनी है कि इस हमाम में सब नंगे होते हैं. इसी समय अन्ना हजारे अपनी देशव्यापी यात्रा शुरू कर रहे हैं. उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में न केवल जनलोकपाल शामिल है, बल्कि भ्रष्टाचार भी शामिल है. अब उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन को भी इसमें शामिल कर लिया है. अब सवाल ये भी उठता है कि अगर अन्ना हजारे की सभाओं में फिर से भीड़ जुटने लगी और उन्हें जनसमर्थन मिलने लगा, तो क्या संसद और जनता आमने-सामने खड़े होंगे?

जिस बात को देखकर अफ़सोस होता है, वह सरकार, संसद और राजनीतिक दलों की, जनता की तकलीफ़ के प्रति असंवेदनशीलता है. सरकार, संसद और राजनीतिक दलों को अब इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि ढांचे के यानी गवर्नेंस के बिगड़ते स्वरूप ने लोगों को कितना परेशान कर रखा है. महंगाई बढ़ाने के हर तरीक़े पर सरकार, संसद और राजनीतिक दलों की लगभग एक राय है. रस्मी विरोध होता है और रस्मी विरोध ख़त्म भी हो जाता है. इसी तरह भ्रष्टाचार पर रोक का कोई सार्थक उपाय किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल कहीं न कहीं सरकार में हैं और वे सब लगभग एक चरित्र के दिखाई देने लगे हैं.

बजट सत्र से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हर संसद का सत्र जनता की आशाओं को समाप्त कर रहा है. इतना ही नहीं, अगर संसद का नज़ारा देखना हो, तो आप एक बजे के बाद लोकसभा चैनल को देखिए. सांसदों की सदन में उपस्थिति, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा, आपको बता देगी कि गंभीरता कितनी है? जब पार्टियों के नेता ही सदन में न हों, तो उनके फॉलोवर सदन में क्यों होंगे? इसलिए ऐसी संसद से, इसके किसी सत्र से या बजट सत्र से कैसी उम्मीदें पालनी चाहिए, फ़ैसला आपको करना है. ■

editor@chauthiduniya.com

जेंडर रिवोल्यूशन जारी रहना चाहिए

मेघनाद देसाई

क्रांति एक ही बार में नहीं होती, बल्कि यह सतत होती रहती है. 14 जुलाई, 1789 को बास्तील के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति की घोषणा हुई थी, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी और कई साल बाद इसकी समाप्ति हुई. भारत में 16/12 (दिल्ली गैंग रेप) से लैंगिक क्रांति की शुरुआत हुई है और ऊपर नीचे होते हुए यह अभी भी जारी है. कुछ महिला विरोधी लोग इस आंदोलन को और भड़का देते हैं, जिससे इस आंदोलन को जारी रखने में सहायता मिलती है. इस बार श्रीनगर के शाही इमाम महिला आंदोलन को बचाने के लिए सामने आ गए. यह विचार कि तीन लड़कियों द्वारा पश्चिमी संगीत गाने-बजाने से इस्लाम की तौहीन हो सकती है, हंसी के लायक़ है. क्या इसकी उम्मीद नहीं की गई थी. आख़िर एफएएन बैंड (फ़राह, अनीका और नोमा) के गाना गाने को हराम क्यों कहा जाना चाहिए. ऐसा केवल इसलिए, क्योंकि उन्होंने अनजान लोगों के सामने गाना गाया है, अपने परिवार के सामने नहीं, और यही धर्म के लिए हराम है. क्या यह केवल लड़कियों पर लागू होता है, जो इन शाही इमामों के अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहती हैं. सवाल उठता है कि क्या इन लोगों ने कश्मीर के संगीत उत्सव या फिर क़व्वाली उत्सव के समय गाने वाली महिलाओं को गाने से रोका है. कुछ लोग कह सकते हैं कि मुख्य मुद्दा संगीत के स्वरूप का है यानी पश्चिमी संगीत ही मुख्य मुद्दा है. क्या अगर ये भारतीय संगीत गातीं या बजातीं, तो सब कुछ अच्छा होता. ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरह लड़कियों को रोका ही जाता.

हालांकि फ़तवे के कारण इन्हें रोका नहीं जा सका, बल्कि हिंसा की धमकी के कारण डर पैदा हुआ है. यहां पर उमर अब्दुल्ला को उनके बयान के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना संभव था, उतनी कड़ी कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने वोट बैंक के बारे में नहीं सोचा, बल्कि कार्रवाई की बात कही. उन्होंने सही बात कही है, न कि राजीनीतिक टिप्पणी की है. दिल्ली में हुई सामुहिक दुष्कर्म की घटना के बाद जितनी भी टिप्पणियां आईं, उनमें उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी को सबसे अच्छा कहा जा सकता है. अन्य लोगों को इस बात का ही डर था कि उन्हें क्या कहना चाहिए. 16/12 की घटना के बाद आरएसएस और आसाराम बापू ने जिस तरह की टिप्पणी की, वह महिलाओं को डराने वाली ही थी. अगर महिलाएं अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहती हैं, तो यह रूढ़िवादी हिंदू और इस्लाम के विरुद्ध हो जाता है. राजनीतिक व्यवस्था धर्म को चुनौती देने से डरती है. धर्म को चुनौती नहीं देने के पीछे एक कारण धर्मनिरपेक्षता को बताया जाता है. इस समय धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि रूढ़ियों के सामने निरीह भाव से आत्मसमर्पण कर देना. इसके साथ ही वोट बैंक का भी मुद्दा है, जिसके कारण सभी दल इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि उनके बोलने से कहीं उनका वोट बैंक उनसे ख़फ़ा न हो जाए.

ग़ौरतलब है कि लैंगिक आंदोलन ने ईसाईयत को भी चुनौती दी है, लेकिन इसे बहस के द्वारा निपटा लिया गया है और अपने भीतर इसने बदलाव भी किया है. एंग्लिकन चर्च में महिला बिशप के मुद्दे पर बहस हुई है. हालांकि अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है. गे लोगों के बारे में भी बहस हुई है और इसे स्वीकार भी किया गया है. संभव है कि कुछ समय में चर्च गे विवाह को अनुमति दे दे. हालांकि अभी इसके लिए संघर्ष चल रहा है. कैथोलिक चर्च में भी कुछ परंपरागत रूढ़ियों पर बहस की जा रही है. तलाक़, गर्भपात, घरेलू हिंसा, वैवाहिक दुष्कर्म आदि पर धार्मिक विश्वास वाले लोगों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी बहस की जा रही है. भारत में धार्मिक मुद्दों पर बहस करने से लोग हिचकते हैं. पचास के दशक में नेहरू के समय संशयवाद को बढ़ावा दिया गया था, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए. वामपंथी दलों ने भी हिंदू धर्मपरायणता का मुद्दा उठाया. उनका मानना है कि धर्मपरायणता भारत के आधुनिकीकरण के मार्ग में रोड़ा है. रामायण, भागवत गीता, उपनिषद आदि की आलोचना की जाती है, लेकिन यह आलोचना केवल दर्शन के स्तर पर ही की जाती है. भारत आधुनिक, उदार संविधान वाला और महिला विरोधी विचार से मुक्त धर्म वाला देश नहीं हो सका है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसे ऐसा होने से रोक दिया. वामपंथ को अफ़वाह के आधार पर बदनाम कर दिया गया और सभी लोगों ने बिना कोई आलोचना के धार्मिक रीति-रिवाजों को मनाना शुरू कर दिया. निरीश्वरवाद समाप्त हो गया और कबीर जैसे पंथनिरपेक्ष संत एक फैशन बन गया. इंदिरा गांधी के इस खेदपूर्ण पंथनिरपेक्षता का सबसे अधिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और बाबरी मस्जिद विध्वंस इस पंथनिरपेक्ष स्वरूप के लिए वाटरलू साबित हुआ. हम लोगों को धार्मिक रूढ़िवादिता के ख़िलाफ़ संघर्ष फिर से शुरू करना है और मानवाधिकार के लिए जंग करनी है. धार्मिक रूढ़िवादिता से महिलाओं का शोषण बढ़ता है. अगर भारतीय महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो हमे धार्मिक सुधार के लिए बहस करनी ही होगी. हमारे बीच उमर अब्दुल्ला की तरह कम ही लोग हैं, जो न केवल फ़तवे को चुनौती देते हैं, बल्कि उसका विरोध भी अपनी पूरी ताक़त से कर सकते हैं. इसलिए 16/12 के बाद का आंदोलन जारी रखना चाहिए, जब तक कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करने लगें. ■

feedback@chauthiduniya.com

टॉनिक को बचाने वाले एनिमल वेलफेयर टीम के सदस्य ने कहा कि टॉनिक को देखने पर लगता है कि कोई स्वीट बॉय आपकी आंखों में झांक रहा हो.

25 फरवरी–03 मार्च 2013
चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार – जीने का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

जानने का अधिकार, जीने का अधिकार

आख़िर क्या है सूचना का अधिकार क़ानून, कैसे आप इस क़ानून का इस्तेमाल कर बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी और सिखा सकते हैं भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सबक़. चौथी दुनिया आपको बताएगा कि कैसे करें इस क़ानून का इस्तेमाल और कैसे बनाएं आरटीआई आवेदन. अगर आपको इस क़ानून के इस्तेमाल से संबंधित कोई परेशानी हो, या कोई सुझाव चाहिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम आपको देंगे सही सुझाव.

क्या है सूचना का अधिकार?

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित एक क़ानून है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ. यह क़ानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है. उल्लेखनीय है कि सरकार, सरकारी ख़र्च और अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भी हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही दिया जाता है. यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ ख़रीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है. इसलिए हम सभी के पास यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार ख़र्च किया जा रहा है? यह हमारे मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है.

क्या और किससे सूचना मांग सकते हैं?

सभी इकाइयों/विभाग जो संविधान, या अन्य क़ानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त-पोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.

- ब सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं.
- ब सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं.
- ब सरकारी दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकते हैं.
- ब सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं.
- ब सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं.

किससे मांगे सूचना और आवेदन शुल्क कितना है?

इस क़ानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है. हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग फीस रखी गई है. सूचना पाने के लिए 2 रुपये प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है. आवेदन शुल्क नक़द, डीडी या बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा कर सकते हैं. कुछ राज्यों में, आप कोर्ट फीस टिकटें ख़रीद कर अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं. ऐसा करने पर आपकी फीस जमा मानी जाएगी. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप क्या हो?

केंद्र सरकार के विभागों के लिए, कोई प्रारूप नहीं है. आपको एक सादा काग़ज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही आवेदन बना सकते हैं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं. अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास निजी संदर्भ के लिए अवश्य रखें.

क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है?

हां, यदि आवेदन पीआईओ को दे दी गई है, तो 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. लेकिन यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दी गई है, तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए.

यदि सूचना न मिले?

यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हों, तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर करें. हरेक विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है. सूचना प्राप्ति के 30 दिनों एवं आरटीआई अर्ज़ी दाख़िल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम दायर कर सकते हैं.

द्वितीय अपील क्या है?

द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है. द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर की जा सकती है. केंद्र सरकार के विभागों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के लिए, राज्य सूचना आयोग है. प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख़ के 90 दिनों के भीतर कि जब तक प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

दांत से उठाई 23 बेंच

अगर कोई एक बेंच उठा लेता है, तो उसके हाथों में दर्द होने लगता है. लेकिन ज़रा सोचें, यदि हमारे मुंह पर जरा-सा दरवाज़ा लग जाए तो ख़ून तक निकलने लगता है, हालांकि इनके दांत से ख़ून नहीं निकलता, दरअसल, चीन के तीस वर्षीय ली होंग्झिओ ने एक अनोखा विश्व कीर्तिमान बनाया है. पेशे से स्टंटमैन, ली ने लकड़ी की बनी हुई 23 बेंचों को अपने दांतों से 11 सेकंड तक साध कर वहां उपस्थित लोगों को चौंका दिया. हर एक बेंच एक मीटर लंबी, 45 सेंटीमीटर ऊंची और तीन किलो वजनी थीं. ग़ौरतलब है कि ली से पहले का गिनीज रिकॉर्ड मात्र 14 बेंचों का था. ■

इंसान की शक्ल वाला कुत्ता

हमेशा सुना है कि दुनिया में एक ही शक्ल के दो इंसान होते हैं, लेकिन यहां उल्टा है. अमेरिकी प्रांत केंटुकी में इंसान से मिलती-जुलती शक्ल वाला यह डॉगी लोगों को काफी पसंद है और इसका नाम रखा गया है टॉनिक. और तो और, टॉनिक के लिए उसका होम स्वीट होम सर्च किया जा रहा है. टॉनिक को बचाने वाले एनिमल वेलफेयर टीम के सदस्य ने कहा कि टॉनिक को देखने पर लगता है कि कोई स्वीट बॉय आपकी आंखों में झांक रहा हो. टॉनिक की स्वीट सी स्माइल अहसास दिलाती है कि वह एक इंसान है, न की डॉगी. ग्रुप के सदस्य ने बताया कि टॉनिक बहुत शांत और समझदार है. टॉनिक को और कुत्तों के साथ रखा जाता है और उसकी पूरी देखभाल की जाती है. टॉनिक सबसे बहुत घुल-मिल गया है. पर टॉनिक सबको बहुत पसंद है. पसंद क्यों न हो, वह स्पेशल जो है. बताया गया है कि टॉनिक की बॉडी में मेडिकल जांच के लिए एक माइक्रोचिप डाल दी गई है. टॉनिक को गोद लेने की फीस 250 डॉलर है और मालिक को ख़ुद ही इस डॉगी को लेने आना होगा. लगता है कि टॉनिक को जल्द ही अपना घर मिल जाएगा. ■

अब शर्माने की ज़रूरत नहीं

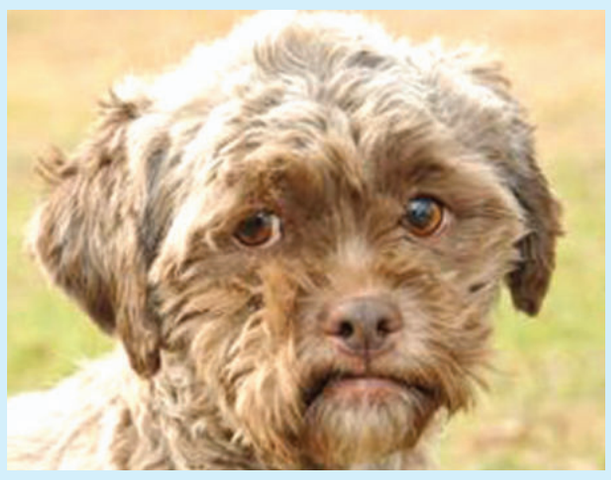

वैसे तो लिखना एक कला है और लिखते समय हर किसी से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ग़लती हो ही जाती है. जी हां, यह पेन की नहीं, हमारी ग़लती होती है. दरअसल, कुछ लिखते वक्त अनजाने में आप ग्रैमर और स्पेलिंग संबंधी न जाने कितनी ग़लतियां करते होंगे और इसकी वजह से आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती होगी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एक ऐसी कलम बन गई है, जो आपको इस तरह की ग़लतियों की जानकारी दे देगी.

जर्मनी की कंपनी लर्नस्टिफ्ट ने ऐसी कलम बनाने का दावा किया है. कंपनी का कहना है कि यह कलम ग्रैमर और स्पेलिंग से जुड़ी हर ग़लती पर वाइब्रेट (थरथराएगा) होगी, जिससे यह पता चल जाएगा कि आप ग़लती कर रहे हैं. फ़िलहाल यह कलम प्रारंभिक चरण में है. कंपनी का कहना है कि कलम के यूजर्स दो तरह के फंक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे, कैलीग्राफी और ऑर्थोग्राफी मोड. कैलीग्राफी मोड जहां वाक्यों की बनावट संबंधी ग़लतियों की जानकारी देगा, वहीं ऑर्थोग्राफी मोड बर्तनी और ग्रैमर संबंधी ग़लतियों के बारे में बताएगा. दरअसल, इस कलम में कई सेंसर लगे हुए हैं. जब लेटर्स को ग़लत तरीक़े से सजाकर वाक्य बनाया जाता है, तो सेंसर उसे पकड़ लेते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको फल भी मिलेगा. सामाजिक कार्यों में धन व्यय होगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. तेज़ी से चल रहे कुछ कार्यों में बाधा ज़रूर उत्पन्न होगी, लेकिन आप विचलित न हों, प्रयासरत रहें. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति से संबंधित कोई अच्छी ख़बर मिलेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप अपने अच्छे कार्यों के कारण पुरस्कृत होंगे. आप स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. व्यवसायी जोखिम वाले बाज़ार से बचकर चलें. नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी परेशानी होगी. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. क़ानूनी मामलों में ज़रूर सफलता मिलेगी. वाहन चलाते समय सावधान रहें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आप निराशावादी विचारों से दूर रहें. आर्थिक रूप से आप मज़बूत होंगे. आपके ऐश्वर्य से जुड़े ख़र्च बढ़ेंगे. आप अपने सगे-संबंधी से विवाद को न बढ़ने दें. स्वास्थ्य का ख्याल रखें. हल्के उतार- चढ़ाव का अनुभव होगा. अचानक किसी यात्रा का योग बनेगा. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप अपने आलसीपन को त्याग दें. अपने व्यय को नियंत्रण में रखें. अपनी कार्यशैली में आप परिवर्तन लाएंगे. आर्थिक रूप से थोड़ा सख्त महसूस करेंगे. कोई पूर्वलंबित कार्य भी पूर्ण होगा. शारीरिक रूप से भी आप मज़बूत होंगे. सट्टे और जोखिम वाले बाज़ार से बचकर चलें. विद्यार्थी कड़ी मेहनत करेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का ख़ास ख्याल रखें. ज़्यादा उलझनों में फंसने से बचें. किसी पर अंधविश्वास कर कोई कार्य न करें. गाड़ी सावधानी से चलाएं. इस सप्ताह आपका थोड़ा समय अतिथि सत्कार में भी गुज़रेगा. आपको मित्र-बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा. संपत्ति से संबंधित किसी क़ानूनी दावपेंच से बचें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह आप तनाव न लें. किसी मांगलिक कार्य में भी आपको शरीक होना पड़ेगा. स्थानांतरण से संबंधित कोई ख़बर मिलेगी. संतान सुख उत्तम रहेगा. आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, अन्यथा नुक़सान की आशंका है. ख़र्च को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप यात्रा से यथासंभव बचें. विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा. नई संपत्ति की ख़रीद से संबंधित योजना बनाएंगे और आप उसमें सफल होंगे. आप कटु सत्य बोलने पर लगाम लगाएं. पारिवारिक लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी लगन से करेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाएंगे. आपके जीवन में उत्साह का संचार रहेगा. कुछ बनते कार्यों में बाधा का अनुभव करेंगे. अपने स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. सामाजिक रूप से मान-सम्मान बढ़ेगा. वाहन से संबंधित कुछ ख़र्चे होंगे. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आपकी आमदनी बढ़ने वाली है. इस सप्ताह व्यापारी और नौकरीपेशा दोनों वर्ग ख़ुश रहेंगे. किसी बुज़ुर्ग का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनेगा. आपकी भाग-दौड़ बढ़ेगी. स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. अपनी रणनीति किसी को बताने से बचें. किसी लंबी दूरी की यात्रा से बचें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आप भाग्यशाली साबित होंगे और बहुत सारे रुके कार्य भी बनेंगे. विरोधी आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप पूरी चुनौती देंगे. पारिवारिक परेशानी के कारण मन घबराएगा. युवा काफ़ी उत्साहित रहेंगे. स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आप नए ऐश्वर्य की वस्तु जैसे मकान, गाड़ी ख़रीदने की योजना बनाएंगे. पारिवारिक माहौल सौहार्द्रपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग आमतौर पर ख़ुश रहेंगे. जोखिम वाले बाज़ार से बचकर चलें. संतान और दांपत्य सुख उत्तम रहेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आप धनोपार्जन के लिए व्यस्त रहेंगे. किसी ख़ास मित्र-बंधु की बातों में आकर जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति की ख़बर मिलेगी. व्यापारी अपने व्यापार में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे. स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा.

cshekhar_3@hotmail.com

दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोई देश अगर परमाणु परीक्षण करता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं देशों को होती है, जो पहले से ही परमाणु हथियार से लैस हैं.

परमाणु हथियार की होड़ का ज़िम्मेदार कौन ?

परमाणु हथियार की आकांक्षा विश्व के सभी स्वतंत्र और संप्रभु देशों को इसलिए है, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए इसे अब ज़रूरी समझा जाने लगा है. यह अलग बात है कि सभी देशों के पास इसकी तकनीक नहीं है, जिसके कारण वे इससे वंचित रह गए हैं, लेकिन कुछ देश इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं और जिनके पास यह हथियार है, वे इसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए और प्रयास कर रहे हैं. अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या वे देश, जो अभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे जिन्होंने केवल इसकी शुरुआत की?

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

उत्तर कोरिया ने तीसरा परमाणु परीक्षण किया, तो इस पर हो-हल्ला मच गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है. अमेरिका आग बबूला हो रहा है. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा ही रहा है, लेकिन उनकी सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी. दूसरी ओर, भारत ने भी इस परीक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि कोरिया का परमाणु परीक्षण इस क्षेत्र की शांति के लिए ख़तरा हो सकता है. भारत ने भी कोरिया को सलाह दे डाली कि उसे धैर्य से काम लेना चाहिए. आख़िर भारत ने कहां धैर्य रखा है, क्योंकि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे भी कुछ ऐसी ही सलाह दी थी, जैसी सलाह आज भारत उत्तर कोरिया को दे रहा है. दरअसल अब होगा यह कि पहले से ही कई प्रतिबंधों की मार झेल रहे उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे. हालांकि इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है. चूंकि अब उसने अपनी परमाणु ताक़त का इज़हार कर दिया है, इसलिए उस पर हमला करना तो मुमकिन है भी नहीं. आख़िर कोरिया यही तो चाहता है. उसे अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बचाए रखना है. दरअसल, कोरिया को अमेरिकी नीति पर भरोसा ही नहीं है. दक्षिण कोरिया को अमेरिका का सहयोग प्राप्त है. उत्तर कोरिया ने पहले भी कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है. कोरिया को लगता है कि अगर उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो परमाणु शक्ति संपन्न होना ज़रूरी है. ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने से न केवल राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा, बल्कि कोरिया अपना सर भी ऊंचा रख सकता है. उसे इराक़, अफ़ग़ानिस्तान और अन्य कई देशों की तरह अमेरिकी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कमोबेश यही स्थिति ईरान की भी है. वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं तथा इस आर्थिक प्रतिबंध को और कड़ा करने की धमकी दी जा रही है. इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्यहु का कहना है कि उनकी सरकार का प्राथमिक मिशन ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को विफल करना है, जबकि इज़रायल के पास ख़ुद ही परमाणु हथियार है. हालांकि वह इसकी घोषणा नहीं करता है, लेकिन सभी को इस बात की जानकारी है कि इज़रायल के पास परमाणु हथियार है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईरान को परमाणु हथियार से वंचित करने की नैतिक ज़िम्मेदारी उसके पास कैसे हो सकती है. दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोई देश अगर परमाणु परीक्षण करता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं देशों को होती है, जो पहले से ही परमाणु हथियार से लैस हैं. इन देशों में भी अमेरिका की चिंता सबसे बड़ी होती है, जिसका कारण उसकी अपनी नीतियां हैं. सच तो यह है कि उसने अपनी नीतियों के कारण ही सबसे ज़्यादा दुश्मन बने रखे हैं और जिसके सबसे ज़्यादा दुश्मन होंगे, उसे सबसे अधिक डर होगा. ईरान पर कितना भी प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह परमाणु हथियार बना लेगा. अनुमान यह भी है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है. आख़िर ईरान परमाणु बम बनाए भी क्यों नहीं, जबकि उसके आसपास के पांच देशों के पास परमाणु हथियार हैं. चीन पहले ही परमाणु बम बना चुका है.

भारत के पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान ने भी परीक्षण कर लिया है और वह भी अब परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है. इज़रायल अघोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उत्तर कोरिया ने तीन परमाणु परीक्षण करके यह बता दिया कि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं. ऐसे में ईरान के पास अगर परमाणु बम विकसित करने की तकनीक है, तो वह क्यों चूकेगा.

अब सवाल यह उठता है कि आख़िरकार परमाणु हथियार की होड़ क्यों उत्पन्न हुई और इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. सबसे पहले अमेरिका ने न केवल परमाणु बम बनाया, बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी में इसका इस्तेमाल भी किया. हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी. उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्वयुद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने युद्ध ख़त्म करने के लिए नहीं किया था, बल्कि दुनिया को अपनी ताक़त दिखाने के लिए किया था. सच तो यह है कि अगर अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं भी करता, तो जापान का पराजित होना तय था, क्योंकि जर्मनी और इटली पराजित हो चुके थे. 30 अप्रैल, 1945 को ही हिटलर की मौत हो गई थी और मई में जर्मनी ने हार भी स्वीकार कर ली थी. और इटली का पतन पहले ही हो चुका था, यानी धूरी राष्ट्र की पराजय अनिवार्य थी, लेकिन चूंकि अमेरिका को अपनी ताक़त दिखानी थी, इसलिए उसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया. इसके बाद तो परमाणु बम बनाने की होड़ लगना लाज़िमी ही था, क्योंकि सोवियत संघ को साम्यवाद का प्रसार करना था. अगर सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार नहीं होता, तो वह दूसरे देशों को कैसे प्रभावित कर सकता था. इसलिए रूस ने भी परमाणु बम बनाया. अब ब्रिटेन, जो अमेरिका के साथ परमाणु बम की तकनीक पर काम कर रहा था, पीछे कैसे रह सकता था, क्योंकि अमेरिका ने तो यह साफ़ शब्दों में कह दिया था कि वह किसी को परमाणु तकनीक नहीं देगा. बाद में ब्रिटेन भी अपने अभियान पर लग गया और उसने भी परमाणु बम बना लिया. इसी तरह फ्रांस और चीन भी इस होड़ में शामिल हो गया. भारत ने पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चीन से पराजित होने के बाद जब यह सवाल उठने लगा कि अगर भारत के पास परमाणु बम होता, तो क्या चीन उस पर आक्रमण करने की हिम्मत जुटा पाता, तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया और आख़िरकार परमाणु परीक्षण कर ही लिया, भले ही उसे आर्थिक प्रतिबंध की मार क्यों न झेलनी पड़ी हो. पाकिस्तान भी जैसे इसी समय का इंतज़ार कर रहा था और उसने भी भारत का जवाब दिया और परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया. कमोबेश यही स्थिति ईरान और उत्तर कोरिया की भी है. ऐसे में अभी परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तर कोरिया या करने जा रहे ईरान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं. इसके लिए तो ज़िम्मेदार अमेरिका ही है, जिसने सबसे पहले न केवल इसे बनाया, बल्कि इसका इस्तेमाल भी किया. इसी ने दूसरे देशों को इस बम की आवश्यकता महसूस करवाई और अब अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करता है, तो उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है.

अगर विश्व को परमाणु बम के ख़तरे से मुक्त करना है, तो फिर इसके लिए दूसरे विकल्प पर विचार करना पड़ेगा. भारत ने बहुत पहले ही यह विकल्प दे रखा है कि अगर दूसरे सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दें, तो वह भी अपने परमाणु हथियार समाप्त कर देगा. अगर अमेरिका या फिर अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सही मायने में विश्व की चिंता है, तो उन्हें इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. आख़िरकार दक्षिण अफ्रीका ने 1993 में ही अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे. पूर्व सोवियत राष्ट्रों बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे. अगर ये देश ऐसा कर सकते हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इज़रायल आदि क्यों नहीं कर सकते हैं ? भारत तो इसके लिए तैयार ही है. पाकिस्तान पर भी दबाव बनाया जा सकता है. अगर किसी एक देश के पास परमाणु हथियार होगा, तो दूसरे देश इसे बनाने की कोशिश तो करेंगे ही. भारत ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, अब कोरिया ने बनाया है और ईरान बनाने वाला है. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ और देश इस पर काम करें या फिर कर भी रहे होंगे. ब्राजील और अर्जेंटीना ने भी सत्तर और अस्सी के दशक में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आख़िरकार बना नहीं पाए. इराक़ और लीबिया भी कोशिश कर चुके हैं. ऐसा तो है नहीं कि ये देश फिर से कोशिश नहीं कर सकते हैं. इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका सही तरीक़े से निभानी होगी और इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करना होगा. आख़िर विश्व को परमाणु बम की आवश्यकता ही क्या है. परमाणु हथियार वाले सभी देश अपना परमाणु हथियार नष्ट कर दें, ताकि आगे किसी को इसकी आवश्यकता ही नहीं हो, क्योंकि अगर इन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, तो इनके पास दूसरे देशों को मना करने का नैतिक अधिकार भी होगा. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

कमरों की कमी के कारण बच्चे साल भर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

बाबा का मुक्तिदान

सरदार काका साहब मिरीकर का बेटा बाला साहब मिरीकर कोपर गांव का रहने वाला था. वह दौरे पर चितली गांव जा रहा था. रास्ते में वह बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया. मस्जिद में जाकर उसने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया. बाबा और बाला साहब के बीच कुशलक्षेम और इतर बातें होती रहीं. बाबा ने उसे चेतावनी देने के स्वर में कहा, क्या तुम हमारी द्वारकामाई को जानते हो? कुछ समझ न सकने के कारण बाला साहब मिरीकर चुप रह गया. बाबा आगे कहते गए, यही (मस्जिद) हमारी द्वारकामाई है, जहां तुम बैठे हो. यह ख़तरों और चिंताओं को दूर करके उन बच्चों की रक्षा करती है, जो इसकी गोद में बैठते हैं. इस मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी द्वारकामाई बहुत दयालु हैं. यह सरल हृदय भक्तों की माता हैं और संकट में उनकी रक्षा करती हैं. इसकी गोद में जो एक बार बैठ जाता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं. जो इसकी छाया में विश्राम करता है, उसे आनंद मिलता है. जब बाला साहब मस्जिद से जाने लगा, तो बाबा ने उसे भभूत दी और अपना हाथ उसके सिर पर रखा. उन्होंने फिर कहा, क्या तुम लंबा बाबा यानी सर्प को जानते हो? उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी कसी और उसे दाहिनी कुहनी के नज़दीक लाते हुए मुट्ठी खोलकर हथेली को सांप के फन की तरह हिलाते हुए कहा, वह बहुत भयानक है, पर द्वारकामाई के बच्चों का वह क्या बिगाड़ सकता है? जब मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी द्वारकामाई रक्षा करती हैं, तब सांप क्या कर सकता है? जितने लोग वहां उपस्थित थे, वे बाबा के इस काम और मिरीकर के संदर्भ में कही गई बात को जानने के लिए आतुर हो गए, किंतु इस विषय में बाबा से पूछने का साहस किसी को नहीं हुआ. बाला साहब मिरीकर ने बाबा को प्रणाम किया और जाने लगा. बाबा ने शामा (माधवराव देशपांडे) को बुलाया और मिरीकर के साथ चितली जाने के लिए कहा. शामा बाला साहब मिरीकर के पास आया और उसे बताया कि बाबा की आज्ञानुसार वह उसके साथ चितली जाएगा. मिरीकर ने जवाब दिया, तुम्हें साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे असुविधा होगी. शामा ने वापस आकर बाबा को मिरीकर की बात बताई. बाबा बोले, ठीक है, मत जाओ. हमारा तात्पर्य अच्छाई करने का है और अच्छा करेंगे. जो कुछ नियति में है, वह होगा ही.

इसी बीच बाला साहब ने फिर सोचा और शामा को साथ चलने के लिए कहा. फिर बाबा से विदा लेकर

जब बाला साहब मस्जिद से जाने लगा, तो बाबा ने उसे भभूत दी और अपना हाथ उसके सिर पर रखा. उन्होंने फिर कहा, क्या तुम लंबा बाबा यानी सर्प को जानते हो? उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी कसी और उसे दाहिनी कुहनी के नज़दीक लाते हुए मुट्ठी खोलकर हथेली को सांप के फन की तरह हिलाते हुए कहा, वह बहुत भयानक है, पर द्वारकामाई के बच्चों का वह क्या बिगाड़ सकता है? जब मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी द्वारकामाई रक्षा करती हैं, तब सांप क्या कर सकता है?

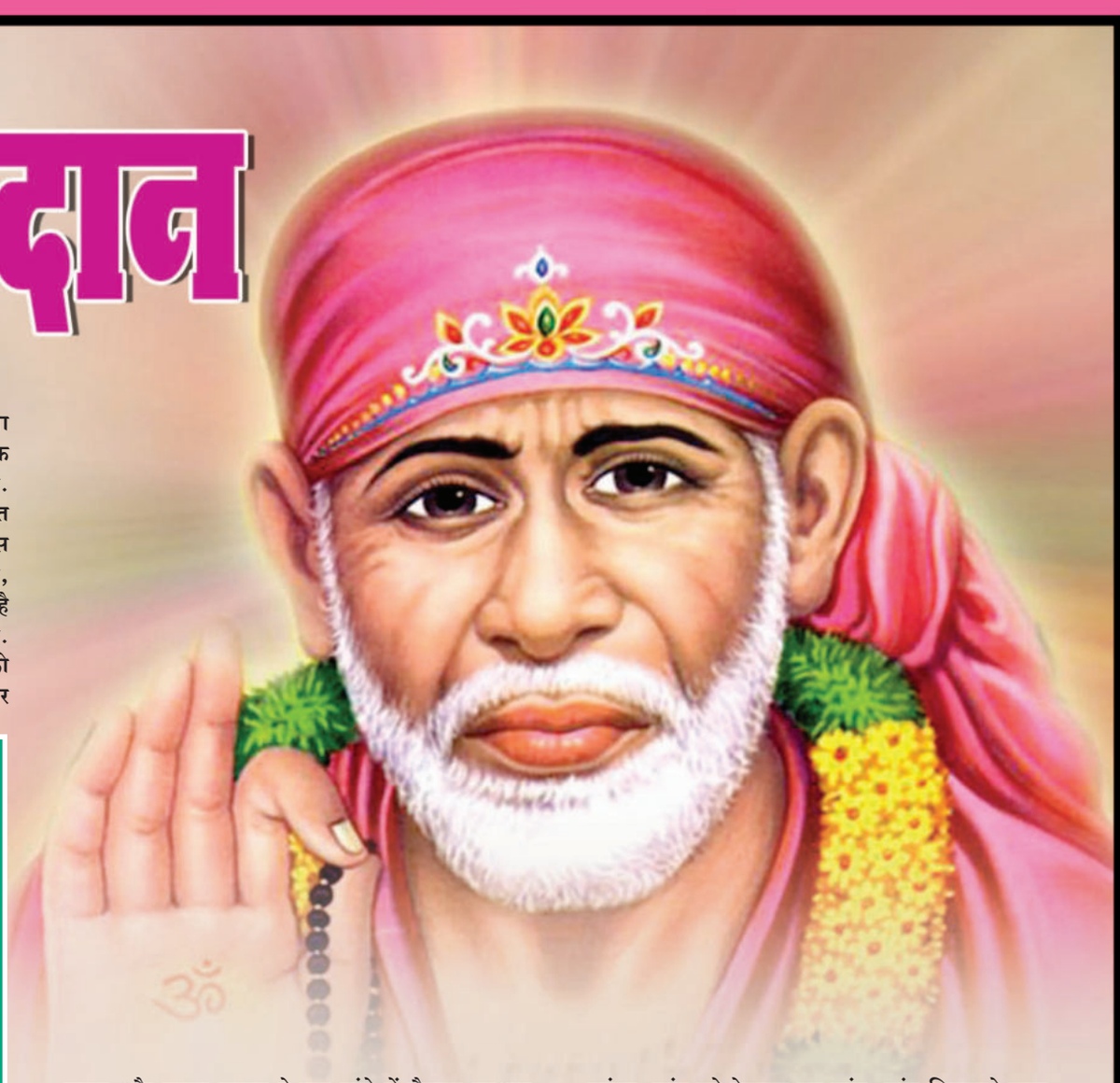

शामा और बाला साहब ने एक तांगे में बैठकर प्रस्थान किया. वे रात को नौ बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में उन्होंने डेरा जमाया. उस समय दफ्तर में काम करने वाले नहीं आए थे, इसलिए चटाई पर बैठकर बाला साहब अख़बार पढ़ने लगा. उसका उपरना (चादर) उसकी कमर से नीचे फैला हुआ था. उसके एक हिस्से में चुपचाप आकर एक सांप कुंडली मारकर बैठ गया. उसे किसी ने नहीं देखा. वह सरसराहट की आवाज़ करता हुआ सरकने लगा. उसकी सरसराहट की आवाज़ चपरासी ने सुनी और तुरंत लालटेन लिए वहां पहुंचा. सांप को देखकर वह सांप-सांप चिल्लाने लगा. बाला साहब डर से कांपने लगा. शामा भी आश्चर्यचकित रह गया. वहां उपस्थित लोग और शामा डंडे एवं लाठियां ले आए. सांप बाला साहब की कमर से सरक कर नीचे ज़मीन पर आया और मार डाला गया. इस तरह साई बाबा की भविष्यवाणी और चेतावनी सच हुई और संकट टल गया. बाबा के प्रति बाला साहब मिरीकर की आस्था और गहरी हो गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरहद पर भारतीय गांवों के हालात क्या हैं

ख्वाजा यूसुफ़ जमील
feedback@chauthiduniya.com

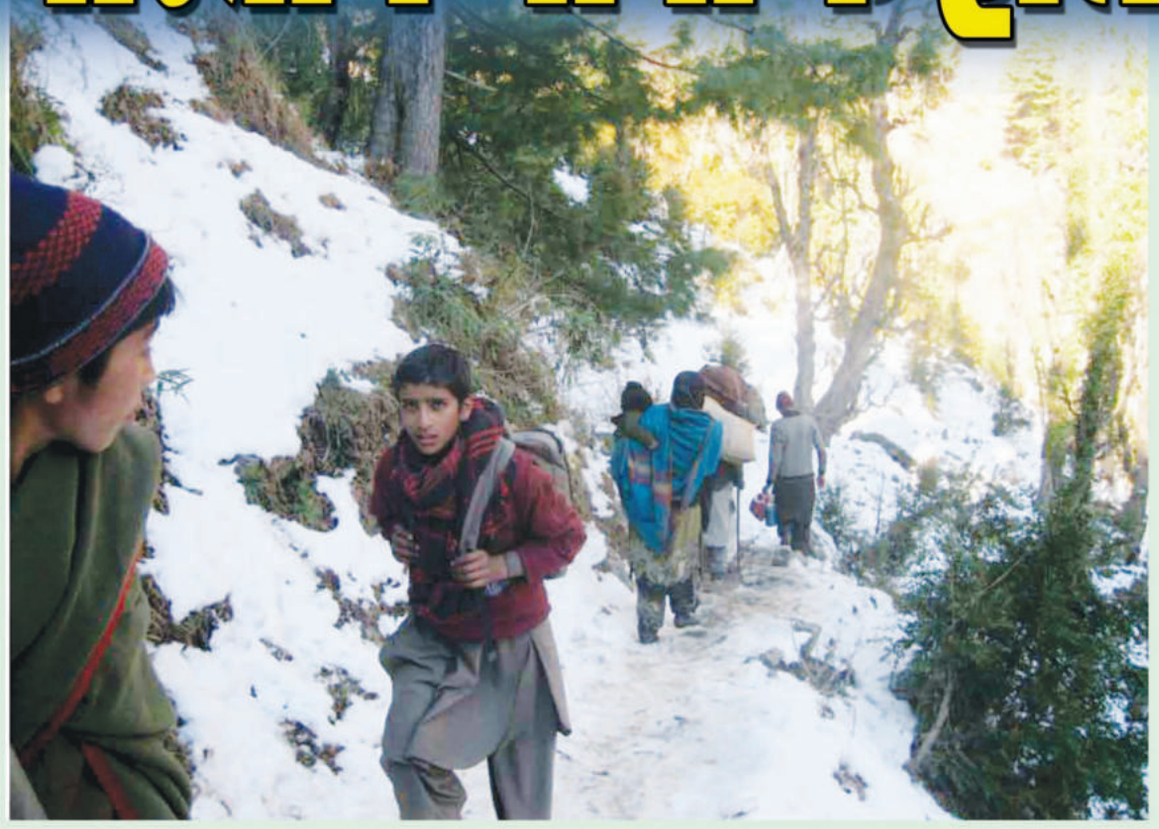

हाल में जम्मू स्थित पुंछ ज़िले से लगने वाली भारतीय सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा वीभत्स कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच उपजा तनाव वक़्त के साथ ठहर तो गया है, लेकिन यह कहना कि अब घाटी शांत हो गई है, शायद जल्दबाज़ी होगी. दोनों ओर से बस सर्विस शुरू तो अवश्य हो गई है, लेकिन पाकिस्तान कभी फ़ौजी कार्रवाई, तो कभी शाहरुख़ ख़ान पर विवादित बयान देकर मामले को जानबूझकर गरमाए रखने की कोशिश कर शांति की पहल को धक्का पहुंचाने का प्रयास कर रहा है. सरहद पर फ़ौजियों के साथ अमानवीय कार्रवाई का असर न सिर्फ़ सीमा तक सीमित था, बल्कि समूचे देश में ग़ुस्से की लहर के रूप में देखा गया. एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाज़े बंद हो चुके हैं और युद्ध ही आख़िरी विकल्प है, लेकिन हमेशा की तरह भारत ने संयमता का परिचय देते हुए एक बार फिर से युद्ध को टालकर विश्व को शांतिप्रिय देश होने का सबूत दिया है. इस हालात में भारतीय मीडिया ने भी बख़ूबी अपना रोल अदा किया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टरों ने सरहद से लाइव टेलीकास्ट कर देशवासियों को भारतीय सैनिकों के हालात से रूबरू ज़रूर करवाया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान किसी को भी सरहद पर बसे नागरिकों की याद नहीं आई. किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आख़िर सरहद पर बसे भारतीय गांवों के हालात क्या हैं? सरकारी योजनाओं का यहां क्या हाल है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है?

वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर समूचे दक्षिण एशिया महाद्वीप पर नज़र आता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी को पड़ता है, तो वे सीमा के क़रीब रहने वाले हमारे जैसे निवासी हैं, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अपनी ताक़त आज़माते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी भी पल कहीं से एक गोली या बारूद गांव वालों के लिए बर्बादी का पैग़ाम लेकर हाज़िर हो सकता है. सच तो यह है कि जैसे-जैसे ये दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वैसे-वैसे सीमा पर बसे निवासियों के दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं. कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो पिछले कुछ वर्षों से सीमा पर लगभग शांति थी. समय-समय पर की गई फ़ौजी कार्रवाई का मूल्य सरहद पर बसे नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से चुकाना पड़ता रहा है. दरअसल, इन्हें मालूम है कि गोली और जवाब में चलने वाली गोली एक फ़ौजी और आम नागरिक में अंतर को नहीं जानती है. यही कारण है कि सीमा से सटे गांवों के प्रत्येक घर में तक़रीबन ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने अपना भाई, पिता या पति खोया है.

इतना ही नहीं, बल्कि आज भी पुंछ में विकलांगों की एक बड़ी संख्या मौजूद है, जो भारत और पाकिस्तान की गोलाबारी में अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग खोकर सारी ज़िंदगी अपाहिज के रूप में जीने को मजबूर है. सीमा से सटे कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि न तो यहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है और न ही रोज़गार का कोई साधन ही उपलब्ध है. शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से भी गांव के बच्चे वंचित हैं. पुंछ ज़िला हेडक्वार्टर से महज़ 14 किलोमीटर दूर पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा से लगा गांव बांडी चेंचिया इसका एक उदाहरण है, जहां शिक्षा के मौलिक अधिकार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं. आर्थिक रूप से पिछड़े इस गांव में दस वार्ड हैं और क़रीब 6000 की आबादी है. यहां के निवासी 54 वर्षीय मुहम्मदीन के अनुसार, वार्ड नंबर 3 में आठ वर्ष पूर्व एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया गया था. तब से लेकर आज तक महज़ एक कमरे में यह स्कूल चल रहा है.

कमरों की कमी के कारण बच्चे साल भर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. देश भर में बच्चों को स्कूल से जोड़ने वाली केंद्र की महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना यहां नाकाम ही नज़र आती है. स्कूल की छात्रा आफ़रीन (9 वर्ष) के अनुसार, उन्हें मिड डे मील कभी मिलता है, तो कभी नहीं. गांववासी शमशादा क़ौसर (38 वर्षीय) कहती हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में शिक्षा की बात तो दूर की बात है, उन्हें सरकार द्वारा दिया जाने वाला मिड डे मील और यहां तक कि साफ़ पानी भी उपलब्ध नहीं होता है. वह पूछती हैं कि हम इसकी शिकायत कहां कराएं? गांव के एक बुज़ुर्ग मुहम्मद बशीर के अनुसार, हमारे गांव के बच्चे पुंछ जाकर प्राइवेट एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहद कमी है. उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में तीन अध्यापकों की ड्यूटी है, लेकिन कोई भी रोज़ नहीं आता है. ऐसे में केवल एक शिक्षक से सभी विषयों की पढ़ाई करवाने की आशा करना बिल्कुल बेमानी है. यह स्थिति सीमा पर बसे केवल एक गांव के शिक्षा व्यवस्था की है. कुछ ऐसे ही हालात स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हैं, जहां न तो स्वास्थ्य केंद्र सेवा देने लायक़ है और न ही जनवितरण प्रणाली से गांववालों को कोई विशेष लाभ मिल पाता है. कमोबेश ऐसी परिस्थिति लगभग इन सभी गांवों में है, जो सीमा के बिल्कुल क़रीब हैं, लेकिन इसके बावजूद एक कटु सच यह है कि यह देश के दूसरे हिस्सों की तरह मीडिया की सुर्ख़ियां नहीं बन पाती है.

पिछले 65 सालों में कई अवसर आए हैं, जब दोनों ही देश कभी फ़ौजी, तो कभी राजनीतिक स्तर पर बयानबाज़ी कर संबंध में तनाव पैदा करते रहे हैं, लेकिन रिश्ते की इस कड़वाहट का मूल्य सीमा पर बसने वालों को ही चुकाना पड़ा है. कहने में ग़लत नहीं होगा कि इन दोनों पाटों के बीच सीमा पर रहने वाले पिसकर रह गए हैं. इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय फ़ौजी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. सच्चाई तो यह है कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने वाला फ़ौजी हो ही नहीं सकता है. फ़ौजियों के साथ किसी भी प्रकार की अमानवीय हरकत एक फ़ौजी के साथ-साथ सीमा पर बसे सभी नागरिकों को चिंतित करता है. इस प्रकार के उपजे तनाव से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है, जो पहले से ही तंगहाली और सरकारी योजनाओं के अभाव में जी रहे हैं. *(चरखा)* ■

वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर समूचे दक्षिण एशिया महाद्वीप पर नज़र आता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी को पड़ता है, तो वे सीमा के क़रीब रहने वाले हमारे जैसे निवासी हैं, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अपनी ताक़त आज़माते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी भी पल कहीं से एक गोली या बारूद गांववालों के लिए बर्बादी का पैग़ाम लेकर हाज़िर हो सकता है. सच तो यह है कि जैसे-जैसे ये दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वैसे-वैसे सीमा पर बसे निवासियों के दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं. कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो पिछले कुछ वर्षों से सीमा पर लगभग शांति थी.

भक्त सूरदास की रचनाएं कृष्ण प्रेम से लबरेज़ हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण लीला का मनोहारी वर्णन किया है.

अनंत विजय

विवाद के साये में पुस्तक मेला

हर साल आयोजित दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार कई मायनों में अहम है. नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक एमए सिकंदर ने पिछले साल यह ऐलान किया था और कहा था कि उन्हें कुछ वक़्त दिया जाए, तो वह बेहतर आयोजन कर सकते हैं. उस वक़्त सिकंदर ने एनबीटी का पदभार ग्रहण ही किया था. दिल्ली के प्रगति मैदान में रविवार को ख़त्म हुए विश्व पुस्तक मेले का यह आयोजन पहले के पुस्तक मेलों से ज़्यादा व्यवस्थित और नियोजित है. पिछले सालों में आयोजित पुस्तक मेलों को अव्यवस्था और लोकार्पणों के रेले के तौर पर याद किया जाता था. प्रकाशकों को भी इस बात की शिकायत रहती थी कि उन्हें कोई ऐसी जगह मुहैया नहीं करवाई जाती है, जहां लेखकों का पाठकों के साथ संवाद हो सके. बड़े प्रकाशक तो कई स्टॉल को जोड़कर अपनी दुकान सजाते थे, जहां विमोचन आदि में काफ़ी सहूलियत होती थी, लेकिन छोटे प्रकाशकों को काफ़ी दिक्क़तों का सामना करना पड़ता था. हालांकि इस बार मेले के आयोजक ने इस दिक्क़त को दूर कर दिया है. प्रगति मैदान के हॉल नंबर 12 में एक बड़ा–सा ऑथर्स कॉर्नर बना दिया है, जहां हर घंटे लेखक अपनी बात रखते हैं. कभी कहानी पाठ होता है, तो कभी कविता पाठ, कभी बुज़ुर्ग लेखक अपने अनुभवों को बांटते हैं, तो कभी युवा लेखक अपनी लेखन प्रक्रिया को साझा करते हैं. पाठकों और लेखकों के बीच संवाद से हमेशा साहित्य का भला हुआ है. पाठकों के मन में उठने वाले सवालों का भी जवाब मिलता है और लेखकों को भी पाठकों की नब्ज़ पर हाथ रखने का मौक़ा मिलता है. इसका लाभ लेखकों को कुछ भी रचते समय होता है.

दरअसल, इस बार का पुस्तक मेला हिंदी के पाठकों, प्रकाशकों और लेखकों के लिए एक विवाद लेकर भी आया. हिंदी की बिल्कुल नवोदित कहानीकार ज्योति कुमारी ने हिंदी के प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह राजकमल प्रकाशन और उसके मालिक अशोक माहेश्वरी पर बेहद सनसनीख़ेज़ आरोप लगाए. इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा विस्तार देना होगा. ज्योति कुमारी ने कुछ कहानियां हंस में लिखीं और राजेंद्र यादव की सरपरस्ती में हिंदी कहानी जगत में प्रवेश किया. लेकिन सिर्फ़ सरपरस्ती से किसी रचनाकार के आगे बढ़ने में हमेशा से संशय रहता है. इस बार भी था. ज्योति की कहानियां हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगीं, तो लगा कि सरपरस्ती से इतर उसमें प्रतिभा भी है. कई कहानियां छप जाने के बाद हर कथाकार की तरह उसके मन में भी आया होगा कि एक संग्रह छपे. लेकिन संग्रह छपने के पहले जिस

तरह का अप्रिय विवाद हुआ, वैसा विवाद कोई भी संवेदनशील और नवोदित रचनाकार नहीं चाहता है. अपवाद हर जगह होते हैं. ज्योति कुमारी के मुताबिक़, प्रकाशक ने उसके सामने कुछ साहित्येत्तर शर्तें रखीं, जिस वजह से उसने राजकमल प्रकाशन से अपना संग्रह नहीं छपवाने का फ़ैसला लिया. ज्योति के बयान के मुताबिक़, प्रकाशक ने उनके संग्रह का नाम दस्तख़त और अन्य कहानियां की जगह शरीफ़ लड़की रखने का प्रस्ताव दिया था. शरीफ़ लड़की भी ज्योति की ही एक अन्य कहानी है. कहानीकार के मुताबिक़, प्रकाशक का यह तर्क था कि शरीफ़ लड़की शीर्षक ज़्यादा सेलेबल है. इसके अलावा, ज्योति यह भी चाहती थी कि उसके संग्रह में राजेन्द्र यादव और नामवर सिंह की लिखी भूमिका प्रकाशित की जाए. इस पर भी प्रकाशक को ऐतराज़ था. प्रकाशक यह चाहते थे कि कवर पर नामवर सिंह की कोई एक पंक्ति और बैक कवर पर राजेन्द्र जी की लिखी भूमिका से चार पांच पंक्तियां प्रकाशित कर दी जाएं. ज्योति को प्रकाशक की दोनों शर्तें मंज़ूर नहीं थीं. ज्योति कुमारी ने राजकमल प्रकाशन के मालिक पर यह भी आरोप जड़ा है कि उन्होंने उसे नाम बदलने की नसीहत दी. ज्योति के मुताबिक़, अशोक माहेश्वरी के अनुसार, ज्योति कुमारी नाम सेलेबल नहीं है. लिहाज़ा उसको बदलकर ज्योतिश्री या कुछ और दिया जाना चाहिए. कोई ऐसा नाम, जो पाठकों को आकर्षित कर सके. ज्योति को प्रकाशक का यह तर्क भी नहीं रुचा. ज्योति का कहना है कि मेरा लेखन उस बाज़ारवाद के ख़िलाफ़ रहा है, जो ज़रूरत नहीं, बल्कि जेब देखकर तय होता है. जो औरत को एक उत्पाद, प्रेजेंटेशन की तरह पेश करता है, अपने लाभ के लिए. तो सिर्फ़ इसलिए कि किताब की बिक्री यह नाम सहायक होगा और इस नाम से सेंसेशन फैलेगा, जो बाज़ार के दृष्टिकोण से लाभदायक है, मैं इस नाम पर सहमत नहीं हो सकी. यह बात ठीक है, लेखिका को अपनी किताब कहीं से भी छपवाने का हक़ है, लेकिन अगर इस पूरे विवाद को प्रकाशक की नज़र से देखें, तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है. प्रकाशक कारोबार के लिए बैठा है और वह बाज़ार का दोस्त है. अगर वह बाज़ार से दुश्मनी मोल लेगा या बाज़ार के नियमों के ख़िलाफ़ जाएगा, तो फिर क्या ख़ाक कारोबार करेगा. प्रकाशक की इन दोनों सलाहों में किसी तरह की कोई दिक्क़त नहीं है. ये दो ऐसी सलाह हैं, जो कोई भी प्रकाशक दे सकता है. इसलिए इस पर इतना बड़ा वितंडा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी.

अशोक माहेश्वरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने राजेन्द्र यादव से व्यक्तिगत बातचीत में कुछ सुझाव दिए थे. उनका कहना है कि पुस्तक मेले के अवसर पर वह तीन युवा कथाकारों– ज्योति, आकांक्षा और इंदिरा की किताबें छाप रहे थे और उनमें से किसी भी संग्रह में भूमिका नहीं थी. लिहाज़ा उन्होंने ज्योति को परोक्ष रूप से यह सलाह दी. राजेंद्र यादव का भी कहना है कि अशोक माहेश्वरी ने कुछ भी ग़लत नहीं किया. चूंकि वह इस पूरे मामले में बीच में थे, लिहाज़ा उनको पूरी जानकारी है. लेकिन यहां अशोक माहेश्वरी को यह समझना चाहिए था कि कहानीकार या कहानियां कितनी अहम रही होंगी, जिसके लिए नामवर सिंह को भी क़लम उठानी पड़ी. राजेंद्र यादव तो गाहे–बगाहे लेखकों–लेखिकाओं को आशीर्वचन देते ही रहते हैं.

लेकिन जिस तरह की चर्चा पुस्तक मेले में चल रही है और मीडिया में इस पूरे विवाद को कास्टिंग काऊच की तरह से पेश किया जा रहा है, हमारे लिए दरअसल वह चिंता का विषय है. ज्योति कुमारी ने एक पत्र जारी कर लेखकों का साथ मांगा है और इस तरह की अनैतिक साहित्यिक हथकंडों के पुरज़ोर विरोध का आह्वान भी किया है. ज्योति की इन बातों की व्याख्या हर कोई अपने तरीक़े से कर रहा है. लेकिन चाहे जो भी हुआ है, यह सच है कि एक नवोदित लेखक और हिंदी के शीर्ष प्रकाशक के बीच विश्व पुस्तक मेले के दौरान इस तरह के अप्रिय विवाद से हिंदी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. दरअसल, अगर हम इस विवाद के बहाने से हिंदी प्रकाशन जगत पर ग़ौर करें, तो एक बेहद तकलीफ़देह तस्वीर उभर कर सामने आती है. राजकमल प्रकाशन जैसा शीर्ष प्रकाशक ज्योति कुमारी जैसी बिल्कुल नई लेखिका की किताब बग़ैर किसी एग्रीमेंट के छापने को क्यों तैयार हो जाता है. दूसरा सवाल यह है कि ज्योति कुमारी, आज जिस स्त्री शक्ति की दुहाई दे रही हैं और जिस तरह से अपने और राजकमल के बीच के विवाद को एक बड़ा फ़लक देने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने भी बग़ैर एग्रीमेंट के अपने संग्रह की पांडुलिपि राजकमल प्रकाशन को क्यों सौंपी. क्या उन्हें राजकमल प्रकाशन संस्थान पर इतना भरोसा था या फिर कोई और वजह थी, जिसने उसे एग्रीमेंट के बग़ैर किताब छपवाने के लिए राज़ी कर लिया था. ज्योति को इन वजहों,अगर कोई थी, तो खुलासा करना चाहिए. अगर उन्होंने बग़ैर किसी अन्य वजह की, अनुभवहीनता के चलते ऐसा किया था तो उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की ज़रूरत है. इस मामले में वाणी प्रकाशन ने बेहद प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया और ज्योति–राजकमल विवाद के बीच में पहले ज्योति कुमारी से प्रकाशन एग्रीमेंट किया और फिर उसके संग्रह को छापा. अगर राजकमल ने भी किताब छापने से पहले ज्योति कुमारी से एग्रीमेंट किया होता, तो बेहतर होता, शर्तें पहले ही साफ़ हो जातीं. राजकमल प्रकाशन जैसे संस्थान से इस तरह के अनप्रोफेशनल एप्रोच की अपेक्षा नहीं की जा सकती है.

साहित्य में इस तरह से लेखकों–प्रकाशकों के बीच पहले भी कई अप्रिय प्रसंग सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार इस विवाद में जिस तरह से साहित्येत्तर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसने हिंदी प्रेमियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. हिंदी में प्रकाशक और लेखक का संबंध बहुत कुछ विश्वास की बुनियाद पर चलता है. अगर इस छोटे से विवाद ने इस विश्वास की बुनियाद में छोटी–सी भी दरार पैदा कर दी, तो लेखक–प्रकाशक संबंधों पर इसका दूरगामी असर होगा. आज ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी के बड़े लेखक इस पूरे विवाद में दख़ल दें और अगर कोई साहित्येतर वजह है, तो उसको बातचीत से हल करें. हिंदी को बदनामी से बचाने के लिए यह बेहद ज़रूरी है. वैसे ज़रूरत तो अशोक माहेश्वरी को प्रोफेशन एप्रोच अपनाने की भी है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सूरदास का कृष्ण प्रेम

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है. श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूरज माने जाते हैं, जिनकी भक्ति के लबरेज़ रचनाओं से हिंदी साहित्य जगमगा उठा है. हाल में राजकमल प्रकाशन ने सूर संचयिता नामक एक किताब प्रकाशित की है, जिसमें महान कवि सूरदास के जीवनकाल पर रोशनी डालने के साथ ही उनकी चुनिंदा रचनाओं को भी शामिल किया गया है. किताब के संपादक हैं मैनेजर पाण्डेय, जिनकी इससे पहले भी सूरदास पर आधारित किताब भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य प्रकाशित हो चुकी है. सूरदास के जन्म स्थान और जन्म तिथि को लेकर अनेक मतभेद हैं. उनकी जन्मभूमि के तौर पर अब गोपाचल (ग्वालियर), मथुरा प्रांत में कोई गांव, रुनकता (आगरा), सीही (दिल्ली) और साही (आगरा) का ज़िक्र आता है. साहित्य लहरी के एक पद में उनका निवास स्थान गोपाचल बताया गया है. इसी तरह अनेक आलोचकों ने उनके जन्म और मृत्यु के समय को लेकर साहित्य लहरी के मुनि पुनि रसन के रस लेख वाले पद को स्वीकार किया है, लेकिन इस पद के इतने विरोधी अर्थ दिए गए हैं कि उनके आधार पर सूरदास की जन्म तिथि का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

वार्ता साहित्य और सांप्रदायिक मान्यता के आधार पर यही कहा जाता है कि सूरदास वल्लभाचार्य से उम्र में दस दिन छोटे थे. वल्लाभाचार्य का जन्म संवत 1535 विक्रम की वैशाख शुक्ल 5 मंगलवार को माना जा सकता है. इसलिए डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा ने उनका जन्म संवत 1535 के आसपास माना है. सूरसागर के पदों में सूरदास के सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास और सूर श्याम, ये पांच नाम मिलते हैं. कहीं–कहीं सुरसुजान, सूरसरस, सूरजश्याम और सूरजश्यामसुजान भी मिल जाते हैं. इनमें से सुजान, सरस आदि विशेषण ही हैं. इसलिए उनके सूर या सूरज के साथ संयुक्त होने से स्वतंत्र नाम नहीं बन सकते. क़ाबिले–ग़ौर यह है कि क्या सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास और सूरश्याम ये पांचों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या अलग–अलग पांच व्यक्तियों के नाम हैं. डॉ. ब्रजेश्वर शर्मा ने सूरज, सूरजदास आदि नामों को सूरदास के मूल नाम का परिवर्तित रूप न मानकर किसी दूसरे व्यक्ति का ही नाम माना है. उनके मुताबिक़, सूरदास ने विकल्प से सूरज या सूरजदास का व्यवहार नहीं किया, वरना किसी सूरजदास नामक कवि ने सूरदास के पदों में अपनी छाप लगा दी और कुछ स्वरचित पद सूरसागर में शामिल कर दिए. वह सूरदास को सूरदास ही मानते हैं. सूर निर्णय के लेखकों के मुताबिक़, सूरदास का नाम सूरज था. सूरज का लघु रूप सूर है, फिर वैष्णवता के कारण सूरजदास, सूरदास या सूरश्याम नाम पड़ गए. इसलिए सूर, सूरदास, सूरजदास और सूरश्याम, ये सभी नाम सूरदास के ही हैं.

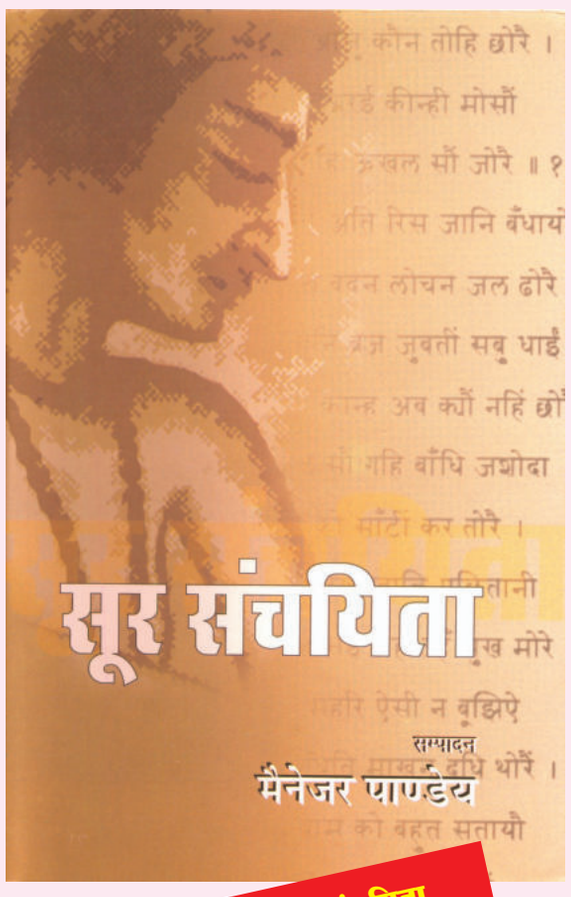

समीक्ष्य कृति : सूर संचयिता
संपादन : मैनेजर पाण्डेय
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
क़ीमत : 250 रुपये

सूरदास की जाति और वंश को लेकर भी संशय बरक़रार है. दरअसल, भारत में व्यक्ति का कम और जाति का अधिक महत्व है. यहां उन भक्तों को भी जाति निर्णय के प्रपंच से गुज़रना पड़ता है, जो ख़ुद जाति भेद के विरोधी थे. भक्तों की एक ही जाति है. उनका एक ही परिचय है कि वे भक्त हैं और भगवान ही उनके सर्वस्व हैं. सूर की कविता में संप्रदाय और जाति का आग्रह नहीं है. वहां तो एक भावनात्मक धरातल पर समान अनुभूति में निमग्न संपूर्ण समाज या पूर्ण व्यक्ति है. चौरासी वैष्णव की वार्ता में ज़्यादातर भक्तों की जाति का ज़िक्र है, लेकिन सूरदास जैसे संप्रदाय के मशहूर भक्त की जाति का कोई संकेत ही नहीं है. सूरदास के पदों में भी जाति संबंधी कोई बात नहीं कही गई है, इसकी वजह से उनकी जाति या वंश का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. हालांकि आलोचकों ने अपने–अपने विचारों के मुताबिक़ उनकी जाति बताई है. ग़ौरतलब है कि सूरदास नेत्रहीन थे. वह जन्मांध थे या बाद में नेत्रहीन हुए, इस पर भी मतभेद हैं. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ने सूर संदर्भ में लिखा है कि यह कहने का साहस नहीं होता है कि सूरदास ने बिना अपनी आंखों से देखे केवल कल्पना से ये सब लिखा है, लेकिन महाकवि सूरदास में उन्होंने सूरदास को जन्मांध सिद्ध किया है, जबकि चंद्रबली पांडेय के मुताबिक़, सूरदास जन्मांध नहीं थे. हां, धीरे–धीरे अंधे ज़रूर हो गए.

चौरासी वैष्णवन की वार्ता में सूरदास की जीवनी मथुरा और आगरा के मध्यवर्ती यमुना के किनारे गऊघाट नामक स्थान पर उनके निवास से शुरू होती है, जहां वल्लभाचार्य से उनकी मुलाक़ात होती है. वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और श्रीमदभागवत के दशम स्कंध की लीला की ललित झांकी भी दिखाई. इसके बाद सूरदास एकतारे पर हरि लीला का गायन करने लगे. उनकी बादशाह अकबर और गोस्वामी तुलसीदास से मुलाक़ात के वक़्त और जगह को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं. इसी तरह उनकी मौत के वक़्त को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं हैं. सूरदास के जन्मकाल की तरह ही उनका देहावसान–काल भी विवादग्रस्त है. अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनका देहावसान काल संवत 1640 विक्रम ही विश्वसनीय जान पड़ता है. पारसौली में उस वक़्त सूरदास को वल्लभाचार्य, श्रीनाथ जी और गोसाई विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ जी की आरती करते समय सूरदास को मौजूद न पाकर जान लिया कि सूरदास का आख़िरी वक्त क़रीब आ गया है. उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पुष्टिमार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना हो ले ले. आरती के बाद गोसाई जी रामदास, कुंभनदास, गोविंदस्वामी और चतुर्भुजदास के साथ सूरदास के नज़दीक पहुंचे और अचेत पड़े सूरदास को चैतन्य होते हुए देखा. सूरदास ने गोसाई जी का साक्षात भगवान के रूप में अभिनंदन किया और उनकी भक्तवत्सलता की प्रशंसा की. चतुर्भुजदास ने उस वक़्त शंका की कि सूरदास ने भगवद्यश तो बहुत गाया, लेकिन वल्लभाचार्य का यशगान क्यों नहीं किया. इस पर सूरदास ने बताया कि उनके लिए आचार्य जी और भगवान में कोई फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि जो भगवद्यश है, वही आचार्य जी का भी यश है. उन्होंने गुरु के प्रति अपनी आस्था भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो वाला पद गाकर ज़ाहिर की. इसी पद में सूरदास ने अपने को द्विविध आन्धरो भी बताया. इसके बाद सूरदास ने शरीर त्याग दिया. सूरदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की. काशी नागरीप्रचारिणी सभा के खोज विवरण की रिपोर्ट के मुताबिक़, सूरदास के नाम से 25 ग्रंथों की सूची उपलब्ध है. इनमें सूरसारावली, सूर लहरी, सूरसागर, भगवत भाषा, दशम स्कंध भाषा, सूरसागर सार, सूर रामायण, मानलीला, राधा रसकेलि कौतूहल, गोवर्धनलीला (रास लीला), दानलीला, भंवर लीला, नाग लीला, व्याहलीला, प्राणप्यारी, दृष्टिकूट के पद, सूरशतक, सूरसाठी, सूरपचीसी, सेवाफल, सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद, हरिवंश टीका (संस्कृत), एकादशी माहात्म्य, नल दमयंती और राम जन्म शामिल हैं.

भक्त सूरदास की रचनाएं कृष्ण प्रेम से लबरेज़ हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण लीला का इतना मनोहारी वर्णन किया है कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है.

खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी
कटि कछनी पीतांबर बांधे, हाथ लए भौंरा, चक, डोरी
मोर मुकुट, कुंडल स्रवननि बर दसन–दमक दामिनि–छवि छोरी
गए स्याम रवि–तनया कैं तट, अंग लसति चंदन की खोरी
औचक ही देखी तहं राधा, नैन बिसाल भाल दिए रोरी
नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठि रुलति झकझोरी
संग लरिकिनी चलि इत आवति, दिन–थोरी, अति छबि तन–गोरी
सूर स्याम देखती हीं रीझै, नैन–नैन मिलि परी ठगोरी

किसी भी रचनाकार की रचनाओं में जीवन के यथार्थ और अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है. हालांकि उन्हें भक्त कवि माना जाता है, लेकिन कृष्ण की भक्ति के अलावा उनकी रचनाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को देखा जा सकता है.

एक किसान के तौर पर वह अपने पद में खेतीबाड़ी का ज़िक्र करते हैं–
प्रभु जू यौं कीन्हीं हम खेती
बंजर भूमि गाउं हर जोते, अरू जेती की तेती
काम क्रोध दोउ बैल बली मिलि, रज तामस सब कीन्हौं
अति कुबुद्धि मन हांकनहारे, माया जूआ दीन्हौं
इंद्रिय मूल किसान, महातृन अग्रज बीज बई
जन्म जन्म को विषय वासना, उपजत लाता नई
कीजै कृपादृष्टि की बरषा, जन की जाति लुनाई
सूरदास के प्रभु सो करियै, होई न कान कटाई

उन्होंने अपने पदों में किसानों की ग़रीबी, कर्मचारियों के अनाचार और सामंतों की लूट का भी ज़िक्र किया है.

अधिकारी जम लेखा मांगै, तातैं हौं आधीनौ
घर मैं गथ नहिं भजन तिहारो, जौन दिय मैं छूटौं
धर्म जमानत मिल्यों न चाहै, तातैं ठाकुर लूटौ
अहंकार पटवारी कपटी, झूठी लिखत बही
लागै धरम, बतावै अधरम, बाक़ी सबै रही
सोई करौ जु बसतै रहियै, अपनौ धरियै नाउं
अपने नाम की बैरख बांधौ, सुबस बसौं इहिं गाउं

उनकी रचनाओं में उर्दू फ़ारसी के शब्द भी ख़ूब मिलते हैं.

मोहरिल पांच साथ करि दीने, तिनकी बड़ी विपरीति
जिम्मैं उनके, मांगैं मोतैं, यह तौ बड़ी अनीति
पांच पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज बिगारे
सुनी तगीरी, बिसरि गई सुधि, मो तजि कीनौं है साफ़
सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीजै माफ़

बहरहाल, यह किताब सूरदास के जीवनकाल और उनके जीवनकाल से संबंधित विवादों को बयान करती है. इसके साथ ही सूरदास के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराती है. पाठकों को, ख़ासकर हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए यह किताब बेहद उपयोगी कही जा सकती है. ■

किताब मिली

पुस्तक
युगपुरुष
संपादक
शशिकांत सदैव
प्रकाशक
डायमंड बुक्स
मूल्य
75 रुपये

इस पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन प्रसंगों और उनके विचारों को शामिल किया गया है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

8 इंच वाला टैबलेट देश की पहली क्वॉडकोर टैब होगी. जिंक का दावा है कि इनमें से कुछ में तो ऐपल आई पैड 3 जैसी रेटिना डिस्प्ले वाली स्क्रीन दी जाएगी.

चौथी दुनिया
25 फरवरी-03 मार्च 2013

टोयोटा इटियोस लिवा

नई लिवा में 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा होगा. इसमें रीट्यून सस्पेंशन होगा, बेहतर ब्रेक होंगे और ज़्यादा पावर के लिए चौड़े पहिए भी होंगे. यह जानकारी प्रोजेक्ट से क़रीब से जुड़े सूत्र ने दी है.

जापानी कार कंपनी टोयोटा आने वाले दिनों में इटियोस लिवा हैचबैक का स्पोर्टी और ज़्यादा पावरफुल वर्जन लॉन्च करने का प्लान बनाया है. इटियोस का नया वर्जन लाने के पीछे कंपनी का मक़सद है. इंडिया में इस कार की प्रीमियम अपील और सेल्स को बढ़ावा देना है. कंपनी ने इस वर्जन में कुछ बड़े फ़ेरबदल किए हैं.

नई लिवा में 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा होगा. इसमें रीट्यून सस्पेंशन होगा, बेहतर ब्रेक होंगे और ज़्यादा पावर के लिए चौड़े पहिए भी होंगे. यह जानकारी प्रोजेक्ट से क़रीब से जुड़े सूत्र ने दी है. इटियोस लिवा के मौजूदा पेट्रोल वेरिएंट में 1200 सीसी का इंजन लगा है. नई लिवा के बारे में जापानी कार कंपनी के इंडियन जेवी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीओओ (मार्केटिंग एंड कमर्शल) संदीप ने कुछ भी कहने से इनकार किया है. उन्होंने कहा, कंपनी में कई प्रॉडक्ट्स के प्लान पर काम चल रहा है. मैं इसके बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता.

लिवा के नए मॉडल में डैशबोर्ड, स्विचगीयर और डोर पैनल को प्रीमियम फील देने के लिए बेहतर क्वॉलिटी का प्लास्टिक यूज किया जाएगा. इसमें नई कलर स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि टोयोटा यह नहीं चाहती कि उस पर इटियोस के मामले में क्वॉलिटी के साथ समझौता करने का आरोप लगे. एक इंडस्ट्री ऐनालिस्ट ने कहा, इटियोस सेडान और लिवा हैचबैक में वह क्वॉलिटी नहीं है, जिसके लिए टोयोटा दुनियाभर में जानी जाती है. उम्मीद है कि नई इटियोस में वे सभी चीजें होंगी, जो टोयोटा के इंडियन बिजनेस के लिए हैचबैक मार्केट-इंडिया के सबसे बड़े कार सेगमेंट में जगह बनाने में मददगार हो सकती हैं. जनवरी 2013 में टोयोटा की इंडिया में सेल्स पिछले साल के मुक़ाबले 23 फ़ीसदी घटकर 13,329 यूनिट तक आ गई थी. हालांकि, कंपनी ने 2012 में कुल 1,72,241 व्हीकल बेचे, जो पिछले साल से 27 फ़ीसदी ज़्यादा है. ■

सैमसंग एनएक्स1000

अफोर्डेबल प्राइस में डीएसएलआर जैसे रिजल्ट्स देने वाला कॉम्पैक्ट कैमरा कम ही हैं. सोनी एनईएक्स सीरीज के ज़रिए पहले ऐसा कर चुकी है. अब एनएक्स1000 के साथ सैमसंग इस काम में जुट गई है. एनएक्स1000 लेंस के लिए प्रॉपराइटरी एनएक्स माउंट यूज करती है, इसलिए इसमें सिर्फ़ सैमसंग के लेंस यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में थर्ड पार्टी लेंस माउंट अडप्टर लॉन्च हो, जो कैनन और निकॉन के लेंस यूज करने की सहूलियत दे.

इसमें ज़्यादातर डीएसएलआर की तरह एपीएस-सी साइज का सीएमओएस सेंसर लगा है. इसके साथ आने वाले पैकेज में एक एक्सटर्नल फ्लैश और 20-50 मिलीमीटर का (नॉन-इमेज स्टैबिलाइजेशन) लेंस शामिल है. इसे यूज करना एकदम आसान है क्योंकि इसमें बटन और कंट्रोल एकदम साफ बताए गए हैं. इसमें स्टैंडर्ड मोड डायल और डी-पैड है, जबकि इसके जूम/मैनुअल फोकस रिंग लेंस बैरल पर ही हैं.

कैमरे को यूज करते वक्त जब आप किसी मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करेंगे, तो एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा, जो बताएगा कि उसमें क्या है. यह फीचर हेल्प गाइड कहलाता है और इसे मेन्यू से बंद किया जा सकता है. इसके दूसरे फीचर्स में 3डी स्टिल, स्वीप पैनोरामा, स्टीरियो साउंड के साथ फुल एचडी वीडियो, मैनुअल कंट्रोल और कई प्री-सेट सीन मोड और क्रिएटिव फिल्टर्स हैं. कैमरे का परफॉर्मेंस बेहतरीन है. इसमें ऑटो फोकस बहुत फास्ट है, कलर्स एकदम पक्के आते हैं, शटर लैग मामूली है और आईएसओ 1600 तक नॉयज-फ्री इमेज आती है. इसकी पहली शिकायत यह है कि यह पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं है. इसके हॉटशू में फ्लैश की जगह एक्सटर्नल व्यू फाइंडर दिया गया है. जब इमेज कार्ड पर राइट हो रही होती है, तब कभी-कभार यह रिस्पॉन्स देने में एक सेकंड एक्सट्रा टाइम लेता है. अगर आपको टिल्ट किए जाने वाली टचस्क्रीन और मेटल बॉडी के साथ ऐसे ही परफॉर्मेंस वाले कैमरे चाहिए, तो आप सोनी का एनईएक्स 5-आर ख़रीद सकते हैं. ■

ऑनलाइन सेजेशन सॉफ्टवेयर

स्मोकिंग की बुरी लत भी अन्य नशे की लत की तरह ही होती है, जिसे छोड़ना ज़्यादातर लोगों के लिए कठिन होता है. इसके लिए वे काउंसिल से लेकर दवाओं का भी सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस लत से पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल नज़र आता है. ऐसे में निकट भविष्य में कुछ ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं, जो आपको इस लत से निजात दिलाने में हर पल मदद देंगे. ऑनलाइन सेजेशन सॉफ्टवेयर यूजर को आंकड़ों में यह बताता है कि आपकी स्मोकिंग की लत में कितनी कमी आई है और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है. दरअसल, यह उन लोगों के बारे में भी

बताता है, जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी है और उन्हें इससे कितना फ़ायदा हुआ है. ये सभी यूजर ऑनलाइन एक दूसरेकी प्रोगेस पर चर्चा कर सकते हैं और एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाकर स्मोकिंग कम करने में मदद भी कर सकते हैं.

डिसीजन रिमाइंडर: एक छोटा गैजेट डिसीजन रिमाइंडर है, जिसे किसी लॉकेट की तरह गले में या कलाई में बांधा जा सकता है. वैसे इसे जूते के अंदर भी रखा जा सकता है, लेकिन इसका संपर्क यूजर की त्वचा से ज़रूरी है. इस गा वेनिक सेंसर को फिलिप्स ने डेवलप किया है. जैसा कि स्किन कंडक्टीविटी बदल जाती है इमोशन के बदलने पर. जब भी स्मोकर स्मोकिंग छोड़ने में नया होता है और वह निकोटिन की कमी काफी महसूस करता है, तो रिमाइंडर इसे डिटेक्ट करके यूजर को याद दिलाता है कि आप सिगार पीना चाहते हैं, जबकि आप इसे छोड़ चुके हैं. आप आपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए.■

जिंक लाएगी क्वॉडकोर टैब

टेक्नालॉजी कंपनी जिंक ने ऐलान किया है कि वह कुछ ही दिनों में पांच नए टैबलेट लाएगी. इसमें खास बात होगी 7, 8, 9.7 और 10 इंच स्क्रीन साइज में वह ड्यूल कोर और क्वॉडकोर टैबलेट. ये सभी 15 हज़ार रुपये से कम की प्राइस रेंज में होंगे. दाम के हिसाब से यह नया बैरियर तोड़ेगा. 8 इंच वाला टैबलेट देश की पहली क्वॉडकोर टैब होगी. जिंक का दावा है कि इनमें से कुछ में तो ऐपल आई पैड 3 जैसी रेटिना डिस्प्ले वाली स्क्रीन दी जाएगी. साथ ही 1.6 गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर होगा और 32 जीबी की इनबिल्ट मेमोरी होगी. इसमें ड्यूल कैमरा के अलावा, कुछ और नए फीचर भी दिए होंगे. ■

जहाज से भी तेज दौड़ेगी बाइक

इसकी स्पीड, मशक्यूलर बॉडी, हवा को चीरती गड़गड़ाहट भरी आवाज़, इसे देखकर अच्छे-अच्छे के हौसले पस्त हो जाते हैं. जब यह अपने पीछे धूल का गुबार लिए और पलक झपकते ही ग़ायब हो जाता है रह जाता है तो सिर्फ़ धुंधला सा उसके गुजरने का अहसास. हम किसी सुपरमैन या फिर दैवीय शक्ति की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज बाइक की बात कर रहें हैं, जिसकी रफ्तार हवा से बातें करने वाले जहाज से भी तेज है. सबसे ख़ास बात यह है कि यह बाइक भारत में पेश की जाने वाली है.

इस बाइक को देखने के बाद देश में मौजूद सबसे बेहतरीन बाइकें भी आपको इसके सामने बच्चे नज़र आएंगी. अमेरिका की इंजन निर्माता कंपनी एमटीटी मरीन टर्बाइन टेक्नालॉजी ने इस बेहतरीन बाइक का निर्माण किया है. यह दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली बाइक है, जिसका सफल उत्पादन किया जा रहा है. हाल ही में इस बाइक को भारत में प्रदर्शित किया गया था. इस बाइक के इंजन की ताक़त और रफ्तार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह बाइक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार बुगाटी वेरॉन को भी पीछे कर चुकी है. इसके अलावा, इसकी गति फार्मूला वन कारों के मुक़ाबले तीन गुना ज़्यादा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, जल्द ही यह बाइक भारतीय सड़कों पर भी देखने को मिल सकती है. ■

एप्सन ईएच-टीडब्ल्यू8100 होम प्रोजेक्टर

शायद ही टॉप स्पेसिफिकेशन वाले होम सिनेमा प्रोजेक्टर इतने अट्रैक्टिव क़ीमत पर मिलते हैं. इतने कम दाम में इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और इसका परफॉर्मेंस काफी दमदार है.

एप्सन ईएच-टीडब्ल्यू8100 ऑल न्यू मॉडल है. इसमें 3,20,000:1 का कन्ट्रॉस्ट रेशो है. इसकी ब्राइटनेस 2400 ल्यूमेन है और यह फुल एचडी रेजॉल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है. यह लगभग 47 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसका वजन 8.4 किलो. इसको सेट करना बहुत आसान है. स्विच ऑन करने पर इसका मोटराइज्ड स्लाइडिंग कवर अपने आप खुल जाता है. इस लेंस को स्क्रीन के हिसाब से अडजस्ट किया जा सकता है. लेंस को दाएं-बाएं और ऊपर-नीचे शिफ्ट करने के लिए दो छोटे डायल लगे हैं. इसके बेसिक कंट्रोल किनारों पर दिए गए हैं, जो स्लाइडिंग कवर के अंदर छिपे हैं. मैनुअल फोकस और ऑप्टिकल ज़ूम के लिए लेंस के नज़दीक दो रिंग बनाए गए हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ज़रूरी सामान्य कंपोनेंट, कंपोजिट, वीजीए (डी-सब) और दो एचडीएमआई इनपुट दिए गए हैं.

इसे ज़्यादा कैलिबरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. कलर टोन के लिए प्री-सेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. डीप ब्लैक के लिए इसमें ऑटोमैटिक आइरिस का यूज होता है. जिन सीनों में गहरे रंग होते हैं, उन्हें बेहतर दिखाने के लिए यह लैंप की लाइट को कम कर देती है और उस सीन में ब्राइटनेस बढ़ा देती है. यह फीचर बहुत दमदार

है. इसका 3डी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है. दूसरे प्रोजेक्टर के उलट टीडब्ल्यू8100 में इनबिल्ट आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी 3डी सिग्नल इमिटर है. इसमें 2डी से 3डी कनवर्जन मुमकिन है, लेकिन इसका बेस्ट इफेक्ट तो ब्लू-रे डिस्क के मौलिक 3डी कॉन्टेंट या कंसोल के 3डी गेम्स के साथ यूज करने के लिए मिलता है. इसमें सिर्फ़ एक कमी है. इस पर 3डी देखने के लिए हर एक चश्मे पर 6,600 रुपये ख़र्च करने होंगे. कुल मिलाकर टीडब्ल्यू8100 जितने में मिल रहा है, उतने में बेस्ट परफॉर्मर है. इसे ख़रीदा जा सकता है. इसके बेस्ट एक्स्पीरियंस के लिए इसे टीएचएक्स सर्टिफाइड ऑडियो सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं.

स्पेसिफिकेशन: 3एलसीडी टेक्नालॉजी, 1920 गुणा 1080 पिक्सल रेजॉल्यूशन, 2400 ल्यूमेन ब्राइटनेस, 2डी-3डी कनवर्जन के साथ 3डी, 3,20,000:1 का कंट्रास्ट, 2 एचडीएमआई-इनपुट, कंपोजिट, कंपोनेंट, वीजीए इनपुट, बैकलिट रिमोट, वजन 8.3 किलो. इसकी क़ीमत: 1,70,099 रुपये तय की गई है. ■

सन्नी का स्पेशल एडिशन

भारतीय बाज़ार में एक से बढ़कर एक शानदार कारों को पेश करने वाली जापान की प्रमुख कार निर्माता कंपनी निसान ने अपने मिड लेवल सिडान कार सन्नी कार के नए स्पेशल एडिशन को बाज़ार में पेश किया है. बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से लबरेज नई निसान सन्नी कई मायनों में अपने पिछले मॉडल से बेहतर है. कंपनी ने निसान सन्नी को नये स्पेशल एडिशन में नये और आकर्षक फीचर्स के साथ बाज़ार में पेश किया है.

निसान ने सन्नी स्पेशल एडिशन को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वैरिएंट में पेश किया है. कंपनी ने इस कार के इंटीरियर में परिवर्तन किया है, हालांकि इसके एक्सटीरियर में कंपनी ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है. नये और आधुनिक आकर्षक फीचर्स और तकनीकी से कंपनी एक बार फिर से भारतीय ग्राहकों को लुभाने की तैयारी कर रही है.

ग़ौरतलब हो कि निसान की यह कार भारतीय बाज़ार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही संस्करणों में उपलब्ध है, जिनमें कंपनी ने पेट्रोल वैरिएंट में 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है जो कि कार को 6,000 आरपीएम की शक्ति प्रदान करता है. इसके अलावा, डीजल वैरिएंट में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का के9केइंजन का प्रयोग किया है. ■

एचसीएल के एंड्रॉयड टैबलेट

एचसीएल ने एंड्रॉयड मार्केट में अपने तीन नए एंड्रॉयड टैबलेट लांच किए हैं. एंड्रॉयड के लेटेस्ट आईस्क्रीम सैंडविच ओए से लैस तीनों एचसीएल टैबलेट मॉडलों में 7 इंच की स्क्रीन के साथ 1 गीगाहर्ट प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ कनेक्टीविटी के सभी बेसिक ऑप्शन भी इनबिल्ड है. इनमें से एचसीएल मी वाई 3 मॉडल में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है, जबकि एचसीएल मी वी 1 में सिंगल सिम स्लॉट और यू 2 मॉडल में वाईफाई सपोर्ट मौजूद है. लेकिन यूजर एचसीएल यू 2 मॉडल में डॉन्गल की मदद से 3 जी इंटरनेट सर्विस का प्रयोग कर सकता है. एचसीएल मी यू 2 में फीचर 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, 1 जीबी रैम, 1 गीगाहर्ट एआरएम कार्टेक्स ए9 प्रोसेसर, माली 400 जीपीयू , 4 जीबी इंटरनल मेमोरी, 3000 एमएएच लीथियम बैटरी है. इसकी क़ीमत- 5,999 रुपये तय की गई है. दूसरा एचसीएल मी वी 1 में फीचर 7 इंच की स्क्रीन, 800 गुणा480 रेज्यूलूशन सपोर्ट, एंड्रॉयड आईस्क्रीम सैंडविच ओएस, 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज, 32 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी, 0.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वाईफाई, माइक्रोयूएसबी पोर्ट, 3.0 ब्लूटूथ सपोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, 3.0 ब्लूटूथ कनेक्टीविटी 3200 एमएएच बैटरी है. तीसरा एचसीएल मी वाई 3 में 7 इंच की स्क्रीन, 1024गुणा600 पिक्सल रेज्यूलूशन, 0.3 मेगापिक्सल सपोर्ट, एंड्रॉयड आईस्क्रीम सैंडविच ओएस, कार्टेक्स ए9 प्रोसेसर, 1 गीगाहर्ट स्पीड, 4 जीबी इंटरनल मेमोरी, 1 जीबी डीडीआर 3 रैम है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पारंपरिक खेलों को सहेजता शेखावाटी उत्सव

भारत विविध लोक संस्कृतियों का देश है. यहां कला संस्कृति के साथ-साथ पारंपरिक खेलों के भी विविध रूप हैं. लेकिन इन खेलों के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती आ खड़ी हुई है. शेखावाटी उत्सव जैसे आयोजन इन खेलों के वजूद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. देश की लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए पारंपरिक खेलों को बचाए रखना ज़रूरी है. इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए.

नवीन चौहान
navinchauhan@chauthiduniya.com

किसी भी संस्कृति के चार मुख्य अंग होते हैं. पहला है भाषा, दूसरा खानपान, तीसरा रीति-रिवाज, पहनावा और चौथा खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि पश्चिमी देशों के प्रभाव का असर देश की भाषा, खानपान और मनोरंजन के साधनों पर पिछले एक दशक में दिखा है. इस प्रभाव का सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण खेलों पर पड़ा. एक दौर था, जब गावों में लोग बड़े पैमाने पर तरह-तरह के खेल खेलते थे, लेकिन अब वह नदारद है. दरअसल, पीढ़ियों से खेले जाने वाले ये खेल बहुत ही लोकप्रिय होते थे. खेल का सामान स्थानीय संसाधनों से तैयार होता था. उदाहरण के लिए पुराने कपड़ों और रस्सी की मदद से गेंद बना ली जाती थी, जिसका उपयोग किसी भी खेल में हो सकता था. उस वक़्त उन खेलों की जड़ें देश में बहुत गहरी थीं. हर क्षेत्र के खेलों में वहां की सांस्कृतिक झलक कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाती थी. लेकिन दुख तो इस बात का है कि बदलते समय के साथ नए-नए खेलों को प्रोत्साहन मिलने की वजह से इन ग्रामीण खेलों की लोकप्रियता में भारी कमी आई है. युवाओं की इन खेलों में रुचि कम होने की वजह से कई स्थानीय खेल विलुप्त हो गए, तो कुछ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए. सच तो यह है कि व्यवसायिक और विदेशी खेलों मसलन क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन के कारण ग्रामीण संस्कृति का यह आधार स्तंभ लगभग चरमरा गया है. पुरातन भारतीय खेलों के लुप्त होने की वजह से गावों का पारंपरिक सामाजिक ढांचा कमज़ोर हो रहा है. ग़ौरतलब है कि पारंपरिक खेल लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ ज़रिया है, लेकिन इन खेलों के अस्तित्व के साथ ही लोगों और गांवों के बीच मेलमिलाप भी कम हो गया है.

18 साल पहले 1996 में मोरारका फाउंडेशन ने शेखावाटी की कला संस्कृति के प्रदर्शन के लिए शेखावाटी उत्सव की शुरुआत की. प्रारंभ में ही शेखावाटी के ग्रामीण खेलों को इस महोत्सव का हिस्सा इसलिए बनाया गया, ताकि ग्रामीण खेलों को न केवल इस उत्सव का हिस्सा बनाया जा सके, बल्कि इन खेलों की धूमिल होती पहचान भी इन्हें वापस दिलाई जा सके, वे सभी खेल जो इस क्षेत्र की कभी पहचान थे और बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, शेखावाटी की संस्कृति के अंग कहे जाने वाले खेलों सतौलिया, हरदड़ा, राउंडर बल्ला, लूणक्यार आदि को शेखावाटी महोत्सव का हिस्सा बनाया गया. आज 18 साल बाद राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लगभग 1000 स्कूलों के स्पोर्ट्स एक्टीविटी कैलेंडर में ये खेल शामिल हैं. यहां के बच्चों के बीच ये खेल एक बार फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं. सच तो यह है कि इन खेलों को धीरे-धीरे मान्यता भी मिल रही है. इन खेलों की ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं.

मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता ने बताया कि शेखावाटी उत्सव के पारंपरिक खेलों के संरक्षण के संदर्भ में केवल रिस्पांस को पैमाना माना जाए, तो अठारह साल पहले इन खेलों के आयोजन के लिए हमें तीन-चार टीमें जोड़ने में परेशानी होती थी, लेकिन अब तक़रीबन 5000 बच्चे इन खेलों में हर साल भाग लेते हैं. उन्होंने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए बताया कि शेखावाटी महोत्सव आधे दिन की गतिविधि से बढ़कर अब सात दिन के महोत्सव में बदल गया है. इसमें खेलों का एक महत्वपूर्ण योगदान है. शेखावाटी महोत्सव के आयोजन के बाद क्षेत्र के स्कूलों में क्रिकेट, फुटबॉल के साथ-साथ पारंपरिक खेलों की टीमें भी बनने लगी हैं. पारंपरिक खेल अब शेखावटी क्षेत्र के स्पोर्ट्स कैलेंडर का हिस्सा हैं. शेखावाटी उत्सव के आयोजन में इन खेलों की वजह से लोग ख़ुद को इस आयोजन से जुड़ा हुआ मानते हैं. इन खेंलों को एक बार फिर से रोज़ाना खेले जाने वाले खेलों में जगह मिल गई है. स्थानीय खेलों को क्रिकेट जैसे बड़े खेल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है. देश में पहले से दसवें पायदान पर क्रिकेट ही क़ाबिज़ है, इस कारण हॉकी और फुटबॉल जैसे खेल भी दसवें-ग्यारहवें पायदान पर पहुंच गए हैं.

मोरारका फाउंडेशन के खेल प्रभारी जयचंद खीचड़ ने कहा कि सरकार को इन खेलों के संरक्षण के लिए इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को पारंपरिक खेलों के बारे में जानकारी मिल सके और वे पारंपरिक खेलों से जुड़ सकें. सरकार को इन खेलों को अधिकृत खेलों की सूची में शामिल करना चाहिए, जिससे कि पारंपरिक खेलों के संरक्षण और विकास की योजनाएं बन सकें. अब तक ये खेल ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधन थे. इन खेलों की अब तक कोई निश्चित नियमावली नहीं है. हमने ग्रामीण खेलों की नियमावली बनाने की कोशिश की है, जिससे कि इन खेलों की बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें . उन्होंने यह भी कहा कि बिना नियमावली के पारंपरिक खेलों का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं बन सकेगा. सबसे पहले इन खेलों को वापस उसके पैरों पर खड़ा करना होगा. इसके बाद ही इनकी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सकेगी. इन खेलों को और रुचिकर बनाकर ही नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जा सकता है, तभी इन खेलों का उद्धार हो सकेगा.

शेखावाटी उत्सव में आए दुद्दना का बास डोमरा गांव के दिनेश दत्तुलरिया ने बताया कि इन खेलों को गांव में बच्चे खेलते हैं. बड़ी उम्र के लोग इन खेलों को ज़्यादा नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका दर्शक की होती है. छुट्टियों के दौरान ही लोग इन खेलों को गांवों में खेलते नज़र आते हैं. शेखावाटी उत्सव की वजह से बच्चे पारंपरिक खेलों में रुचि लेने लगे हैं. नवलगढ़ के अब्दुल रहमान ने बताया कि नवलगढ़ जैसे क़स्बे में भी बच्चे राउंडर बल्ला और सतौलिया जैसे खेल खेलते दिखाई पड़ते हैं. घीसा की दाणी दोमड़ा गांव के विक्रम सिंह मैहला ने कहा कि बच्चों को सतौलिया, लूणक्यार और राउंडर बल्ला जैसे खेल खेलता देख हम अपने बचपन को याद कर लेते हैं.

दरअसल, अब सरकार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के प्रसार के लिए गंभीर दिखाई नहीं देती है. खेल राज्य सूची का विषय है. राज्य सरकारें न ही गावों में खेलों के मैदान बना पा रही हैं और न ही संस्कृति का हिस्सा रहे खेलों को संरक्षित कर पा रही हैं. गांवों में खेलों के मैदान अब नहीं रह गए हैं. गोचर भूमि ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का मैदान थीं. कम होती गोचर भूमि भी इन खेलों के विलुप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण है. ग़ौरतलब है कि सरकारी महकमों द्वारा ज़मीनों की बंदरबाट किए जाने की वजह से ही गावों में खेल के मैदान को लेकर ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना और पंचायत युवा खेल क्रीड़ा योजना के अंतर्गत गांवों में खेल के मैदान बनाए जाने के प्रावधान रखे हैं, लेकिन ज़मीन की कमी की वजह से उनका निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है. यदि खेल मंत्रालय बड़े खेलों के साथ-साथ स्थानीय खेलों के लिए भी बजट में एक हिस्से का प्रावधान करे, तो इसमें दो राय नहीं है कि इन खेलों को बचाए रखने के साथ ही साथ उन्हें लोकप्रिय भी बनाया जा सकता है. ■

राउंडर बल्ला

यह शेखावाटी क्षेत्र में एक ज़माने में मशहूर खेल रहा है. यह खेल बेस बॉल से मिलता जुलता है. बेस बॉल और राउंडर बल्ले के बीच मूलभूत अंतर यह है कि इसमें बल्लेबाज़ को ख़ुद ही गेंद उछालनी होती है और उसे मारना होता है, जबकि बेस बॉल में गेंदबाज़ गेंद को बल्लेबाज़ की ओर फेंकता है और उसके बाद बल्लेबाज़ उस पर शॉट खेलता है. दोनों टीमों में सात-सात खिलाड़ी होते हैं. रनों के आधार पर ही हार जीत का निर्णय होता है. रन लेने का तरीक़ा भी बेस बॉल से मिलता जुलता है. इसमें गेंद को मारने के लिए बल्लेबाज़ को तीन चांस मिलते हैं. यदि उन तीनों चांस में बल्लेबाज़ रन बनाने में नाकामयाब होता है, तो उसे आउट क़रार दे दिया जाता है. गेंद को मारने के बाद रन लेने से पहले बल्ले को बल्लेबाज़ी के लिए बने घेरे में छोड़ना होता है. यदि खिलाड़ी ऐसा नहीं करता है, तब भी वह आउट हो जाता है. एक वर्ग के कोने पर खिलाड़ी खड़े होते हैं. वर्ग का एक चक्कर एक खिलाड़ी द्वारा पूरा करने पर एक रन बनता है. यदि बल्लेबाज़ गेंद को मारता है और फील्डर उसे कैच कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में यदि बल्लेबाज़ रन लेने के लिए बल्ला और बल्लेबाज़ी घेरा छोड़ देता है, तो वह आउट हो जाता है. यदि वह बल्ले के साथ सुरक्षा घेरे में रहता है, तो वह सुरक्षित रहता है. लेकिन अपनी बल्लेबाज़ी के तीनों चांस में यदि कैच हो जाता है, तब वह आउट हो जाता है. ■

हरदड़ा

यह भी दो टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है. दोनों टीमों में सात सात खिलाड़ी होते हैं. इस खेल में दो ईंटों के ऊपर बांस का एक डंडा रखा जाता है. दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी कपड़े से बनी गेंद से निश्चित बारी में बांस को गिराता है. जो भी टीम ज़्यादा बार बांस को गिराने में सफल होती है, वह टीम जीत जाती है. ■

लूणक्यार

इस खेल में भी दो टीमों में सात खिलाड़ी होते हैं. इस खेल को खेलने के लिए आठ मीटर व्यास का गोला बनाया जाता है और उसके अंदर सात मीटर व्यास का गोला बनाया जाता है. गोलों के केंद्र में नमक या मिट्टी रखी जाती है. प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को बाधाओं को पार कर नमक तक पहुंचना होता है. विरोधी टीम उन्हें ऐसा करने से रोकती है. ऐसे में यदि वह पकड़ा जाए, तो आउट हो जाता है. टीमों को नंबर के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है. ■

सतौलिया

इस खेल में भी दोनों टीमों में सात-सात खिलाड़ी होते हैं. सात पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर सितौलिया बनाया जाता है. एक टीम के खिलाड़ी उसे गेंद से मारकर गिराते हैं और उसे वापस जमाने की कोशिश करते हैं. विपक्षी टीम उन्हें ऐसा करने से रोकती है. जो भी खिलाड़ी सतौलिया को जमा रहा होता हो, उसे पूरा करने से पहले अगर उसे गेंद लग जाती है, तो वह आउट हो जाता है. जो भी टीम ज़्यादा बार सतौलिया गिराकर उसे वापस जमाने में कामयाब होती है, वही विजेता होती है. ■

जब दिल ही टूट गया...

प्रियंका प्रियम तिवारी feedback@chauthiduniya.com

सत्तर और अस्सी के दशक में ग्लैमर का पर्याय मानी जाने वाली अभिनेत्री ज़ीनत अमान इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चे में हैं. कुछ टेलीविजन चैनलों और अख़बारों ने तो उनकी शादी तक एक 36 वर्षीय व्यवसायी से करा दी. इन अफवाहों के बाद जीनत को मीडिया से रूबरू होना पड़ा. अपनी शादी की ख़बर का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर काफ़ी दुख है कि उनके बारे में मीडिया में ग़लत अफवाहें फैलाई जा रही हैं. जीनत ने फिल्म इंडस्ट्री में एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. जिस जमाने में अभिनेत्रियां साड़ी और लहंगे में दिखाई देती थीं, उस दौरान जीनत ने शॉर्ट्स ड्रेसेज एवं बिकनी पहन कर तहलका मचा दिया था. जीनत अमान ने 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में क़दम रखा. वह फिल्मों में छोटे-मोटे रोल ज़रूर कर रही थीं, लेकिन उन्हें सफलता मिली, देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से. यह फिल्म वर्ष 1971 में रिलीज हुई. फिल्म में जीनत अमान ने देव आनंद की बहन की भूमिका निभाई थी. जीनत ने राज कपूर की सुपर-डुपर हिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पारदर्शी साड़ी पहनीं और अभिनेता शशि कपूर के साथ किसिंग सींस भी दिए थे, वहीं अभिनेता फिरोज ख़ान के साथ फिल्म कुर्बानी में काफ़ी हॉट सींस दिए. फिल्म के बहुत सारे दृश्यों में वह केवल बिकनी पहनी नज़र आईं. उन्होंने फिल्म इंसाफ का तराज़ू में अभिनेता राजबब्बर के साथ भी काफ़ी इंटीमेंट सींस दिए.

जीनत उस जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री थीं. उनकी ख़ूबसूरती और उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था. उस जमाने के फिल्मकार उनके दीवाने थे. चाहे वह देव आनंद हो या राजकपूर उनकी बोल्डनेस के सभी कायल थे. उन्होंने कभी सस्ती लोकप्रियता नहीं बटोरी और इसीलिए उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा को बनाए रखा. हालांकि उनके जीवन में रिश्तों को लेकर एक अजीब कश्मकश बनी रही. वह प्यार में ख़ुद को समर्पित करने वाले लोगों में से थीं. वहीं उनका व्यवहार शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, वह संयम नहीं रख पाती थीं. अपने इस व्यवहार के कारण हीं वह ज़्यादा समय तक किसी रिश्ते में बंधकर नहीं रह पाईं. उन्होंने प्यार किया और शादी भी की, लेकिन दोनों ही रिश्ते बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएं.

लेडी किलर देव आनंद को जीनत से आत्मीय अनुराग था. उन्होंने वर्ष 2007 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वह जीनत के लिए गहरी आत्मीयता महसूस करते थे. पर देव साहब ने उस वक्त चुप रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की सफलता के बाद जीनत की नज़दीकियां राजकपूर से बढ़ रही थीं और उस समय राजकपूर उन्हें लेकर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की तैयारी भी कर रहे थे. देव आनंद ने लिखा था कि जीनत एक ख़ुशमिज़ाज इंसान हैं. सच तो यह है कि अंजाने में ही मैंने उनके प्रति असीम प्यार महसूस किया. हम दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे. राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म इश्क, इश्क, इश्क के प्रीमियर पर इनवाइटेड ऑडिएंस के सामने ही जीनत अमान को किस कर लिया, इससे मुझे काफी जलन महसूस हुई. वह अपने प्यार का इज़हार जीनत से करना चाहते थे, लेकिन उसी दरम्यान देव ने एक पार्टी में देखा कि राज कपूर नशे में धुत्त थे और जीनत उनकी बाहों में थी. इन घटनाओं के संदर्भ में देव आनंद ने लिखा कि मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था. फिर उन्होंने कभी भी जीनत से अपने प्यार का इज़हार नहीं किया कि वह उनके जीवन में क्या महत्व रखती थीं.

देव लिखते हैं कि आप किसी के रास्ते में नहीं आ सकते. शायद मैं जीनत से थोड़ी ईमानदारी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यही तो क़ायदा है, ज़िंदगी नाराज़गी से रुक नहीं जाती. कहीं और ले जाती है. हालांकि देवानंद ने यह भी स्वीकारा था कि उन्होंने जीनत को चाहा, लेकिन जीनत ने उन्हें कभी नहीं चाहा. यह एकतरफा मोहब्बत थी.

देव आनंद के प्यार को तो जीनत ने नहीं अपनाया, लेकिन अभिनेता संजय खान के साथ वह काफ़ी दिनों रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन दु:ख तो इस बात का है कि यह रिश्ता भी शादी में तब्दील नहीं हो पाया. ग़ौरतलब है कि उनकी संजय खान से मुलाक़ात जैसलमेर में वर्ष 1980 में फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर हुई शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया. उस समय वह स्टार थीं और इंडियन सिनेमा की हॉटेस्ट अभिनेत्रियों में शुमार भी थीं, जबकि संजय खान तीन बच्चों के पिता थे. बाद में इस रिश्ते का दुखद अंजाम हुआ. जीनत और संजय के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गए, जिसके कारण दोनों अलग हो गए. ऐसा भी कहा जाता है कि एक झगड़े के दौरान संजय ने जीनत के साथ मारपीट की, जिससे जीनत के चेहरे पर काफ़ी चोटें आईं और उनकी एक आंख भी ख़राब हो गई. फिर अचानक, जीनत की ज़िंदगी में अभिनेता मज़हर ख़ान आ गए, जिनसे जीनत ने साल 1985 में शादी रचा ली. यह रिश्ता भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका. इस दौरान मीडिया में ख़बरें आती रहीं कि मज़हर को ड्रग्स लेने की बुरी आदत है, जिसके कारण जीनत हमेशा मजहर से नाराज़ भी रहती थीं. कभी-कभी मज़हर जीनत पर काफ़ी अत्याचार भी करते थे, उन्हें बुरी तरह मारते-पीटते थे. इस शादी से जीनत को दो बेटे 26 वर्षीय अजान और 23 वर्षीय जहान हैं. वर्ष 1998 में मज़हर की कैंसर से मौत हो गई. ■

जीनत का फिल्मी सफ़र

जीनत का जन्म 19 नवंबर, 1951 को हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में शुरू की. फिर मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफ़िक चुनी गईं. उन्होंने 70 के दशकमें छोटे-मोटे रोल्स के साथ अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया. वर्ष 1972 में देव आनंद की फ़िल्म हरे रामा हरे कृष्णा उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म ने अचानक उन्हें स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी. जीनत ने अपने करियर के शुरूआती दिनों में जहां किशोर कुमार और देव आनंद के साथ काम किया तो वहीं धर्मेंद्र, संजय खान, संजीव कपूर शम्मी कपूर, अशोक कुमार के साथ भी काम किया. उन्होंने उस समय के सुपर स्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया तो उनकी जगह लेने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी सफल जोड़ी बनाई, और कई हिट फिल्में दी. उन्होंने दो शदी के महानायकों के साथ काम किया. ■

कुछ अलग किरदार की चाहत

मनोज ने कहा है कि वह एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि उनसे पहले अनिल कपूर और इरफान खान भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं.

गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करने वाले मनोज बाजपेयी को हॉलीवुड से इन्विटेशन आया है. कब किसकी किस्मत बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान के कैरेक्टर ने उन्हें एक नई पहचान दी है. मनोज ने कहा है कि वह एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि उनसे पहले अनिल कपूर और इरफान खान भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकेहैं. ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर आंग ली की किसी फिल्म का पार्ट बनने का सपना देख रहे मनोज आने वाले समय में नीरज पांडेय की स्पेशल 26 में नज़र आएंगे. मनोज ने कहा कि उन्हें रोमांटिक किरदार पसंद नहीं और शायद उन पर सूट भी नहीं करते. मनोज कुछ अलग हट कर किरदार करना पसंद करते हैं और उन्हें उनकी पसंद का किरदार मिल भी रहा है. ■

अजय की पसंद तमन्ना

अजय देवगन 1980 में बनी फिल्म हिम्मतवाला के रिमेक में लीडिंग रोल में हैं. इस फिल्म में उनके अपोजिट हैं साउथ की अभिनेत्री तमन्ना. अजय इस फिल्म में रेट्रो लुक में नज़र आएंगे. एक्शन हीरो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजय देवगन इन दिनों डांसिंग और कॉमेडी में भी किस्मत आजमा रहे हैं. सच तो यह है दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं. अजय छोटे पर्दे पर भी काम करना चाहते हैं. हाल ही में इच्छा ज़ाहिर की कि वह टेलीविजन पर जज बनना चाहते हैं. हालांकि वह छोटे पर्दे पर कई बार दिख चुके हैं. फिल्म हिम्मतवाला में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा भी दिखेंगी. वह इस फिल्म में डिस्को गाने में डांस करती नज़र आएंगी. इस फिल्म की हिरोइन तमन्ना भाटिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की थी, लेकिन बॉलीवुड में कोई खास कमाल ना दिखा पाने के बाद तमन्ना ने दक्षिण की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और वहां उन्हें सफलता मिली. उन्होंने पादिकथवान और अयान जैसी सफल फिल्में दीं. साजिद खान को इस फिल्म के लिए तमन्ना का नाम अजय ने सुझाया. फिल्म पइय्या से स्टार बनीं तमन्ना अपने सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड से देश में जाना -पहचाना चेहरा बन गईं. तमन्ना इस समय रेबेल, कैमरामैन गंगा थो रामबाबू, भाले थम्मूदू और बॉलीवुड फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग में व्यस्त हैं. उनकी अगली तमिल फिल्म ये इंद्राल काधाल एनबेन है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

दि अटैक ऑफ 26/11

काफ़ी समय से रामगोपाल वर्मा की फिल्में एक के बाद एक पिट रही हैं. अब मुंबई के आतंकवादी हमले पर रामू की फिल्म दि अटैक ऑफ 26/11 1 मार्च 2013 को रिलीज हो रही है. रामू को उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत फिर से खुल जाएगी. फिल्म को डायरेक्ट न केवल रामगोपाल वर्मा ने किया है, बल्कि पटकथा भी उन्होंने ही लिखी है. जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं पराग सांघवी. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं नाना पाटेकर, गणेश यादव और संजीव जायसवाल. यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल के बैनर तले बनी है. फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर से होती है. नाना पाटेकर फिल्म में मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश मारिया की भूमिका में हैं, जो सबको अटैक के बारे में जानकारी देता है. वह सबको बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान से इस अटैक के लिए आतंकवादियों को भारत में एंट्री दी गई और किस तरह से भारत में आकर उन्होंने धीरे-धीरे करके इस अटैक की प्लानिंग की. इस फिल्म में कसाब की भूमिका जमशेदपुर (झारखंड) के संजीव जायसवाल ने निभाई है. लंबे समय तक थिएटर से जुडे संजीव को क़रीब 300 लोगों में स्क्रीन टेस्ट के बाद चुना गया. इस फिल्म में उन 60 घंटों की कहानी है, जब आतंकियों ने ताज में लोगों को बंधक बना लिया था. इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग असली लोकेशंस पर की गई है, यह फिल्म देखकर साफ़ पता चलता है कि इस घटना की काफ़ी अच्छी रिसर्च की गई है. हालांकि इस खौफनाक हादसे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं. उल्लेखनीय है कि इस घटना को चार वर्ष हो गए हैं और अब तक अलग-अलग नामों से छह फिल्में इस विषय पर बन चुकी हैं. ■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

25 फरवरी-03 मार्च 2013

www.chauthiduniya.com

कल्याणपुर उपचुनाव

विपक्ष की अग्नि परीक्षा

कल्याणपुर का उपचुनाव लोजपा एवं राजद गठबंधन का भविष्य तय कर देगा. लालू प्रसाद अगर अपने वोट बैंक को लोजपा के पक्ष में डलवाने में असफ़ल रहे तो यह तय मानिए कि गठबंधन का रास्ता काफ़ी कठिन हो जाएगा. उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अपनी ताक़त का अहसास कराने का यह उपचुनाव एक अच्छा मौका है. अगर वह ऐसा कर पाए, तो फिर बिहार की राजनीति एक नई करवट लेगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी. हालांकि अगर बाजी हाथ से निकल गई, तो फिर नीतीश कुमार काफ़ी आगे निकल जाएंगे और विपक्ष के इन सूरमाओं के सामने हाथ मलने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा.

सरोज सिंह feedback@chauthiduniya.com

कल्याणपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 फरवरी को वोट डाले जाने हैं. इस उपचुनाव में नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन विपक्षी नेताओं की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और अगर ये नेता इस भीड़ को वोट में नहीं तब्दील कर पाए, तो आख़िरकार भद्द तो उनकी ही पिटेगी. लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ख़ुद दावा कर रहे हैं कि उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है. पर सवाल यह है कि कल्याणपुर में जदयू की जीत हो गई तो फिर विपक्ष के इन दिग्गज नेताओं के दावों का क्या होगा. दरअसल, कल्याणपुर में हर लिहाज से लोजपा एवं राजद की संयुक्त उम्मीदवार फ़ायदे में हैं, लेकिन विपक्ष के इन सूरमाओं के अकुशल प्रबंधन से परेशानी हो रही है. राजद और लोजपा के नेता कल्याणपुर में कम और पटना में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि जदयू की टीम घर-घर जाकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही है.

गौरतलब है कि चुनावी मैदान में जदयू के अधिकांश मंत्री एवं विधायक सहित कार्यकर्ता पंचायत एवं टोला भ्रमण करने में लगे हुए हैं. वोटरों को अपने क़ब्ज़े में लेने के लिए जाति समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्री अपने मंत्री और विधायकों को जाति विशेष के तहत भेजने का काम कर रहे हैं. महादलित नेताओं को महादलित टोले में, वहीं मुस्लिम विधायक को मुस्लिम इलाक़े में, सवर्ण विधायक-मंत्रियों को सवर्ण के टोले में एवं कुशवाहा, यादव के टोले में इस जाति के विधायक मंत्रियों के द्वारा जदयू प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटारों को रिझाने का काम हो रहा है. दूसरी तरफ़ ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अपनी ताक़त अंतिम क्षणों के लिए बचा कर रखी हुई है, लेकिन यह रणनीति भारी भी पड़ सकती है. इस तरह के फीडबैक के बाद लोजपा एवं राजद के नेताओं ने कल्याणपुर का दौरा तेज कर दिया है. विपक्ष के सारे नेता यह मान कर चल रहे हैं कि अनुकूल हालात में भी अगर यह सीट हाथ से निकल गई, तो फिर नीतीश कुमार को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. ऐसे हालात में जदयू नेताओं की यह बात साबित हो जाएगी कि इन नेताओं में भीड़ को वोट में बदलने की ताक़त ही नहीं है. लोग केवल चुनावों में उनकी मसखरी के लिए जाते हैं, लेकिन असल में वे वोटर नीतीश कुमार के ही हैं. अभी लालू प्रसाद, रामविलास पासवान एवं उपेंद्र कुशवाहा को पटना में अपनी ताक़त अलग-अलग रैलियों के माध्यम से दिखानी है. कल्याणपुर की हार इन रैलियों पर बुरा असर डालेगी, यह तय है अगर जीत हो गई, तो यह बात साफ़ हो जाएगी कि जनता अब बदलाव की तरफ़ देख रही है. इसलिए जो पार्टी विकल्प देने की स्थिति में होगी, जनता उसका साथ देगी. ऐसे में यह ज़रूरी है कि अगर जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाई रखनी है, तो इस सीट को हर हाल में जीतना ही होगा. जातीय समीकरण के हिसाब से देखें, तो कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में महादलितों का वोट बैंक लगभग 30000, तो दलित का वोट है लगभग 20000. वहीं जदयू एवं कांग्रेस के प्रत्याशी महादलितों में राम जाति से आते हैं और इन दोनों उम्मीदवारों की निगाह महादलित एवं सवर्णों के वोट पर टिकी है. जदयू अपनी लड़ाई को लोजपा गठबंधन से आमने-सामने की मान रहा है. कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुशवाहा वोटों की संख्या लगभग 40 हज़ार, सवर्ण-50 हज़ार, यादव-30 हज़ार और मुसलमान 20 हज़ार के आस पास है. जदयू राजद एवं लोजपा को अपने-अपने परंपरागत वोटों पर पूरा भरोसा है. इसमें जोड़ने तोड़ने वाली बात यह है कि निर्णायक कुशवाहा एवं अतिपिछड़ा वोटों की कितनी हिस्सेदारी यह दल अपने खाते में डाल पाते हैं. भूमिहार वोटों पर भी इन पार्टियों की नज़र है और कोशिश हो रही है कि इस निर्णायक वोट को अपने खाते में किया जाए. सबसे बड़ा दांव कुशवाहा वोट पर लगा है. जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो व्यवहार किया है, इसे लेकर इस समाज में बेहद नाराज़गी है. अब यह उपेंद्र कुशवाहा पर ही निर्भर करता है कि वह इस समाज को क्या संदेश देते हैं. खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के वोट को लोजपा प्रत्याशी को दिलाने में सफ़ल रहे, तो यह मान लिया जाएगा कि न केवल अपने समाज के लोगों को जुटाने, बल्कि इसे वोट में बदलने की ताक़त भी उपेंद्र कुशवाहा रखते हैं. उनके इस कदम से उनका क़द प्रदेश स्तर पर काफ़ी बढ़ेगा और तीन मार्च को गांधी मैदान में होने वाली रैली पर भी इस जीत का असर पड़ेगा. हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस उदार एवं रणनीतिक क़दम के कारण राजद एवं लोजपा के लोग भी तीन मार्च की रैली को खुले दिल से समर्थन करें. यह साफ़ है कि घोषित तौर पर कोई नेता अभी इस तरह का ऐलान नहीं करेगा, लेकिन राजनीति में बहुत सारे फ़ैसले परदे के पीछे भी होते हैं. देखना होगा कि कल्याणपुर में जीत का परचम लहराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान क्या निर्णय लेते हैं. जदयू प्रवक्ता निरंजन कुमार पप्पू दावा करते हैं कि कुशवाहा वोटरों का पूरा समर्थन पार्टी को है और कल्याणपुर में जदयू प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि रोड मैप से दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हो गई है. इसके अलावा नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास की नीति से हर समाज एवं वर्ग का समर्थन जदयू प्रत्याशी को मिल रहा है.

दूसरा निर्णायक वोट भूमिहारों का भी है. ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद से ही यह समाज जदयू से नाराज़ चल रहा है. इस समाज की नाराज़गी किस हद तक है, इसका पहला टेस्ट कल्याणपुर उपचुनाव में हो जाएगा. यही वजह है कि दोनों ही तरफ़ से भूमिहार नेताओं की बड़ी फौज कल्याणपुर का चप्पा-चप्पा छान रही है. लोजपा नेता सूरजभान सिंह कहते हैं कि यह समाज अब नीतीश कुमार के झांसे में आने वाला नहीं है. कल्याणपुर में लोजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत हो रही है. लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान एवं रामचंद्र पासवान अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि एनडीए गठबंधन सिर्फ़ बाईस्कोप दिखाने का काम कर रही है. दलित, महादलित, सवर्ण, यादव, कुशवाहा, वैश्य, सहनी एवं मुसलमान सभी जाति के लोगों का वोट लोजपा के पक्ष में पड़ेगा. कांग्रेस भी यहां रेस में आने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन संगठन की कमजोरी इसे खल रही है. देखना है कि कांग्रेस यहां अपनी प्रतिष्ठा किस तरह बचा पाती है. यहां असली परीक्षा तो लालू प्रसाद, रामविलास पासवान एवं उपेंद्र कुशवाहा की होनी है. देखना है कि वह इस निर्णायक परीक्षा में पास होते हैं या फेल. ■

दूसरा निर्णायक वोट भूमिहारों का भी है. ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद से ही यह समाज जदयू से नाराज़ चल रहा है. इस समाज की नाराज़गी किस हद तक है, इसका पहला टेस्ट कल्याणपुर उपचुनाव में हो जाएगा. यही वजह है कि दोनों ही तरफ़ से भूमिहार नेताओं की बड़ी फौज कल्याणपुर का चप्पा-चप्पा छान रही है. लोजपा नेता सूरजभान सिंह कहते हैं कि यह समाज अब नीतीश कुमार के झांसे में आने वाला नहीं है.

चिकित्सकों एवं बीसीएम को महीनों से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, आशाओं को टीए-डीए ही नहीं मिल रहा है और न ही ज़रूरी स्वास्थ्य उपकरण ही ख़रीदे जा रहे हैं.

एनआरएचएम की हवा निकली

दरभंगा

जयशंकर पांडेय feedback@chauthiduniya.com

इन दिनों ज़िला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस), दरभंगा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की सारी योजनाएं कैसे फलीभूत हों और इससे आम जनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरह पहुंचे, इसकी चिंता यहां किसी को नहीं है. वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और अब तक डीएचएस के पार्ट-बी में राज्य स्वास्थ्य समिति (एसएसएच) पटना से एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली है. इस कारण इस मद से दी जाने वाली करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य सुविधाएं ज़िले में बंद पड़ी हैं. चिकित्सकों एवं बीसीएम को महीनों से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, आशाओं को टीए-डीए नहीं मिल रहा है और न हीं ज़रूरी स्वास्थ्य उपकरण ही ख़रीदे जा रहे हैं. दरभंगा ज़िले को इस कार्य के लिए बतौर सालाना बजट 14 करोड़, 70 लाख रुपये मिलना था.

स्वास्थ्य विभाग में ऐसे विपरीत हालात पैदा करने के लिए इकलौता ज़िम्मेदार हैं, संविदा कर्मी ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) सुधांशु नारायण लाल. इस मामले में उन पर कार्रवाही करने के बजाए उनकी सेवा विस्तार कैसे हो, इस पर सिविल सर्जन डॉ. उदय कुमार चौधरी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इसके लिए वह राज्य स्वास्थ्य समिति पटना को भी चकमा दे रहे हैं. इधर डीपीएम के कारण न केवल महक़मे की भद्द पिट रही है, बल्कि ज़िले की रैंकिंग भी गिर गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने डीपीएम को अविलंब बर्खास्त करने और उनकी भूमिका की जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद भी सीएस डीपीएम के कार्य को संतोषजनक बता रहे हैं और इसका प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं. इतना ही नहीं, विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने भी डीपीएम पर कई आरोप लगाते हुए प्रधान सचिव से शिकायत की थी और कार्रवाही का भी अनुरोध किया था. सिंह ने जिन अनियमितताओं और विसंगतियों को उठाया था, उसका सीएस एवं डीपीएम ने कोई जवाब नहीं दिया. सिर्फ़ खानापूरी की. यहां रणनीति के तहत [illegible] पत्थर भेजकर झुनझुना थमा दिया गया है. डीपीएम की कार्य-प्रणाली को लेकर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी संतोष कुमार मल्ल ने खासी तल्ख टिप्पणी की थी और उन्हें सावधान रहने के लिए चेताया भी था. अक्सर अपनी कारगुज़ारियों के कारण चर्चा में रहने वाले डीएचएस के ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) सुधांशु नारायण लाल को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अविलंब बर्खास्त करने का निर्देश कार्यपालक निदेशक को दिया था, बल्कि उनके ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका की भी जांच करने को कहा गया था. (ज्ञापांक 466-एसएच-20.9.12) इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक गंगा कुमार ने भी अपने प्रतिवेदन में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर कार्यकारी एजेंसी बदलने के मुद्दे पर डीपीएम को कड़ी चेतावनी (ज्ञापांक 7476-5.9.12) सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह कहते हुए दी थी कि वे अपने कर्तव्यों को अमली जामा पहनाने में असफल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने अक्टूबर में राज्य के सभी ज़िलों के ज़िला कार्यक्रम प्रबंधकों की बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने कर्तव्य को ठीक से पालन न करने के लिए डीपीएम लाल को एक सप्ताह का वेतन काटने का निर्देश दिया था. (ज्ञापांक 9058-30.10.12) [illegible] की कार्यप्रणाली के ख़िलाफ़ विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने भी प्रधान सचिव से लिखित शिकायत गत अक्टूबर के पहले सप्ताह में की थी. इसमें लिखा गया था कि आयुष चिकित्सकों, बीसीएम, एएनएम, डाटा ऑपरेटरों तथा पीएचसी के जेनरेटर संचालकों को महीनों से भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि रोगी कल्याण समितियों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के रख-रखाव के लिए डीएचएस राशि मुहैया क्यों नहीं करा रही है, जबकि सरकार ऐसे भुगतान में प्राथमिकता देने को कहती है. सारी अनियमितताओं के लिए [illegible] जांच कर यह बताने का अनुरोध किया था कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से नहीं चलने देने के लिए कौन-कौन ज़िम्मेदार हैं. [illegible] प्रधान सचिव ने सारी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कार्यपालक निदेशक को [illegible] लिखा. इसके बाद कार्यपालक निदेशक ने पत्रांक 9217-5.11.12 के ज़रिए सिविल सर्जन को लिखे पत्र में निर्देशित किया कि विधान पार्षद सिंह को आयुष चिकित्सकों, बीसीएम, एएनएम और डाटा ऑपरेटरों को भुगतान में हो रहे विलंब से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएं, साथ ही डीपीएम लाल की भूमिका की भी जांच कराई जाए. कार्यपालक निदेशक ने 15 नवंबर से 12 नवंबर तक एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन की भी सीएस से मांग की थी, ताकि डीपीएम के मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके. उल्लेखनीय है कि सीएस ने विधान पार्षद सिंह द्वारा उठाए गए सवालों का बिंदुवार जवाब नहीं दिया और न ही डीपीएम लाल की भूमिका की जांच कराई, बल्कि एक पत्र तैयार कर राज्य स्वास्थ्य समिति पटना को ठगने और भरमाने का भरसक प्रयास ज़रूर किया. 26 दिसंबर, 2012 को एसएचएस को लिखे अपने पत्रांक 3997 की मार्फ़त सीएस ने डीपीएम लाल के कार्यकलापों को संतोषप्रद बताया, साथ ही सीएस ने लिखा कि डीपीएम की संविदा अवधि 14.10.12 को ही समाप्त हो चुकी है. [illegible] हस्ताक्षर करने के अधिकारी हैं. यानी सेवा विस्तार की आधिकारिक स्थिति में ही डीपीएम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस विसंगति से सीएस को कोई लेना-देना नहीं है. कहा जा रहा है कि लिखित सूचना देकर सीएस ने अपना पक्ष मजबूत कर लिया है. अब सवाल यह उठता है कि डीपीएम को लेकर प्रधान सचिव कार्यपालक निदेशक, अपर कार्यपालक निदेशक, डीएम प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं. सीएस वरिष्ठ हाकिमों के आदेशों को धत्ता बताते हुए डीपीएम को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यह जानते हुए कि डीपीएम की कारगुजारियों के कारण ही वित्तीय साल 2012-13 में एसएचएस, पटना से डीएचएस, दरभंगा को पार्ट-बी में एक पैसा भी नहीं मिला, जबकि इस मद में पूरे साल का बजट करोड़ों में है. यानी इतनी बड़ी राशि से दरभंगा का स्वास्थ्य महक़मा वंचित रह गया है. ऐसे में स्वाभाविक है कि पार्ट-बी की राशि से चलने वाली सारी योजनाएं यहां महीनों से बंद हैं. आयुष चिकित्सकों, बीसीएम, डाटा ऑपरेटरों समेत कई कर्मियों को मानदेय का भुगतान महीनों से नहीं हो रहा है और न ही आशा दिवस पर आशाओं को टीए-डीए ही मिल रहा है. इस कारण प्रखंड रोगी कल्याण समिति एवं प्रत्येक पीएचसी को रोगी कल्याणार्थ एवं निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों के लिए दी जाने वाली लाखों की सालाना राशि इस साल डीएचएस दरभंगा द्वारा नहीं दी गई है. इतना ही नहीं निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण ख़रीदारी के लिए डीएचएस दरभंगा को 39 लाख, 50 हज़ार रुपये आंवटित किए गए थे, लेकिन एसएचएस पटना ने यह कहते हुए यह राशि विमुक्त नहीं की. पार्ट-बी में उनके यहां पहले से ही यह राशि उपलब्ध है, जबकि सच्चाई यह है कि डीएचएस में इस मद में एक कौड़ी भी नहीं बची है. इसी क्रम में यह भी बताना ज़रूरी है कि क़रीब 77 लाख में आशा दवाई किट की ख़रीदारी डीएचएस द्वारा कर ली गई. इसे लेकर पार्टी को भुगतान के लिए तत्कालीन डीएचएस अध्यक्ष सह जिलाधिकारी आर लक्ष्मण ने मार्च 2011 में ही आदेश दिया था, लेकिन भुगतान अभी तक लंबित है. इसका भी भुगतान पार्ट-बी से ही होना है. ऐसी ही कई अनियमितताओं के चलते डीपीएम लाल के कारण डीएचएस की स्टेट में भद्द पिट रही है और काग़ज़ी घोड़ा दौड़ा कर सीएस डॉ. चौधरी डीपीएम को सेफ मोड में रखे हुए हैं और सीएस डॉ. चौधरी डीपीएम को क्लीन चिट दिए हुए हैं. उल्लेखनीय है कि सीएस डॉ. उदय कुमार चौधरी क़रीब 17-18 वर्षों से दरभंगा ज़िले में ही किसी न किसी पद पर आसीन रहे हैं. वह जुगाड़ के ज़रिए अपना तबादला रुकवाते रहे हैं. इसी तरह सुधांशु नारायण लाल भी छह साल से डीएचएस, दरभंगा में डीपीएम के पद पर कार्यरत हैं. दोनों की जुगलबंदी यहां चर्चा में है. डीपीएम स्टेयरिंग की भूमिका में हैं, वहीं दूसरी ओर, डीएचएस के पार्ट-बी मद के क़रीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का हिसाब ही नहीं मिल रहा है. इसे लेकर सिर्फ़ काग़ज़ी खानापूरी ही चल रही है. गड़बड़झाला की जड़ यही है. एसएचएस पटना का तर्क है कि उक्त साढ़े तीन करोड़ रुपये का हिसाब डीएचएस, दरभंगा ने नहीं दिया है. यानी यह राशि ख़र्च हुई ही नहीं है. फिर बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र के पार्ट-बी में राशि देना ग़ैरक़ानूनी होगा. इस बहस को यहां छोड़ भी दें, तो फिलहाल इन सवालों का जवाब अनुत्तरित है कि आख़िर किस वजह से पार्ट-बी में एक भी पैसा नहीं मिला. इस मद में राशि उपलब्ध हो जाती, तो क्या इससे रोगियों की सुविधाएं नहीं बढ़तीं. सच्चाई से सीएस डॉ. चौधरी बेखबर हैं या फिर एनआरएचएम की योजनाओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है. दरभंगा के सिविल सर्जन ने चौथी दुनिया को बताया कि अविलंब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पार्ट-बी का पैसा अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन मिलने की संभावना है. उन्होंने कहा कि डीएम के सेवा विस्तार के लिए फाइल बढ़ाया गया है. सवाल यह उठता है कि जब डीपीएम का सेवा विस्तार हुआ ही नहीं, तो फिर किस स्थिति में सिविल सर्जन और डीपीएम के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे की निकासी की जा रही है, जबकि डीपीएम के सेवा विस्तार के बिना संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे का निवासी अवैध है. विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रम के बारे में विधान परिषद एवं स्वास्थ्य विभाग को इससें जुड़े गंभीर मामले के बारे में लिख दिया गया है. ■

सिविल

तनाव से दूर रहें

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

शरीर के किसी अंग में जरा भी तकलीफ हो तो बहुत परेशानी होती है. सिर दर्द एक ऐसी बीमारी है, जिसका सीधा संबंध शरीर से तो नहीं है, लेकिन सरदर्द से काफ़ी परेशानी होती है और यह अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है. अररिया के डॉक्टर एपी सिंह कहते हैं कि कभी-कभी सरदर्द की बीमारी लंबे समय के लिए होता है और कभी तो कुछ घंटों में ही ठीक हो जाती है. सरदर्द की शिकायत अक्सर माइग्रेन और साइनस के कारण होती है. माइग्रेन की बीमारी तनाव के कारण होती है, इसमें मरीजों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है. किसी काम में मन नहीं लगता है. कभी-कभी टीबी केकारण भी सिर में दर्द हो सकता है. जिन मरीजों को आंख की रोशनी कम होने की शिकायत रहती है, उन्हें भी सर में अक्सर दर्द रहता है. कई बार मरीजों को एलर्जी होने के कारण भी सर में दर्द हो सकता है. इसलिए मरीज ऐसी चीजों से परहेज करें, जिससे एलर्जी होता है. इसके अलावा खान-पान में भी साफ़ सफ़ाई का ख़ास ख्याल रखें. ■

डॉ. एपी सिंह

एक नज़र

प्रो. चटर्जी के निधन से शोक

सीतामढ़ी के राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के रसायन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं लायंस क्लब के पूर्व जिलापाल प्रो टीके चटर्जी के निधन पर सामाजिक एवं राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक टयक्त किया है. पूर्व मंत्री देवेशचंद्र ठाकुर, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, विधायक गुड्डी देवी, ज़िला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला, जदयू जिलाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह समेत अन्य ने प्रो चटर्जी के निधन पर शोक जताया है. गौरतलब है कि प्रो चटर्जी एक कुशल प्राध्यापक के साथ ही समाजसेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में एक थे. स्थानीय नगर उद्यान से लेकर सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम एवं हलेश्वर स्थान के विकास में प्रो चटर्जी की भूमिका सराहनीय रही है. *- ब्रजेश*

मजदूरों का दर्द मेरा दर्द

चतरा ज़िले के बरकत नगर में आयोजित झारखंड बीड़ी मजदूर संघ की एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने आए मुख्य अतिथि राज्य सभा सांसद धीरज प्रसाद साहु ने मजदूरों के दर्द को अपना दर्द बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है, जो मजदूरों के दु:ख-दर्द से निजात दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है. हाल ही में पार्टी ने देश को बिचौलियों से बचाने के लिए कैश-ट्रांसफर स्कीम लाकर एक नई उपलब्धि रची है. इस मौक़े पर पार्टी के चतरा लोक सभा प्रभारी मो. फुजैल अहमद ने मंच का संचालन किया, जबकि अध्यक्षता संयुक्त रूप से नवयुक्त कार्यकारी अध्यक्ष मो. इमदाद हुसैन, धर्मेंद्र प्रसाद साहु ने किया. इस मौक़े पर पार्टी के पूर्व ज़िला अध्यक्ष बद्रीराम, दुर्गाशंकर सिंह, हाजी साबिर हुसैन, आफताब आलम, सहेंद्र राम, नेमन सिंह, प्रदीप साहु मुख्य रूप से मौजूद थे.

बीडीओ को फटकार

चतरा उपायुक्त मनोज कुमार ने हंटरगंज, प्रतापपुर चतरा हंडवा आदि प्रखंडों में इंदिरा आवास के निर्माण एवं एमआइएस में शिथिलता पर प्रखंड के बीडीओ को फटकार लगाई है. उन्होंने वृद्धा पेंशन भुगतान में विलंब पर भी नाराज़गी जताई है. उन्होंने आगे कहा कि फरवरी माह तक जिनका भी प्रखंड में इंदिरा आवास का रिपोर्ट पूर्ण नहीं पाया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी.

पोस्ता की खेती नष्ट

चतरा पुलिस उपाधीक्षक अंबर लकड़ा एवं वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी के संयुक्त अभियान में सदर थाना एवं वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में लगा पोस्ता (अफीम) के खेती को नष्ट किया गया. इस क्षेत्र में लगातार वर्षों से खेती की जा रही है. यह क्षेत्र अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. पुलिस प्रशासन ने क़रीब दस एकड़ में लगे पोस्ता खेती को नष्ट किया है, जबकि अभी भी पचास एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर पोस्ता की खेती लगी हुई है. जिन गांवों में पुलिस प्रसाशन द्वारा पोस्ता खेती को नष्ट किया गया है, इनमें मानामाथ, कोमुहा के पूर्व एवं पश्चिमी भाग को नष्ट किया जा चुका है. *- चौथी दुनिया ब्यूरो*

शिविर में जांच हुई

सीतामढ़ी शहर के पूर्वी रिंगबांध स्थित राजीव मेमोरियल अर्थो हेल्थ सेंटर में डिलाइटीस डिविजन ऑफ एकोन्मेंट कंपनी द्वारा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके प्रकाश के मार्ग दर्शन में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लायंस क्लब की अध्यक्ष डॉ. प्रतिमा साह एवं निर्मला मिश्रा प्रायोजक बनी. शिविर में तक़रीबन 250 लोग जांच के लिए पहुंचे. इनमें से क़रीब 150 लोगों का जांच कराया गया. कार्यक्रम में डॉ. केएन गुप्ता, डॉ. अंजना प्रकाश, पंकज चौधरी, देव कुमार, राजेंद्र कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, सीमा गुप्ता, पुष्पा लोहिया, डॉ. आरके कुमुद, लक्ष्मी नारायण सिंह, उमेश कुमार, अंशु कुमार, रत्ना कुमारी समेत अन्य थे.

नीतीश पर बरसे पासवान

अररिया के सुभाष स्टेडियम में बिहार बचाओ यात्रा के दौरान रामविलास पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है. नीतीष कुमार बिहार में आठ वर्षों से राज कर रहे हैं, पर विकास नहीं, बल्कि विनाश कर रहे हैं. नीतीष आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं. फॉरबिसगंज भजनपुर गोली कांड की चर्चा करते हुए लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने पीड़ितों के परिजनों को 20 लाख रुपए और एक की नौकरी मुआवजा में देने की बात कहीं. उन्होंने सीबीआई से जांच करवाकर दोषी पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाही की भी मांग की. *- फ़िरोज ख़ान*

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

कर्मठ एवं सुयोग्य बीए ओनर्स उम्मीदवार सोनी कुमारी को कप प्लेट छाप पर बटन दवा कर विजयी बनावें। कल्याणपुर, समस्तीपुर

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ASRFEN-P Acedofenac+Paracetamol Serratiopeptidase Tab.
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
ECTALOPAM Escitalopram oxalate & Clonazepam Tablets
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
SILIPLEX Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
MENSOSET Her. Tonic With Ashoka 1800 mg
ACOBA CAP/SYP/INJ Methylcobalamin, Lycopene, Multivitamin, Multimineral, Ginseng & Antioxidant
MUSTAL Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

जगजीवन महाविद्यालय
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अंगीभूत इकाई
गया - 823003 (बिहार), फोन: 0631-2250029
स्थापना वर्ष-1959
जगजीवन महाविद्यालय, गया, वरीयता क्रम में नगर का दूसरा महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है। आयुक्ति शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ-साथ स्नातक प्रतिष्ठा (कला एवं विज्ञान) में पठन-पाठन की उत्तम व्यवस्था है।
-: इसकी प्रमुख विशेषताएं :-
उच्च शिक्षा के लिए एक उपयुक्त शैक्षिक माहौल
BCA, BBM एवं Bio-Tech
मानकयुक्त पुस्तकालय
सह-शिक्षा का माहौल
NCC एवं NSS का सफल कार्यक्रम
खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की उत्तम व्यवस्था
छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा निर्माणाधीन
भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, वनस्पति, जीव विज्ञान, स्नातकोत्तर में सत्र 2013-14 से पढ़ाई की व्यवस्था
बी.एड एवं बी. कॉम में यथाशीघ्र पढ़ाई की व्यवस्था
Dr. Sunil Suman प्रधानाचार्य

Dr. S.P. SINGH COLLEGE OF DISTANCE EDUCATION
1st & 2nd Floor, Besides City Post Office, Miscot, Main Road, Motihari, East Champaran, Bihar.
Mob : 9472397427, 9534755485
Only Distance Learning Courses from Punjab Technical University & Mahatma Gandhi Univ.
UGC+DEC+AIU+AICTE
Traditional Courses: B.A., B.Com., B.Sc. M.A., M.Com., M.Sc. B. Lis., M. Lis.
IT Courses: B.C.A., M.C.A.
Management Courses: B.B.A., M.B.A.
विशेष जानकारी के लिए श्री अनिल कुमार सिंह से संपर्क करें सुबह 10.00 बजे से शाम 4 बजे तक

राजग गठबंधन के नेताओं का कहना है कि आख़िर सांसद दिनेश चंद्र यादव की क्या ग़लती है, जो कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है.

खगड़िया में राजनीतिक पारा चढ़ा

मनेंद्र कुमार feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया लोकसभा में वर्ष 2009 के चुनाव को पटना हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया, इससे विपक्षी दलों में जश्न का माहौल है. दूसरी तरफ सांसद दिनेश चंद्र यादव खेमे सहित जदयू भाजपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं में कोर्ट के फैसले से भारी निराशा है. राजग गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि आखिर सांसद दिनेश चंद्र यादव की क्या ग़लती है, जो कोर्ट ने उनका निर्चाचन रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि भाकपा प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह का नामांकन रद्द कर दिए जाने के कारण सिंह ने न्यायमूर्ति बीएन सिन्हा की एकलपीठ में चुनाव याचिका दायर की थी. सिंह का कहना था कि उनका नामांकन पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने ग़लत तरीक़े से रद्द कर दिया था, जबकि निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र की त्रुटियां दूर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था. इसके समक्ष समर्थन में अधिवक्ताओं के माध्यम से तथ्य भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने नज़रअंदाज़ कर दिया.

दरअसल, इसी के मद्देनज़र अदालत ने चुनाव को अवैध ठहराते हुए निर्वाचन आयोग को उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है. निर्देश जारी होते ही खगड़िया लोकसभा में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. यहां चर्चा का विषय है कि यदि उपचुनाव होता है, तो किसकी जीत होगी, लेकिन वर्ष 2009 के चुनाव परिणाम पर गौर करें, तो यदि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह मैदान में रहते, तो ऐसे में चुनाव का गणित बिगड़ सकता था. जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव को 2 लाख, 66 हज़ार 964, राजद के डॉ. रवींद्र कुमार राणा को 1 लाख, 28 हजार, 209 तथा कांग्रेस के चौधरी महबूब अली कैसर को 1 लाख, 27 हजार, 415 मत प्राप्त हुआ था, लेकिन कोर्ट का फ़ैसला सुनते ही राजनीतिक गलियारे में अटकले लगना शुरू हो गया कि यदि चुनाव में भाकपा के प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह चुनाव में रहते तो परिणाम कुछ और ही होता. सिंह पूर्व में चौथम जो वर्तमान में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से 1990 एवं 1995 में विधायक का चुनाव दो बार जीत चुके हैं. वह क्षेत्र के असरदार नेता माने जाते हैं. वह वर्ष 1996 और 1998 में खगड़िया लोकसभा चुनाव में भी भाग्य आजमा चुके हैं, जिसमें क्रमश: 73 हज़ार और 78 हज़ार मत मिले थे, जबकि उनके बिरादरी का भी बड़े पैमाने पर मत है. जदयू नेता सह ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष सुनील कुमार का कहना है कि सत्यनारायण सिंह के खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनका जनाधार ख़त्म हो गया है. वह विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उनका वोट ही खिसक गया. इसलिए यह कहना ग़लत है कि खड़ा रहते, तो परिणाम बदल सकता था. तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि सांसद दिनेश चंद्र यादव की जीत की राह मुश्किल थी. वहीं भाकपा प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह का कहना है कि छह अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने उनके सारे काग़ज़ातों को जांच किया तथा सही पाते हुए चेक और लिस्ट जारी कर दिया. इसलिए चेक लिस्ट जारी होने के बाद माना जाता है कि सारे काग़ज़ात ठीक हैं. उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र रद्द करने का आदेश 11 अप्रैल 2009 शाम को अंग्रेजी में जारी हुआ और जब मामला कोर्ट में गया, तो वहां निर्वाची पदाधिकारी का जो आदेश प्रस्तुत किया गया, वह हिंदी में था. इतना ही नहीं बार-बार अनुरोध करने के बाद भी निर्वाची पदाधिकारी ने बात नहीं सुनी. इसलिए दुर्भावना से प्रेरित होकर अधिकारी ने नामांकन रद्द किया था. उन्होंने फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच जनता के सामने आ गया है कि अधिकारी और वर्तमान सांसद का क्रियाकलाप क्या है. वहीं सांसद दिनेश चंद्र यादव का कहना है कि इस फ़ैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे. उन्हें भरोसा है कि वहां न्याय ज़रूर मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी को फॉर्म 26 शपथ पत्र के साथ देना है, इसमें संपत्ति और अपराध संबंधित विवरण होता है, लेकिन सत्यनाराण सिंह ने फॉर्म 26 तो दिया, लेकिन शपथ पत्र नहीं. इसलिए उनका नामांकन रद्द हुआ था. वहीं माकपा के जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि अफसरों द्वारा जनतंत्र पर हमला हुआ है. इसकी कोर्ट ने रक्षा की है, जबकि भाकपा माले के सुभाष सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार के अफसरशाही चरम सीमा पार कर चुका है, इसका नतीजा था कि सत्यनारायण सिंह का नामांकन रद्द करना. इसलिए कोर्ट का फ़ैसला स्वागत योग्य है. वहीं कांगेस के जिलाध्यक्ष लाल बिहारी सिंह का कहना था कि निर्वाची पदाधिकारी को एक पक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिए था. वहीं भाकपा के ज़िला मंत्री प्रभाशंकर सिंह, अनिल सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, राकपा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेताओं ने कहा कि इसे अफसरशाही एवं पूंजी-वादी व्यवस्था पर जीत कह सकते हैं. न्याय के लिए हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा था, लेकिन इस फ़ैसले से न्याय की जीत हुई है. वहीं आम लोगों का कहना है कि अधिकारी द्वारा यदि सही निर्णय किया जाता, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती. वहीं राजद के पूर्व सांसद आरके राणा ने कहा कि वर्तमान सूबे की सरकार में अफसरशाही ज़रूर चरम सीमा पार कर चुकी है, लेकिन न्याय के मंदिर में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है. इस निर्णय के बाद सुशासन की सरकार अफसरों के क्रियाकलाप को उजागर कर दिया है, जबकि राजद ज़िला महासचिव संजय यादव एवं रामशरण विचार मंच के अध्यक्ष विजय कुमार पांडव ने कोर्ट के निर्णय को सराहा है. तमाम बातों को गौर करें, तो इस फ़ैसले के बाद अफसरों का निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है. अफसरशाही का परिणाम बताकर सुशासन की सरकार को कोसा जा रहा है, जबकि वर्तमान सांसद की छवि पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है. यदि उपचुनाव हो या इस तरह की 2014 में चुनाव हो, तो यह मामला जोर-शोर से विपक्षी के द्वारा उठाया जाएगा. जदयू के जीत में कांटे की राह बनकर उभरेगी. अगला सांसद का ताज किसके सिर पर बंधेगा, यह अटकलें लगना अभी से ही शुरू हो गया है. ■

डी.सी.यादव | केसर अली | आर.के. राणा | सत्य नारायण सिंह

शिक्षा व्यवस्था चौपट

मितुल गौतम feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा व्यवस्था में अमीर और ग़रीब के बीच फर्क किया जाए तो इससे शिक्षा का स्तर जरूर गिरेगा. सारी दुनिया एक्सीलेंस एजुकेशन की बात कर रही है और हम अभी तक क्वालिटी एजुकेशन में उलझे हुए हैं. राज्य सरकार ने आज शिक्षा को कई भागों में विभक्त कर दिया है, नतीजा आज शिक्षा-व्यवस्था अनियंत्रित हो गई है. उक्त बातें बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रो. (डॉ.) नवल किशोर यादव ने सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान, पटना द्वारा आयोजित बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर: समस्या और समाधान सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर बोला. वहीं एक क्षेत्रीय निजी चैनल के संपादक अभिरंजन कुमार ने कहा कि शिक्षा हमारी बुनियादी जरूरत है. सेमिनार की अध्यक्षता संस्थान के निर्देशक डॉ. समीर कुमार सिंह ने की. सेमिनार के समापन के दौरान सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते है, ऐसे में लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों के प्रति कैसे क़ायम होगा. ■

एक नज़र

चमकेगा गोगरी

गोगरी अनुमंडल के सबसे उपेक्षित सर्किल नंबर एक के गांवों को अब कोई दियारा नहीं कहेगा क्योंकि इस इलाक़े के सभी गांव जल्द ही सड़क से जुड़ जाएंगे. परबत्ता क्षेत्र के गांवों में सड़क निर्माण किया जाएगा. उक्त बातें बिहार विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक, पूर्व मंत्री एवं परबत्ता विधायक राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी ने कहीं. उन्होंने इस क्षेत्र के सबसे जनउपयोगी सड़क एनएन 31 से सटे देवठा बजरंगबली मंदिर के नजदीक से लेकर 14 किलोमीटर लंबी सड़क नाबार्ड योजना के तहत 14 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले सड़क के शिलान्यास के बाद प्राथमिक विद्यालय भिमड़ी के मैदान में एक महती जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. स्थानीय मुखिया क्षत्री शर्मा के नेतृत्व में एनएच 31 से गाजे-बाजे के साथ सम्राट चौधरी की अगुवाई की गई. विधायक सम्राट चौधरी ने अपने विशेष परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के प्रवास क्रम में रामपुर गांव से कटघरा होते हुए हरिनमार दियारा तक जाने वाले संपर्क पथ में नाबार्ड योजना से निर्मित पुल का उद्घाटन किया. *- गीता कुमार*

नया विकल्प देंगे उपेंद्र

नीतीश सरकार ने जनता के सपने को चकनाचूर कर दिया है. सात वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया. इस सरकार में अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए यहां की जनता को एक नए विकल्प की जरूरत है. ऐसा मानना है खगड़िया के नव निर्माण मंच के प्रदेश संयोजक सह पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा का. उन्होंने बताया कि तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में नव निर्माण महारैली का आयोजन किया जा रहा है. इसी दिन हमारी नई पार्टी बिहार नव निर्माण मंच की विधिवत घोषणा की जाएगी. मौक़े पर ज़िला संयोजक अमीत कुमार मंटु एवं खगड़िया संसदीय क्षेत्र के मुल्कराज आनंद ने संयुक्त रूप से ज़िले के आमजनों एवं कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बिहार में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य सभी मोर्चे पर नए विकल्प के निर्माण की ज़रूरत है.

जदयू प्रखंड अध्यक्ष बने सुनील

खगड़िया सदर प्रखंड अंतर्गत बछौता मध्य विद्यालय में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ. प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी श्रवण कुमार एवं प्रखंड पर्यवेक्षक मनोज कुमार मनुज ने कहा कि सर्वसम्मति से दुबारा प्रंखड अध्यक्ष पद पर सुनील कुमार को चुना गया. इस चुनाव में 24 पंचायत के अध्यक्ष एवं डेलीगेट ने भाग लिया. अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि पार्टी के हित एवं संगठन मजबूत बनाने का कार्य करता रहूंगा. इस मौक़े पर जिलाध्यक्ष सोनेलाल मेहता, अलौली विधायक रामचंद्र सदा, सुबोध कुमार पटेल, युवाध्यक्ष सुनीत कुमार, नीलम वर्मा, सुधीर कुमार सिंह, ध्रुव कुमार शर्मा, अजीत कुमार, ज़िला निर्वाची पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, बबलू मंडल, अरविंद मोहन सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे. *- नंदकिशोर*

पूर्व मंत्री वीरेंद्र की नई पार्टी

बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा ने सामाजिक न्याय दल नामक एक पार्टी का गठन किया है. पटना के रवींद्र भवन में कार्यकर्ताओं एवं अपने समर्थकों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की. इधर कुशवाहा द्वारा उक्त पार्टी बनाए जाने पर रामगढ़वा एमके मिशन आवासीय विद्यालय के सभागार में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया. मौक़े पर ज़िला पार्षद सह दल के प्रदेश सचिव उमेश सिंह कुशवाहा, बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष श्यामसुंदर प्रसाद ने दल के बिहार प्रदेश संगठन सचिव बद्री पासवान, पवन किशोर दास, खुर्शीद आलम, पूर्व सैनिक एवं जिला सामाजिक न्याय दल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, मो. इबलैश, विशेश्वर प्रसाद, पारस नाथ राम, सुनील कुमार मौर्ज, ब्रजकिशोर यादव, सुरेश दास, रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष जयलाल कुशवाहा, महासचिव नंदलाल साह, मनोज साहनी, सरपंच सह दल के कोषाध्यक्ष रविकांत रौशन, दल के मीडिया प्रभारी श्रीनिवास प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे. *- डीएन कुशवाहा*

साइकिल योजना की राशि वितरित

संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के मधुबनी पंचायत स्थित कृष्ण दिवाकर उच्च विद्यालय में एक समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री साइकिल योजना एवं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि छात्रों के बीच बांटी गई. ज़िला पार्षद आशुतोष पांडेय एवं राजन मिश्रा ने मंत्री साइकिल योजना के तहत पच्चीस सौ रुपये प्रति छात्र की दर से 76 छात्रों को एवं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 21 छात्र-छात्राओं के बीच दस-दस हज़ार रुपये का चेक वितरण किया. मौक़े पर प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्विवेदी, शिक्षक विजय मिश्रा, रामबहादुर ठाकुर, सुशील कुमार, मुकुल कुमार पांडेय, आनंद किशोर पांडेय सहित अभिभावक एवं ग्रामीण मौजूद थे. *- मुकुल पांडेय*

शिक्षा का दीप जलाते रवि

चतरा ज़िले के एक ऐसे शिक्षक हैं, जो बिहड़ जंगल और पहाड़ों में अकेले शिक्षा का दीप जला रहे हैं. उनका नाम रवि है. रवि वर्तमान में हंटरगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजगुरु में पदस्थापित हैं. वह अपना वेतन भी ग़रीब और असहाय बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं. उन्हें अब तक कई जनप्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है. पुरस्कृत करने वालों में राज्य सभा सांसद, धीरज प्रसाद साहु, वर्तमान सांसद इंद्र सिंह नामधारी, चतरा ज़िला परिषद अध्यक्ष ममता देवी आदि ने पुरस्कृत किया है. *- अमरेंद्र प्रताप*

रवि कुमार

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

131 कल्याणपुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से काँग्रेस पार्टी की स्थानीय, शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील, समाजसेवी एवं लोकप्रिय उम्मीदवार पूर्व काँग्रेस विधायक स्व0 चुल्हाई राम की पौत्री अनीता राम बी.ए.ऑनर्स के हाथ छाप के सामने बटन दबा कर भारी मतों से विजय बनावें। चुनाव चिन्ह

131 कल्याणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के स्थानीय प्रत्याशी शिक्षित, कर्मठ, सुयोग्य, संघर्षशील, समाजसेवी एवं लोकप्रिय महिला उम्मीदवार मंजू कुमारी तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें। चुनाव चिन्ह

Mahindra powerol Engines & DG sets powered efficiency
World Class Silent DG Sets
Zero-Leak engines
Most fuel efficient in its class
Manual & AMF Power
Available on DGS & D Rate Contract
Range 2.5 kVA to 500kVA
Finance Available
24 x 7 Service
SATYA ENTERPRISES Land Development Bank Building, Budh Marg, Patna-800001

पार्टी के अनेक नेताओं का आरोप है कि ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने निवर्तमान अध्यक्ष को पुन: कुर्सी पर बैठाने के मकसद से सुगौली, पकड़ीदयाल, चकिया, मेहसी और चिरैया प्रखंडों का चुनाव ही निरस्त कर दिया.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बेपटरी हुईं सीतामढ़ी की रेल परियोजनाएं

सीतामढ़ी ज़िले में रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए वर्ष1992 में प्रयास शुरू किया गया. तब वहां के सांसद थे नवल किशोर राय. बाद में राजद के सीताराम यादव ने बतौर सांसद कमान संभाला था. पिछले चुनाव जदयू के अर्जुन राय ने जीत सुनिश्चित करते हुए सांसद के रूप में कमान थाम ली, लेकिन आगामी चुनाव में मात्र एक साल शेष रह गया है और अब तक रेल परियोजना पूरी नहीं हो सकी है. संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि शायद चुनावी लाभ की उम्मीद में जनप्रतिनिधि इसे खींच रहे हैं.

ब्रजेश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

अर्जुन राय

नवल किशोर राय

सीताराम यादव

सीतामढ़ी को ज़िले का दर्जा मिलने के चार दशक बाद भी ज़िले में रेल परियोजनाओं का निर्माण अब तक अधर में लटका है. ऐसा नहीं है कि बीते वर्षों में इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन कार्य की धीमी रफ्तार से यह पता चलता है स्थानीय ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस दिशा में सार्थक पहल नहीं की है. नतीजा यह है कि हर बार सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है. चाहे वह दरभंगा–सीतामढ़ी–नरकटियागंज अमान परिवर्तन का मसला रहा हो, या सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नए रेल लाइन निर्माण का या फिर बैरगनिया से छौडादानो रेल परिचालन का. गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता जटा शंकर आत्रेय ने समय–समय पर ज़िले से लेकर प्रखंड तक आंदोलन किया. वर्ष 1991 में पहली बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद नवल किशोर राय ने दिल्ली के ससंद भवन ज़िले में रेल परियोजनाओं के विस्तार की भूमिका बांधना शुरू किया था. वर्ष 1992 में राय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया. वर्ष 1996–97 में उन्होंने दरभंगा–नरकटियागंज रेल लाइन के परिवर्तन की स्वीकृति दिलाई थी. बाद में राशि भी आवंटन कराया था. 1998 के लोकसभा चुनाव में राजद के सीताराम यादव से पराजित होने के कारण राय की रेल योजना अधर में लटक गई, लेकिन अगले ही साल वर्ष 1999 में पुन: सांसद बनने के साथ ही उन्होंने कार्य के लिए राशि मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई. वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में राजद के सीताराम यादव ने पुन: सांसद बनने का मौक़ा प्राप्त कर लिया. इस बीच देश की राजनीति और रेल महक़मे में हुए फेर बदल के कारण भी परियोजना की रफ्तार धीमी रही. बतौर सांसद सीताराम यादव ने भी कार्य की गति को कुछ हद तक बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली. तपस्वी नारायण दास हॉल्ट एवं भीसा हॉल्ट समेत अन्य कुछ कार्य ही कराए जा सके, लेकिन बाद में तत्कालीन सांसद नवल किशोर राय द्वारा डाले गए रेल की नींव ने असर दिखाना शुरू किया, जो वर्ष 2008 में ज़ोर पकड़ा. जय नगर–दरभंगा नरकटियागंज रेल खंड पर तक़रीबन 501 करोड़ की लागत से परिवर्तन का कार्य शुरू कराया गया. दरभंगा–सीतामढ़ी के बीच क़रीब 68 किलोमीटर में 70 पुल एवं पुलिया के साथ 123 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य आरंभ हुआ. इसके लिए 15 मार्च 2008 को मेगा ब्लॉक लिया गया और 29 सितंबर 2008 को निर्माण कार्य कराया गया. पुन: सीतामढ़ी–बैरगनिया के बीच 29 किलो मीटर में 20 पुल व 13 पुलिया के साथ 68 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया गया. इस कार्य के लिए 15 मार्च 2010 को मेगा ब्लॉक लिया गया और 12 अप्रैल 2011 को कार्य पूरा कराया गया. फिर बैरगनिया से छोडादानो के बीच क़रीब 31 किलो मीटर में 11 पुल एवं 24 पुलिया के साथ लगभग 77 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया गया. इस कार्य के लिए 1 अप्रैल 2011 को मेगा ब्लॉक लिया गया और मार्च 2012 में कार्य पूरा किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 5 मार्च 1995 से निर्माणाधीन सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर रेल लाइन का निर्माण अब तक अधर में लटका है. कई आंदोलन के बाद पिछले साल बड़ी मुश्किल से सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर रेल खंड पर रुन्नीसैदपुर तक रेल परिचालन कराया जा सका. तब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी सफलता के जमकर गुणगान भी किए, लेकिन रुन्नीसैदपुर से मुजफ्फरपुर तक परिचालन अब तक संभव नहीं हो सका है. इस बीच स्थानीय सांसद अर्जुन राय ने रेल महक़मा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बहाने शीघ्र परिचालन शुरू कराने की घोषणा भी करते रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रेल के विकास के साथ ही ज़िला को विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि अब तक एकमात्र लिच्छवी एक्सप्रेस एवं दूसरा सप्ताह में दो दिन चलने वाली मिथिलांचल एक्सप्रेस को छोड़ कर लंबी दूरी की ट्रेन आप भी जिलावासियों को उपलब्ध नहीं करा सके हैं. वर्ष 2009 से बतौर सांसद ज़िले के विकास का कमान थामने वाले वर्तमान सांसद अर्जुन राय की मंशा चुनावी रेल का चक्का चलाना नहीं है, इसलिए लोगों में चर्चा का केंद्र बना है. कारण कि पिछले दिनों सांसद राय ने स्थानीय मीडिया में रेल महक़मा के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में मार्च माह में सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर खंड पर रेल परिचालन की घोषणा की थी, लेकिन रेल के मुख्य अभियंता निर्माण बीएस चिटौजिया का अगले ही दिन के बयान ने सांसद के घोषणा को अविश्वास के घेरे में डाल दिया, जब उन्होंने मीडिया में शीघ्र परिचालन को स्वीकारते हुए मार्च महीना के निर्धारण को खारीज कर दिया. अब वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय, वर्तमान से लेकर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री तक ने अघोषित रूप से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है. ज़िले के लोगों को अंदेशा है कि कहीं ज़िले में रेल का पहिया चुनावी पटरी पर तो नहीं है. हालांकि हक़ीक़त से रूबरू होने में महज एक साल शेष रह गए हैं. अब रेल का खेल ज़िले की राजनीति को कौन सी दिशा देती है? इसका सभी को इंतज़ार है. ■

जदयू में गुटबाज़ी भारी पड़ी

इंतेज़ारुल हक़
feedback@chauthiduniya.com

सत्ताधारी जदयू पूर्वी चंपारण ज़िले में दो फाड़ हो गया है. जदयू के अपने ही लोग दिशा बदलती नदी के दो किनारों की तरह हो गए हैं और बीच का बहता हुआ पानी (कार्यकर्ता) इन दिनों चक्कर खाने लगा है. पूर्वी चंपारण में जदयू की गुटबाज़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से इसमें काफ़ी तेजी आई है. दरअसल, इसका नतीजा बीते दिनों सामने तब दिखा, जब नगर भवन में जिलाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आहूत आम सभा में सभी वरीय नेताओं की मौजूदगी के बावजूद जूतम पजार होते–होते बचा. हंगामा इस क़दर हुआ कि ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुशवाहा और प्रांत से आए ऑब्जर्वर प्रदेश महासचिव मंसूर आलम भी सकते में पड़ गए. अंतत: मौजूद विधायकों और पार्टी के नेताओं ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिलाध्यक्ष नामित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया. गौरतलब है कि हंगामा कर रहे पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी पर जमकर पक्षपात करने और डेलीगेटों का नाम परिवर्तित कर अपने चहेते को अध्यक्ष बनाने का प्रयास करने का आरोप लगा रहे थे. यहां प्रो. दिनेश चंद्र प्रसाद पहले से जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं. वह इस बार भी अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के लिए मैदान में हैं, जहां उनका जमकर विरोध हो रहा है. चुनाव में पार्टी के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन की उपज और पार्टी के समर्पित नेता ब्रजेश श्रीवास्तव अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, इस बात का पता जैसे ही निर्वाचन पदाधिकारी को चला, वह निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. दिनेश की मदद को व्याकुल हो उठे. पार्टी के अनेक नेताओं का आरोप है कि ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने निवर्तमान अध्यक्ष को पुन: कुर्सी पर बैठाने के मकसद से सुगौली,पकड़ीदयाल, चकिया, मेहसी और चिरैया प्रखंडों का चुनाव ही निरस्त कर दिया. इन प्रखंडों के निर्वाचित अध्यक्ष एवं डेलीगेट निवर्तमान अध्यक्ष के मुखालिफ थे. इतना ही नहीं, केसरिया और पताही प्रखंड के चुनाव को ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीकार तो किया, पर अध्यक्ष द्वारा भेजे गए डेलीगेटों की सूची यहां न केवल बदल दी गई, बल्कि मनमाफिक सूची बनाकर उसे मतदाता सूची में डाल दिया गया. जैसे ही परिवर्तित सूची और इन प्रखंडों के संपन्न चुनाव को निरस्त करने की ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने घोषणा की वैसे ही कार्यकर्ता भड़क उठे और निर्वाचन पदाधिकारी पर पक्षपात करने तथा जदयू संगठन को यहां छिन्न–भिन्न करने का आरोप लगाते हुए नारेबाज़ी करने लगे. पार्टी संविधान के अनुसार, ज़िले से निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पार्टी के समर्पित पदाधिकारियों को प्रखंड में पर्यवेक्षक तैनात किया जाता है और अलग से प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं. इन दोनों की मौजूदगी में उपस्थित सक्रिय सदस्यों द्वारा प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. प्रखंड से चौदह सक्रिय सदस्यों को जिला के लिए डेलीगेट के रूप में चुना जाता है. ज़िले के प्राय: सभी प्रखंडों में इस प्रक्रिया का अनुपालन जरूर किया गया, लेकिन ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी पर पताही एवं केसरिया के डेलीगेट को बदलने का आरोप संगठन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. हालांकि जानकारों का कहना है कि न केवल ज़िले के कार्यकर्ता, बल्कि प्रभावकारी नेता एवं विधायक भी यहां मौजूदा अध्यक्ष के बदले जाने के पक्षधर बताए जा रहे हैं. नरकटिया के विधायक श्यामबिहारी प्रसाद को अभी भी मौजूदा अध्यक्ष के प्रति मोह दिख रहा है, जबकि नीतीश सरकार के काबिना मंत्री अवधेश कुशवाहा, विधायक रजिया खातुन, पूर्व विधायक मो. अब्दुल्लाह, विधायक शिवजी राय, विधायक मीना द्विवेदी और विधान पार्षद सतीश कुमार परिवर्तन के पैरोकार हैं. यदि यह एकता बरक़रार रही, तो नीतीश कुमार को बाध्य होकर अध्यक्ष बदलना ही पड़ेगा. ऐसी स्थिति में जदयू यहां दो खेमों में बंटी दिख रही है और इस गुटबाजी को संभाल पाना निवर्तमान अध्यक्ष के लिए दूर की कौड़ी नज़र आ रही है. ऐसे में फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है. अब देखना यही है कि उनकी पसंद आम कार्यकर्ताओं एवं संगठन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति ब्रजेश श्रीवास्तव होते हैं या फिर अपने पुराने चहेते और निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश चंद्र प्रसाद. वैसे तो संगठन के लिहाज से अध्यक्ष के दोनों उम्मीदवारों का राजनीतिक जीवन काफी लंबा है. दोनों वर्ष 1974 के आंदोलन की उपज हैं. वर्ष 1994 में जब जनता दल विभाजित हुआ था और जद (जॉर्ज) का 12 सांसदों के साथ निर्माण हुआ था, तब ब्रजेश श्रीवास्तव जनता दल के ज़िला महासचिव थे. दरअसल, उन्होंने विभाजन के बाद इस्तीफा देकर जद (जॉर्ज) में शामिल होकर नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार किया था. वह तब से लगातार पार्टी के महासचिव एवं विभिन्न पदों पर बरक़रार रहते हुए दल की सेवा करते रहे हैं. ■

Best wishes on the occasion of New Year and Basant Panchmi
Running with Spectacular Success
TECHNO MISSION SCHOOL
Samastipur - 848101 (Bihar), Phone : 06274 225309
e-mail : technomission.principal@gmail.com
Run & Managed by : Apurva Welfare Society, Samastipur

Mr. A. K. Lal
Chairman
9431245057

Mr. M. K. Karna
Manager
9304051574

Mr. V. K. Mishra
Principal
9386951010

"EMPOWERMENT THROUGH EDUCATION"

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Opth. Bachelor of Ophthalmology

संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
टीकाकरण
फिजियोथेरापी
अकुपेशनल थेरापी
स्पीच थेरापी
नेत्र जाँच
सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य

1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.

Admission Going On...
डा.अनिल सुलभ
निदेशक-प्रमुख

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

25 फरवरी-03 मार्च 2013

www.chauthiduniya.com

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

लोकसभा चुनाव के लिए

सजती बिसात

अजय कुमार

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी समर के नजदीक आते ही न केवल राजनीतिक दावों और वादों का एक नया दौर शुरू हो जाता है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता पार्टी की जीत के बड़े-बड़े दावे भी करने लगते हैं. वहीं चुनाव मैदान में ताल ठोंकने वाले प्रत्याशी वायदों की झड़ी लगा देते हैं. यही खेल आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है. लोकसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए सभी दलों के मुखिया आक्रामक नजर आ रहे हैं. विरोधियों को पटखनी देने के लिए उनकी कमजोर नब्ज पर चोट की जा रही है. इसके लिए नेताओं के ड्रांइग रूम में रणनीति बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा है. वहीं वोटरों को अपने जाल में फंसाने के लिए वे विवादास्पद मुद्दों को भी हवा दे रहे हैं. इस खेल में सपा-बसपा, कांग्रेस-भाजपा कोई भी पीछे नहीं है. दूसरों की पगड़ी उछालकर उन्हें कमजोर और अपने को मजबूत बताने में सभी नेता एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी क्रम में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह दूसरी पार्टियां बेदम, हमारे लोगों में है दम का राग अलापने से भी नहीं चूक रहे हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले दो दशकों से राजनीति और राजनीतिज्ञों से दूरी बना कर चल रही है. नेता और जनता के बीच सरोकार लगभग खत्म सा हो गया है. एक समय था, जब चौपालों से लेकर चौराहों तक पर लोग राजनीतिक चर्चा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, अपनी राय व्यक्त किया करते थे. लेकिन राजनीति और राजनेताओं का स्तर क्या गिरा कि, लोग अब इस स्तरहीन राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं. हां, चुनाव के समय लोगों के बीच थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर सुनाई देती है. यही एक मौका होता है, जब पांच वर्षों में एक बार नेता हर मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचते हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है. प्रत्याशी यानी नेता भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें किस इलाके में समर्थन मिलेगा, और कहां से उन्हें नकार दिया जाएगा. जहां से समर्थन की उम्मीद ज्यादा होती है, नेता वहीं ज्यादा समय बिताते हैं. इतना ही नहीं, जीत दर्ज करने के बाद भी इसी हिसाब से विकास कार्य भी कराए जाते हैं.

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 80. लोकसभा चुनाव के होने में अभी एक वर्ष से अधिक का समय शेष है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति परवान चढ़ने लगी है. सभी दलों के नेताओं की बोली में चुनाव का असर दिखाई देने लगा है. प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राजनीतिक पार्टियां पूरी गंभीरता के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए बिसात बिछाए बैठी हैं. वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो इस समय राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर पांच राजनीतिक दलों का क़ब्जा है, जिनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 22-22, बसपा के 21, भाजपा के 10 और राष्ट्रीय लोकदल के 5 सांसद हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही पांच दलों का वर्चस्व रहा हो, लेकिन चुनावी संग्राम में करीब दो दर्जन राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. यह और बात है कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. इसका यह मतलब नहीं है कि इन दलों के हौसले पस्त पड़ गए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के छोटे छोटे दल भी जोड़-तोड़ में लग गए हैं. पीस पार्टी, अपना दल, जस्टिस पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम राजनीतिक दल समय रहते प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व तैयार करने में लगे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन यह तय है कि प्रदेश की चार बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के प्रत्याशी 2014 में करीब-करीब सभी

पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही पांच दलों का वर्चस्व रहा हो, लेकिन चुनावी संग्राम में करीब दो दर्जन राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. यह और बात है कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. इसका यह मतलब नहीं है कि इन दलों के हौसले पस्त पड़ गए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के छोटे छोटे दल भी जोड़-तोड़ में लग गए हैं. पीस पार्टी, अपना दल, जस्टिस पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम राजनीतिक दल समय रहते प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व तैयार करने में लगे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन यह तय है कि प्रदेश की चार बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के प्रत्याशी 2014 में करीब-करीब सभी सीटों पर ताल ठोंकते नजर आएंगे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमाएगी.

सीटों पर ताल ठोंकते नजर आएंगे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमाएगी. सभी राजनीतिक दलों को अपनी-अपनी ज़मीनी पकड़ का अहसास तो है, लेकिन इनमें से कोई भी दल 55 से 60 सीटों से कम जीतने की बात नहीं कर रहा है.

लोकसभा चुनाव के लिए अगर प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही 80 में से 69 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित करके प्रारंभिक बढ़त हासिल कर ली है. दरअसल इसी वजह से प्रत्याशियों को क्षेत्र में काम करने और क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए पर्याप्त समय भी मिल गया है. लेकिन सरकार प्रशासन और शासन के स्तर पर लगातार नाक़ाम हो रही है. अपनी नाक़ामियों को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है. जैसा कि कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया गया. मुलायम प्रशासनिक खामियों के लिए लगातार नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं. क़ानून व्यवस्था का प्रदेश में हाल बेहाल है. सरकार अपने निर्णय बदलने की आदत भी नहीं बदल पाई है. जिस तरह गोंडा के विधायक विनोद सिंह से सीएमओ के अपहरण के बाद इस्तीफा लिया गया था, उन्हें वापस बहाल करके सपा ने जनता के सामने एक गलत संदेश दिया है. अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार जनता

की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है. युवा सीएम का प्रदेश को स्वच्छ छवि वाली सरकार देने का दावा खोखला साबित हो चुका है. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बढ़त की उम्मीद लगाए बैठी है, तो यह उसका भोलापन ही कहा जाएगा. कोई भी समाजवादी नेता ज़मीनी हकीकत समझने के लिए तैयार नहीं है. आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर क़ाबिज होने का सपना देखते हुए आगे बढ़ रहे मुलायम सिंह किसी स्पष्ट नीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाए हवा में ज्यादा बातें कर रहे हैं. विधान सभा चुनाव के बाद से आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ ऐसा नहीं किया, जिससे कि विपक्षियों को सपा की बढ़ती ताकत का अहसास हो सके. सरकार की क्लास लेना उनकी दिनचर्या बन गई है. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही उनका ज्यादा समय गुजरता है. वह समाजवादी पार्टी के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में यदा-कदा ही दिखाई देते हैं. एक तरफ तो वह केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की दुर्दशा के लिए वह कांग्रेस को भी कुसूरवार ठहरा रहे हैं. बहरहाल, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा करके मुलायम सिंह ने अपनी काफी किरकिरी करा ली है. उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर किसी एक दल का क़ब्ज़ा हो गया हो. यह बात सपा सुप्रीमो को न जाने क्यों समझ में नहीं आ रही है. उनकी बातों में विरोधाभास अधिक नज़र आता है. एक तरफ तो वह प्रदेश सरकार की असफलता के लिए उसकी लगातार खिंचाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मतदाता प्रदेश की समाजवादी सरकार के कामकाज से खुश होकर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट देंगें. सरकार ही नहीं, संगठनात्मक रूप से भी समाजवादी पार्टी जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है. उसके नेता जनसेवा करने की बजाए लूट-खसूट और क़ानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने में लगे हैं. दागियों ने समाजवादी पार्टी को अपना खेवइया बना रखा है. सपा प्रमुख को ब्यूरोक्रेसी की खामियां तो नजर आती हैं, लेकिन अपनी सरकार की छवि की उन्हें चिंता नहीं रहती. यदि मुलायम सिंह सरकार की छवि के प्रति वाकई में गंभीर होते, तो आपराधिक प्रवृत्ति के कई नेताओं के पास लाल बत्ती नहीं होती. राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की बातों में राजनीति का पुट ज्यादा रहता है, इसीलिए अखिलेश सरकार के मंत्री बेलगाम होते जा रहे हैं. वोट बैंक की राजनीति मुलायम के सिर चढ़कर बोलती है, जिस नेता के पास वोट बैंक है, नेताजी उसे कुछ भी नहीं कहते हैं. राजनीतिक विश्लेषक सपा प्रमुख के दावों को नकारते हुए सपा को लोकसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं हैं. इसके लिए वे दलील देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश को आगे करके लड़ा था. अखिलेश युवा थे, उनकी बातों को लोगों ने गंभीरता से लिया, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही अखिलेश की असलियत सबके सामने आ गई. वह भी अपराधियों को संरक्षण देने में पीछे नहीं हैं. उनके मंत्रिमंडल में कई दागी हैं. ऐसे में अबकी बार उनका जादू शायद ही मतदाताओं के सिर चढ़ कर बोले. बसपा भी विधान सभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बेचैन लग रही है. वह लोकसभा चुनाव में सपा को पटखनी देकर हिसाब बराबर करना चाहती है. बसपा ने भी कई सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के खाते में 21 सीटें आईं थीं. उस समय बसपा की ठीक वैसी ही स्थिति थी, जैसी आज समाजवादी पार्टी की है. तब बसपा को सत्ता में आए करीब दो वर्ष हुए थे. जनता की नाराज़गी उनसे बढ़ने लगी थी, फिर भी 21

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

सपा प्रमुख के फैसले से हाथरस से सपा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन की जीत की राह भी थोड़ी आसान हो सकती है.

सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि इन होर्डिंगों में कहीं भी बड़े लोहिया (डॉ. राम मनोहर लोहिया) और छोटे लोहिया (जनेश्वर मिश्र) का नामोनिशान नहीं था.

लोकसभा चुनाव के लिए सजती बिसात

पृष्ठ 17 का शेष

सीटें उनके खाते में आ ही गईं. लेकिन बसपा, सपा के रास्ते पर चलते हुए एक बार फिर से बाहुबलियों को अपने खेमे में शामिल कर रही है. वह बाहुबलियों को लोकसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाने में पीछे नहीं है. जैसा कि फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार को बदलकर बाहुबली बबलू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. लोगों की सपा से बढ़ती असंतुष्टि का फायदा बसपा को मिल सकता है और उसके खाते में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं. मायावती किसी भी तरह लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं. लेकिन बाहुबलियों का साथ बसपा के लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है.

प्रदेश की जनता को धीरे धीरे अहसास हो रहा है कि बसपा राज वर्तमान सपा राज से बेहतर था. भले ही मायावती के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन वह समाजवादी सरकार के आका की तरह नौकरशाही के सामने लाचार नहीं दिखती थीं. नौकरशाही के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण था. इस बात का फायदा जनता को भी मिलता था. बसपा राज में गुंडाराज आज के मुकाबले बहुत कम दिखता था. उनके समय प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द्र बेहतर था. उन्होंने अपने कार्यकाल में सांप्रदायिकता को प्रदेश में किसी भी तरह सर नहीं उठाने दिया. इस एक मामले में सपा से बेहतर नज़र आती हैं. सपा के ग्यारह महीने के कार्यकाल में प्रदेश में कई दंगे हो चुके हैं. सपा पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप भी लग रहे हैं, जबकि मायावती के कार्यकाल में उन पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे. बसपा सुप्रीमो सत्ता हासिल करने के बाद जातिवाद की राजनीति से काफी हद तक दूर चली गई थीं, जबकि सपा राज में ठीक इसके उलट हो रहा है. प्रदेश की जनता का भला करने की बजाए सपा सरकार जनता को अलग-अलग बांट कर देखती और सुविधाएं बांटती है. इसीलिए समाज का एक बड़ा तबका उनसे नाराज चल रहा है. वैसे मायावती इसका फायदा उठा सकती हैं. हाल ही में उनके भाई के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. यह उनके लिए ठीक संकेत नहीं हैं. ऐसी स्थिति में मायावती को भी नुकसान हो सकता है.

केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव में लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में 22 लोकसभा सीटों पर क़ब्ज़ा कर पाई थी. इससे पहले 1989 में उसके सांसदों की संख्या दो अंकों तक पहुंच सकी थी. तब उसके 15 सांसद जीत सके थे. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश में दहाई के आकड़े तक पहुंचने के लिए तरस गई है. 2012 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी. 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया था. इस बार राहुल बतौर कांग्रेस उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने हैं. इस बार उनके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी होगी. वह उत्तर प्रदेश को शायद ही पिछली बार जितना वक्त दे पाएं. ऐसे तो उत्तर प्रदेश में उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है, साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की सशक्त टीम भी नहीं है. कांग्रेस बतौर संगठन प्रदेश में कमजोर हो गया है. एक के बाद एक घोटालों के खुलासे के कारण केंद्र सरकार के साथ-साथ कांग्रेस की छवि भी खराब हो गई है, इसलिए लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रह गया है. इसके साथ दिन व दिन बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है. यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है. ऊपर से बीमारी से उबरने के बाद सोनिया गांधी में पहले जैसी तेजी भी नहीं दिखाई पड़ रही है. इस कारण कांग्रेस के लिए 22 का आंकड़ा छू पाना भी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. उसकी सीटों की संख्या में गिरावट होना तय दिखाई पड़ रहा है. कांग्रेस 10 से 15 सीटें भी हासिल कर ले, तो यह उसका सौभाग्य होगा.

भाजपा की तो बात ही निराली है, क्योंकि वहां कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा पैदा होते हैं. फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के गिरने का ग्राफ 2014 में थम जाएगा. उसे सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है. राजनाथ सिंह की भाजपा अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने के बाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं के जोश में इजाफा हुआ है. कल्याण की वापसी, उमा भारती का उत्तर प्रदेश में बढ़ता रुझान, समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की नीति, कांग्रेस की खराब छवि यह सभी वे बातें हैं, जो कि अंधे के हाथ बटेर लगवाने में योगदान कर दें. भाजपा अपनी अंदरूनी उठापटक पर रोक लगाकर इस मौके से कितना फायदा उठा पाती है यह तो वक्त ही बताएगा. उम्मीद पर दुनिया कायम है, भाजपा भी इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 सीटों पर क़ब्ज़ा करना चाहेगी. यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं होती है, तो उसे लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा.

अन्य छोटे दलों जिनमें कांग्रेस को केंद्र में समर्थन दे रहा राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है. ये दल प्रदेश के क्षेत्र विशेष या सीट में अपना असर दिखा सकते हैं, उनसे किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है. राष्ट्रीय लोकदल की छवि भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है. उनकी गुड़(सत्ता) के पास भिनभिनाने की प्रवृत्ति सबको साफ दिखाई देती है. उनका न कोई स्थाई दोस्त है न ही दुश्मन. वह तो सत्ताधारी दल के साथ होते हैं. पिता चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे अजित सिंह की इस पार्टी की सीटों की संख्या भी तीन के आकड़े तक सिमट सकती है. क्रिकेट और राजनीति दोनों ही अनिश्चितताओं का खेल है, एक ही पल में दोनों खेलों का रुख बदल जाता है. बदलता मौसम भी दोनों पर असर डालता है. ऐसे में सभी को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पिच पर लोकसभा चुनावों का इंतजार है. उत्तर प्रदेश को फतह किए बिना दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ■

अजित को घर में घेरेगी सपा

संजय सक्सेना feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ जबर्दस्त घेराबंदी शुरू कर दी है. खासकर अजित सिंह को उनके संसदीय क्षेत्र बागपत में घेरने के लिए सपा ने अपने तेजतर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री को छोटे चौधरी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है. शास्त्री की पहचान अजित विरोधी राजनीति करने वालों में होती है. दोनों के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहता है. 1998 में शास्त्री अजित सिंह को पटखनी भी दे चुके हैं. जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले शास्त्री भाजपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं. पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. बागपत से पहले डॉ विजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था. इसके अलावा सपा प्रमुख ने रालोद सांसद सारिका बघेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है. अपने पाले में खींचकर मुलायम ने उन्हें आगरा से प्रत्याशी बनाया है. सारिका के पति बघेल हैं, जबकि सारिका जाटव हैं. आगरा में जाटव और बघेल मतदाता अच्छी-खासी तादाद में हैं. सपा ने आगरा की सीट हथियाने के लिए मजबूत चाल चली है. इसके साथ ही सपा प्रमुख के फैसले से हाथरस से सपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन की जीत की राह भी थोड़ी आसान हो सकती है.

बागपत से पहले डॉ विजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था. इसके अलावा सपा प्रमुख ने रालोद सांसद सारिका बघेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है. अपने पाले में खींचकर मुलायम ने उन्हें आगरा से प्रत्याशी बनाया है. सारिका के पति बघेल हैं, जबकि सारिका जाटव हैं. आगरा में जाटव और बघेल मतदाता अच्छी-खासी तादाद में हैं.

गौतरलब हो कि विधान सभा चुनाव के समय भी सपा ने अजित की बेहद करीबी अनुराधा चौधरी को अपने पाले में खींचकर रालोद को तगड़ा झटका दिया था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही जाट नेता राजेंद्र चौधरी को अखिलेश की कैबिनेट में शामिल कराया है. इसके अलावा, कानपुर से केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को उतार कर सपा ने जायसवाल साहब की धड़कने तेज कर दी हैं. उक्त तीन स्थानों के अलावा, सपा ने बरेली से आयशा इस्लाम, फर्रूखाबाद से सचिन सिंह यादव, अंबेडकर नगर से हीरालाल यादव, संतकबीरनगर से अब्दुल कलाम को अपना प्रत्याशी बनाया है. सपा अब तक कुल 69 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. ■

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार

क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बढ़ावा क्यों?

संजय सक्सेना feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार गठन के ग्यारह महीने बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल से दागी चेहरों की छुट्टी कर देंगे, जिससे कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार की साफ-सुथरी छवि लोगों को दिखाई दे. लेकिन विस्तार के दौरान ठीक इसके उलट हुआ. विस्तार के दौरान मुख्यमंत्री एक साथ कई कार्ड खेलते दिखाई दिए. उनकी राजनीतिक सोच क्षेत्रीय और जातीय राजनीति में उलझ कर रह गई है. लगता है अखिलेश भी यह समझ गए हैं कि क्षेत्रवाद और जातिवाद के इस दौर में चुनाव कूटनीति से जीता जा सकता है, और इसके लिए सरकार की छवि कोई अहमियत नहीं रखती. एक तरफ उन्होंने मंत्री पद और लाल बत्ती बांटते वक्त सबको साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की बिसात पर गोटियां सजाते दिखाई दिए. मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उनकी छवि भी बदल गई है. वह इस विस्तार के बाद मुलायम के पद चिन्हों पर चलते दिखाई दिए. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि संकट में साथ देने वालों को सम्मान देने में सपा पीछे नहीं है, इसके लिए उन्हें दागियों को भी गले लगाने से परहेज नहीं है. ठीक ऐसी ही राजनीति मुलायम करते हैं. वह भी जिसे दोस्त मानते हैं, उसे साथ लेकर चलने के लिए ज़माने से इजाजत नहीं लेते थे. अब ऐसा ही कुछ अखिलेश भी करते दिखे. इसके साथ ही उन्होंने यह दिखाने की कोशिश भी की कि सपा की सियासत में अब अगड़ों को भी शामिल कर लिया गया है.

पुराने समीकरणों और पुख्ता ज़मीन के सहारे अगड़ों व पिछड़ों की मजबूत गोलबंदी करके विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने वाली समाजवादी पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए इस गोलबंदी को और मजबूत करने की कोशिश की है. इसके साथ ही जातीय समीकरणों को बैलेंस करते दिखाई दिए. दरअसल, सपा नेताओं को विधान सभा चुनाव के समय ही यह बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ एक वर्ग व जाति के आधार पर वे दिल्ली की सियासत में अपना दखल नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अब वे ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य को भी किसी भी तरह सपा के साथ जोड़े रखना चाहते हैं. इसके अलावा सपा आलाकमान अति पिछड़ी जातियों के जरिये अपने पारंपरिक पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में भी बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं. मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए तिर्वा (कन्नौज) के विजय बहादुर पाल कानपुर मंडल में पाल बिरादरी के अकेले विधायक हैं. उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके पाल समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है. कानपुर मंडल में बाल बिरादरी काफी है. राजेंद्र चौधरी, रामसकल गुर्जर, विजय मिश्रा, मनोज पांडेय, राममूर्ति वर्मा, आलोक कुमार शाक्य, गायत्री प्रजापति तक लगभग सभी चेहरे लोकसभा चुनाव में सपा के लिए वोटों के इंतजाम की रणनीति का हिस्सा रहे थे. सपा उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए सभी को लालबत्ती थमा दी. वोट बैंक को साधने की चाहत में अखिलेश ने मंत्रिमंडल में कई दागियों को भी जगह दे दी. मंत्रिमंडल में शामिल हुए लोगों में राजेंद्र चौधरी, विजय कुमार मिश्रा, योगेश प्रताप सिंह को छोड़कर अधिकांश के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, शांति भंग करने और दंगों के आरोप लग चुके हैं. छात्र राजनीति से आने वाले तेज नारायण पांडेय पर सर्वाधिक आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं पंडित सिंह व मनोज पांडेय के खिलाफ तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुख्यमंत्री से जब उनके मंत्रिमंडल के नए सहयोगी विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के बारे में पूछा गया कि वह गोंडा के सीएमओ के अपहरण तथा उन्हें धमकी देने के मामले में आरोपी हैं, इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों जगह दी गई है, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जांच के पूरा हुए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. मुख्यमंत्री कुछ भी कहें लेकिन हक़ीकत यही है कि विवादास्पद छवि के लोगों से उनका जुड़ाव सपा की छवि के लिए ठीक नहीं है. चाहे वह गन्ना शोध संस्थान के विवादास्पद उपाध्यक्ष को बचाने के लिए एसपी को हटा देने का मामला हो या मंत्रिमंडल विस्तार में दागियों को चुनने का. जिस मंत्री को एक सीएमओ के अपहरण के आरोप में हटा दिया गया था, उनकी मंत्रिमंडल में वापसी दुखद है साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा उनका बचाव करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है. सपा को भूलना नहीं चाहिए कि अपनी खराब होती छवि के कारण उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में नुक़सान हो सकता है.

अब अलिखेश के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 58 हो गई है. अभी भी मंत्रियों के दो पद खाली हैं. वैसे अभी भी एक दर्जन ऐसे जिले हैं जहां से कोई भी मंत्रिमंडल में किसी को जगह नहीं मिल सकी है. मंत्रिमंडल विस्तार से बुंदेलखंड और महिलाओं के हाथ निराशा लगी है. बहरहाल समाजवादी सरकार ने जिस जरह से जातीय संतुलन बैठाने का प्रयास किया है, उसी तरह की कोशिश अन्य दल भी करते दिखाई दे रहे हैं.

अखिलेश सरकार के विस्तार से यह बात भी साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी भले ही केंद्र सरकार को समर्थन दे रही हो, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पटखनी देना उसकी प्राथमिकता में शामिल है. समाजवादी नेता किसी भी तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं. इसलिए एक तरफ तो वह राहुल और सोनिया के खिलाफ सपा प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की संभावना जताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली व अमेठी से जीते नेताओं को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देकर सपा उन जिलों से मिले समर्थन को लोकसभा चुनाव के लिए भी साथ जोड़े रखना चाहती है. रायबरेली और अमेठी से चुनकर आए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देकर सपा, कांग्रेस को यह संदेश भी देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की ज्यादा तल्खी उसे भविष्य में भारी पड़ सकती है.

लगभग एक वर्ष से सत्ता पर क़बिज समाजवादी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार ने ही राजनीति का पारा ऊपर चढ़ा दिया है. वैसे तो इसे एक सामान्य प्रकिया की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अखिलेश सरकार के गठन के समय ही मंत्रिमंडल में कुछ सीटें खाली रह गईं थीं. शुरुआत में अड़तालीस मंत्रियों के शपथ लेने के बाद यानि एक के निधन और दूसरे को हटा दिए जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की गुंजाइश सबको समझ आ रही थी. कुछ मामलों में अखिलेश मुलायम से अलग नज़र आए. उन्होंने नए मंत्रियों के चयन में युवा चेहरों पर भरोसा करते हुए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है. लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने का हल्ला मचा रहे मुलायम सिंह के बयानों से तो यही लगता है कि भाजपा, कांग्रेस और बसपा को टक्कर देने के लिए सपा व्यूह रचना में जुटी है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अखिलेश कैबिनेट की जो शक्लो-सूरत निकल कर सामने आई है, उसके अनुसार अब उनके मंत्रिमंडल में उन्हें छोड़कर 10 मुस्लिम, 11 ठाकुर, 08 यादव, 07 दलित, 06 ब्राह्मण, 04 कुर्मी, 02 वैश्य और एक-एक सदस्य चौरसिया, निषाद, गुर्जर, प्रजाप्रति, पाल, लोध व शाक्य बिरादरी के हैं. इस तरह से अब अलिखेश के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 58 हो गई है. अभी भी मंत्रियों के दो पद खाली हैं. वैसे अभी भी एक दर्जन ऐसे जिले हैं जहां से कोई भी मंत्रिमंडल में किसी को जगह नहीं मिल सकी है. मंत्रिमंडल विस्तार से बुंदेलखंड और महिलाओं के हाथ निराशा लगी है.

बहरहाल समाजवादी सरकार ने जिस जरह से जातीय संतुलन बैठाने का प्रयास किया है, उसी तरह की कोशिश अन्य दल भी करते दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस लोकलुभावन बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है, तो भाजपा कुंभ में एक बार फिर से हिंदुत्व की अलख जलाने की कोशिश कर रही है. सपाई चुनावी कौशल के सहारे अपनी सरकार की खामियों पर परदा डालने की कोशिश करते दिख रहे हैं. तकरीबन एक साल के सपा शासन का अनुभव अच्छा नहीं है. सांप्रदायिक हिंसा पर अंकुश लगाने में विफलता, नौकरशाही को ताश के पत्तों की तरह फेंटने की आदत, बदहाल क़ानून व्यवस्था और निचले स्तर पर सत्ता के दुरुपयोग के मामले इतने ज्यादा हैं कि कई बार मुलायम सिंह को भी इस पर टिप्पणी करनी पड़ती है. यदि दो टूक शब्दों में कहा जाए, तो अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय रणनीतिकारों ने सरकार की छवि की जगह क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को वरीयता दी है, जिसके सहारे 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जा सके. ■

लोहिया की डगर से भटकी सपा

राकेश कुमार यादव feedback@chauthiduniya.com

प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर बनाई गई समाजवादी पार्टी अब लोहिया की दिखाई डगर को भुला बैठी है. सूबे की समाजवादी सरकार के मंत्री अब समाजवाद से किनारा करते जा रहे हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि अपनी सामंतवादी जड़ों को मजबूत कर अल्प समय में ही गरीब चंद से अमीर चंद बनने की कवायद में जुट गए हैं. इसका सबसे ताजा उदाहरण फैज़ाबाद की अयोध्या विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए सपा विधायक तेजनरायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय का है. जिन्हें हाल में ही प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. उन्हें राज्य सरकार में मनोरंजन कर राज्य मंत्री बनाया गया है. पवन पांडेय ने चुनाव लड़ते समय अपने को सबसे गरीब दिखाते हुए अपना बैंक बैलेंस 66 हजार रुपये घोषित किया था. विधायक बनते ही उन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन में करोड़ों रुपये खर्च कर लोगों को चौंका दिया. इसके बाद सूबे में राज्य मंत्री बनने के बाद गृह जनपद में अपना राजसी स्वागत कराकर एक बार फिर से वह सुर्खियों में आ गए हैं. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार निर्देश जारी कर चुके हैं कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता अपने वाहनों पर हूटर व लाल बत्ती न लगाएं. विजटिंग कार्डों पर सपा मुखिया व मुख्यमंत्री के चित्र न छपवाएं. साथ ही वाहनों पर पार्टी का ध्वज किसी भी सूरत में न लगाएं. विभिन्न मौकों पर लगने वाले होर्डिंगों के संदर्भ में भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. जिनमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला तथा विधानसभा स्तरीय संगठनों द्वारा निर्धारित कार्यकर्ताओं की होर्डिंग संगठन के अध्यक्ष के स्तर से लगाए जाएं. इनमें आयोजक अपना चित्र न लगाएं, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अथवा मुख्य अतिथि के चित्र लगाए जाएं. इसके लिए 15 पदाधिकारियों का चयन भी अखिलेश यादव ने कर दिया है, जो जनपदों में भ्रमण कर इस बात की ताकीद करेंगे कि कौन-कौन इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इन्हीं जिम्मेदारों में तेजनरायण पांडेय भी शामिल हैं, जिनके स्वागत में ही उनके कार्यकर्ताओं ने सपा मुखिया के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए न केवल सैकड़ों होर्डिंग लगवाए, साथ ही गाड़ियों पर झंडे लहराते हुए धूम-धड़ाके से मंत्री का स्वागत भी किया. मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को इतना धन होर्डिगों और फूलों में नहीं करने का निर्देश भी नहीं दिया. यदि स्वागत में खर्च हुए पैसों को नगर के विकास में खर्च किया जाता, तो मंत्री जी की लोगों के बीच पकड़ और मजबूत हो पाती. लेकिन मंत्रीजी के पास इतना कुछ सोचने समझने की फुर्सत ही कहां है. उन्हें तो केवल बारात का दूल्हा बनने में ही आनंद आता है.

बहरहाल, पवन पांडेय के स्वागत के लिए जिले की सीमा में प्रवेश करते ही धूम-धड़ाका शुरू हो गया. उनके स्वागत के लिए लगे होर्डिंगों में कार्यकताओं ने अपने फोटो छपवाए थे. सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि इन होर्डिंगों में कहीं भी बड़े लोहिया (डॉ. राम मनोहर लोहिया) और छोटे लोहिया (जनेश्वर मिश्र) का नामोनिशान नहीं था. उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चल रही थीं. जगह-जगह हुए स्वागत समारोहों में कार्यकताओं ने कहीं 51 किलो की, तो कहीं 151 किलों की माला उन्हें पहनाई. जब उन्होंने अयोध्या विधानसभा में प्रवेश किया, तो उनका स्वागत शादी समारोह की तर्ज पर होने लगा. सहादतगंज चौराहे से वह खुली गाड़ी में सवार हुए. इसके बाद जब रिकाबगंज चौराहे पर पहुंचे, तो उन्हें दूल्हे की टोपी पहनाई गई. ढोल-नगाड़ों के बीच जमकर आतिशबाजी भी की गई. पार्टी कार्यालय में भी खूब नाच-गाना हुआ. कुल मिलाकर मनोरंजन कर राज्य मंत्री का स्वागत राजशाही तरीके से किया गया. इस स्वागत समारोह में कितने रुपये बर्बाद किए गए, यह तो कार्यकर्ता ही बता सकते हैं. यदि कार्यकर्ताओं ने मंत्रीजी के स्वागत में हजारों खर्च किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी मंत्री जी से अपेक्षाएं भी लाखों में होगी.

तेजनरायण पांडेय के निर्वाचन के बाद यहां की जनता को सुविधा कम, दुविधा ज्यादा मिली है. एक साल के भी कम के उनके कार्यकाल में नगर के ऐतिहासिक देवकाली मंदिर की मूर्तियों की चोरी हुई. हालांकि, जिसकी बरामदगी एक माह बाद हो गई थी. मूर्ति बरामद होने के दूसरे ही दिन नगर में दुर्गाप्रतिमा विजर्सन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई. इस घटना के बाद फैज़ाबाद सांप्रदायिक दंगे की चपेट में आ गया. एक सप्ताह तक यहां कर्फ्यू लगा रहा. दंगे के बाद मुआवजा वितरण के नाम पर भी राजनीति हुई. मामले के शांत होने के बाद मुख्यमंत्री जनपद आए. उन्होंने कुछ दंगा पीड़ितों को मुआवजे का चेक भी वितरित किया. चेक वितरण के बाद एक समारोह में नगर विधायक ने खूब वाहवाही लूटी. समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण बताया और खुद को गरीब सुदामा बताकर जिले के विकास के लिए अनुदान मांगा. हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन नए मंत्रिमंडल विस्तार करते ही सुदामा को मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, जिस पर उनके सहयोगी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं. विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा करें, तो अयोध्या विधायक द्वारा किए गए वादों पर अफसरशाही अमल नहीं होने दे रही है. अधिकारियों के लगातार हो रहे स्थानांतरण की वजह से यहां की कई विकास योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं. जिनमें जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाया जा रहा फ्लाई ओवर और 300 बिस्तरों का अस्पताल भी शामिल हैं लेकिन इस तरफ नेताजी का ध्यान ही नहीं जा रहा है. ■

बेअसर रहा लालबत्ती पर स्टिंग ऑपरेशन

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

एक कहावत है, छूरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छूरी पर, दोनों ही स्थिति में कटना खरबूजे को ही पड़ता है. ऐसा ही एक वाकया गोंडा के एसपी नवनीत राणा के साथ हुआ है. पशु तस्करों की पैरवी करने और एसपी गोंडा को रिश्वत के लिए तैयार करने के आरोप में फंसे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त सपा नेता एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष केसी पांडेय की लालबत्ती तो बच गई, लेकिन पशु तस्करी मामले में स्टिंग करने वाले गोंडा के एसपी नप गए. राणा की जगह पहले एचएन सिंह का नाम जरूर आया, लेकिन दिन ढलते-ढलते उनकी जगह आईपीएस राजेंद्र प्रसाद सिंह यादव की नियुक्ति कर दी गई.

मुख्यमंत्री का आजमगढ़ में यह कहना था कि केसी पांडेय का जो प्रकरण मीडिया में उजागर हुआ है, वह बसपा सरकार के समय का है. लेकिन एक दिन पहले अपर पुलिस निदेशक कानून एवं व्यवस्था अरुण कुमार ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि गोंडा के एसपी ने स्टिंग ऑपरेशन उनके ही निर्देश पर 30 दिसंबर को किया था. दरअसल, हुआ यह था कि 23 दिसंबर को गोवंश तस्कर गैंग के मुखिया माजिद के इशारे पर एसपी से कुछ लोग मिलने गए थे. इन लोगों ने एसपी को गोवंश से लदे ट्रकों को सीमा से बाहर निकालने के लिए हर माह आठ लाख रुपये देने की पेशकश की. एसपी ने इन लोगों को बुलाया और पूरी डील सीसीटीवी कैमरे में कैद करवा ली. एसपी से डील करने माजिद गैंग के आशुतोष पांडेय अपने साथियों के साथ वहां आए. उसने एसपी को घूस की पेशकश की, तो वहीं डॉ केसी पांडेय से बात करवा दी. उन्होंने संसदीय बोर्ड के सदस्य होने की हैसियत से बात की, और इसे एसपी ने टेप कर लिया. इसके बाद जैसे ही आशुतोष ने एक लाख रुपये की रिश्वत पेश की, उसे और उसके तीन साथियों को पुलिस ने रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. सपा सरकार के लिए मुसीबत पैदा करने वाला यह एक मात्र वाकया नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी गोंडा जिले के विधायक विनोद कुमार सिंह को राज्यमंत्री बनाया गया था. लेकिन उल्लेखनीय है कि संविदा के आधार पर भर्ती में स्थानीय सीएमओ से इनकी भिड़ंत और सीएमओ के अपहरण के विवाद के कारण मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा लेना पड़ा था. वहीं सपा सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही नटवर गोयल को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया और उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया. लेकिन अफसरों पर दबाव और मीडियाकर्मी से उलझने के चक्कर में इन्हें अंततः जेल जाना ही पड़ा. इसी वजह से इनकी लाल बत्ती छिन गई. 4 जनवरी को साहब सिंह सैनी को बीज प्रमाणीकरण निगम का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया. लालबत्ती लगाकर चलते उन्हें दस दिन भी नहीं गुजरे थे कि साहब 14 जनवरी को एक बैठक में अधिकारियों से भिड़ गए. उसी दौरान उनकी पहली पत्नी ने देहरादून में उनके ख़िलाफ उत्तराखंड में मुक़दमा दर्ज करा दिया.

ऊहापोह में पड़ी सरकार सैनी का मामला सुलझा पाती कि उससे पहले उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के बतौर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री का दर्जा पाए केसी पांडेय ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी. गन्ना शोध संस्थान के बतौर उपाध्यक्ष केसी पांडेय की नियुक्ति के बाद राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर सुदीप सेन के मनोनयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, कोलकाता में कल्चरल इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यवसायी सुदीप सेन के मनोनयन पर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. मालूम हो कि सुदीप सेन का मनोनयन पिछले महीने ही हुआ था. कहते हैं कि सेन ने विधानसभा चुनाव के दौरान सपा को डेढ़ करोड़ रुपये चंदे के रूप में दिए थे. इससे पहले दिसंबर 2011 में उनकी पत्नी अदिति ने भी छह लाख रुपये चंदे के रूप में सपा को दिए थे. सुदीप सेन चंडीगढ़ के प्राचीन कला केंद्र से अनुमोदित गीत, संगीत व नृत्य का इंस्टीट्यूट बसंती विद्या बिथि का संचालन करते हैं. वह नजरूल गीत गायक के रूप में मशहूर हैं. कोलकाता व पड़ोस के जिलों में बसंती विद्या बिथि की 13 शाखाएं हैं. सुदीप उसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी अदिति सेन सचिव हैं. यह संस्था उनके दादा मनोरंजन सेन ने 1928 में स्थापित की थी. इस इंस्टीट्यूट का एक ट्रस्ट भी है, जिसका नाम मनोरंजन सेन स्मृति संसद ट्रस्ट है. बिथि में मुख्य रूप से लड़कियों को रवींद्र संगीत, कत्थक और ओडिसी नृत्य, ठुमरी, शास्त्रीय संगीत, नजरूल गीत, ग़ज़ल, भजन सिखाया जाता है. सेन का मुख्य व्यवसाय बिथि ही है. वह खुद बांग्लादेश के विद्रोही कवि नजरूल इस्लाम के गीतों को गाते हैं. सुदीप सेन के समाजवादी पार्टी से जुड़ाव उनके करीबी सपा महासचिव तथा राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा की वजह से है. जब नंदा सोशलिस्ट पार्टी में थे, तब से उनके साथ हैं. कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी का आरोप है कि सपा सरकार लालबत्ती का सौदा कर रही है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ उसका दावा सिर्फ दिखावा है. भाजपा नेता हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं कि इस घटना की वजह से सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है. विरोधी ही नहीं, सपाई भी इसे नहीं पचा पा रहे हैं. फिलहाल एक जनहित याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गन्ना शोध परिषद के उपाध्यक्ष केसी पांडेय की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह में इस मामले में हलफनामा दाखिल करे, जो कि सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी का न हो. अदालत ने जानना चाहा है कि लोगों को लालबत्ती कैसे दी जाती है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार दीक्षित की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. नूतन ठाकुर की पीआईएल पर दिया. याचिका में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था कि विभिन्न आयोगों, निगमों, कंपनियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों की नियुक्ति संबंधी खास योग्यताओं को ठीक प्रकार से परिभाषित किया जाए. साथ ही नियुक्त होने वाले लोगों की आपराधिक रिकॉर्डों की सतर्कता विभाग से जांच कराई भी जाए. याचिका में पशु तस्करों को संरक्षण देने के आरोप संबंधी मामले में केसी पांडेय की कथित भूमिका की जांच कराए जाने का भी आग्रह किया गया है.

दूसरी ओर बुद्धिजीवियों का तर्क है कि इन नियुक्तियों को केवल इस आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि इन पदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया जाए, जो किसी आपराधिक मामले में वांछित हों. इसी तरह राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति का मनोनयन किया जाए, जिसने सपा को भारी-भरकम चंदा दिया हो. ऐसी नियुक्तियां सरकार की साख को बट्टा लगाने जैसा है. सत्ता का ऐसा इस्तेमाल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सपा पर पैसे लेकर लालबत्ती बांटने का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान का कहना है कि प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में लूट मची है. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि पूंजीपतियों के हाथों में लालबत्तियां सौंपकर सपा सरकार समाजवादी सिद्धांतों को दफन कर रही है. चौहान ने यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा का दावा महज छलावा है. विपक्ष का गन्ना अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त केसी पांडेय को हटाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. पशु तस्करों की संरक्षण देने के आरोपों में घिरे पांडेय के खिलाफ उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. भाजपा सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर पांडेय को तत्काल पद से बर्खास्त करने और मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

फिलहाल राज्य सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन में पशु तस्करी से जुड़े मामले में केसी पांडेय के शामिल होने के प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है. लेकिन जानकारों का मानना है कि यह मामला भी ठंडे बस्ते में न चला जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी कई मामलों में हो चुका है. एसपी के तबादले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रामलीला मैदान में प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है. इसमें अन्य कई हिन्दू संगठन भी शामिल हुए. सभी ने एसपी के तबादले पर सरकार की निंदा की है. भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि सरकार ने नौकरशाही को खतरनाक संदेश दिया है. उसका मनोबल तोड़ा है. यह मामला सदन में उठाया जाएगा. एसपी नवनीत राणा कहना है कि उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है. ■

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष मार्च में तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. उस दौरान 12 मार्च को वह लखनऊ आएंगे.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

क्या मोदी सभी समस्याओं का समाधान हैं?

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी और उसको लेकर बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता भले ही भावी प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करने में बहुत संभल कर बयान दे रहे हों, लेकिन इससे अलग भाजपा और संघ की अन्य अनुवांशिक इकाई कहे जाने वाले संगठनों के प्रतिनिधि भावी प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर कुछ ज्यादा ही उतावले दिख रहे हैं. किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सोच-समझ कर अपनी रणनीति की घोषणा करने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रहा है. उसे इस बात की भी चिंता नहीं दिखाई दे रही है कि यदि मोदी का नाम जद(यू)(जनता दल यूनाइटेड) की सहमति के बिना प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जाता है, तो राजग टूट जाएगा. यही वजह थी कि महाकुंभ में 07 फरवरी को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद व संत महासम्मेलन में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संतों के सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए. इस मौके पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर से जन आंदोलन की घोषणा की और रामलला हम आएंगे, संसद में कानून बनाएंगे का नारा भी दिया. धर्म संसद और संत सम्मेलन का पूरा नजारा हिंदुत्व के इर्द-गिर्द ही नज़र आया. मोदी को लेकर धर्म संसद में आलम यह था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अपील भी उस समय बेअसर दिखी, जब कुछ संतों ने परोक्ष रूप से, तो कुछ ने खुलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत की. कुंभ मेले में जुटे आरएसएस के करीबी साधु-संतों की धर्म की बजाए राजनीतिक आस्था हिचकोले ले रही थी. धर्म संसद में ऐसे धर्मगुरुओं की संख्या भी कम नहीं थी, जो यह मानकर चलते हैं कि साधु-संतों को अपना सारा ध्यान धर्म के कार्यों में ही लगाना चाहिए. राजनीति में दखल देने और शामिल होने से उनकी गरिमा का ह्रास होगा. यहां बात केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा पर नहीं रुकी, बल्कि साधु-संतों ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी उनकी अमर्यादित टिप्पणी के लिए भला-बुरा कहा. संतों का कहना था कि शिंदे को हिंदू धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अगर होता तो वह हिंदुओं को आतंकवादी बताने की जुर्रत कभी नहीं करते.

धर्म संसद और संत महासम्मेलन का आयोजन इलाहाबाद में वासुदेवानंद सरस्वती के बद्रिका आश्रम में हुआ. इसमें स्वामी श्रीरामानुजायार्य, स्वामी विवेवरानंद, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेता अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, आचार्य गिरिराज किशोर भी मौजूद थे. कांची कामकोट्टि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने धर्म संसद की अध्यक्षता की. विहिप के कई बड़े नेताओं और कुछ संतों की ना-नुकर के बाद भी धर्म संसद अपने इरादों से नहीं हटी. कुछ धर्मगुरुओं और हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले वक्ताओं का कहना था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है. वह विकास पुरुष हैं. मंच पर बैठे संत मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का राग छेड़े हुए थे, उस दौरान बाहर जुटी भीड़ मोदी लाओ, देश बचाओ के नारे लगा रही थी. कुंभ मेले में सुबह-सुबह डुबकी लगाने पहुंचे मोहन भागवत से जब मीडिया ने देश की राजनीति पर बात की, तब वह बोले कि मैं यहां राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं आया हूं. हालांकि शाम होते ही उनके सुर बदल गए. संघ प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे पर प्रहार करते हुए राम जन्मभूमि को देश की अस्मिता का सवाल बताया. उन्होंने कहा कि हिंदू न हिंसक होता है और न ही आरएसएस का कार्यकर्ता. हिन्दुत्व और संघ पर उंगली उठाने वालों को जनता सबक सिखाएगी. भावी प्रधानमंत्री के संबंध में वह खुल कर कुछ नहीं बोले, लेकिन यह जरूर कहा कि मोदी मेरे मित्र हैं. मैं चाहूंगा कि संत उन्हें आशीर्वाद दें. उन्होंने कहा, इस समय भाजपा की ओर से पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, इसलिए भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए.

बहरहाल, मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने को लेकर भाजपा, संघ और उनके अनुवांशिक संगठनों में काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है. संघ और इसके करीबी साधु-संतों को लगता है कि मोदी ही सभी समस्याओं

मोदी को लेकर धर्म संसद में आलम यह था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अपील भी उस समय बेअसर दिखी, जब कुछ संतों ने परोक्ष रूप से, तो कुछ ने खुलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत की. कुंभ मेले में जुटे आरएसएस के करीबी साधु-संतों की धर्म की बजाए राजनीतिक आस्था हिचकोले ले रही थी. धर्म संसद में ऐसे धर्मगुरुओं की संख्या भी कम नहीं थी, जो यह मानकर चलते हैं कि साधु-संतों को अपना सारा ध्यान धर्म के कार्यों में ही लगाना चाहिए.

का समाधान हैं, लेकिन भाजपा मोदी के नाम के आने पर सहयोगी दलों के बिदकने की संभावना से चिंतित दिखाई पड़ रही है. बात यहीं तक सीमित रहती, तो भी कोई बात नहीं थी. मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बना कर यदि राजग ने चुनाव लड़ा, तो हिंदू वोट एकमुश्त भाजपा के पक्ष में पड़ ही जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटों का कांग्रेस अथवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण होने की संभावना ज्यादा है. उम्मीद इसी बात की है कि लोकसभा चुनाव के समय मोदी के खिलाफ मुस्लिम एकजुट होकर सपा की बजाए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस प्रबल दावेदार रहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी को दूसरे सहयोगी दलों के रहमों-करम पर आगे बढ़ना होगा. मोदी को चेहरा बनाकर चलने में भाजपा और राजग की राह में इस तरह की कई परेशानियां आ सकती हैं. यदि भाजपा मोदी को आगे करके बहुमत में आती है, तब कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन राजग सरकार बनाने के लिए राजग को जोड़तोड़ करनी पड़ी और नए सहयोगियों की जरूरत पड़ी, तो मोदी के नाम पर कोई भी साथ आने से पहले हजार बार सोचेगा.■

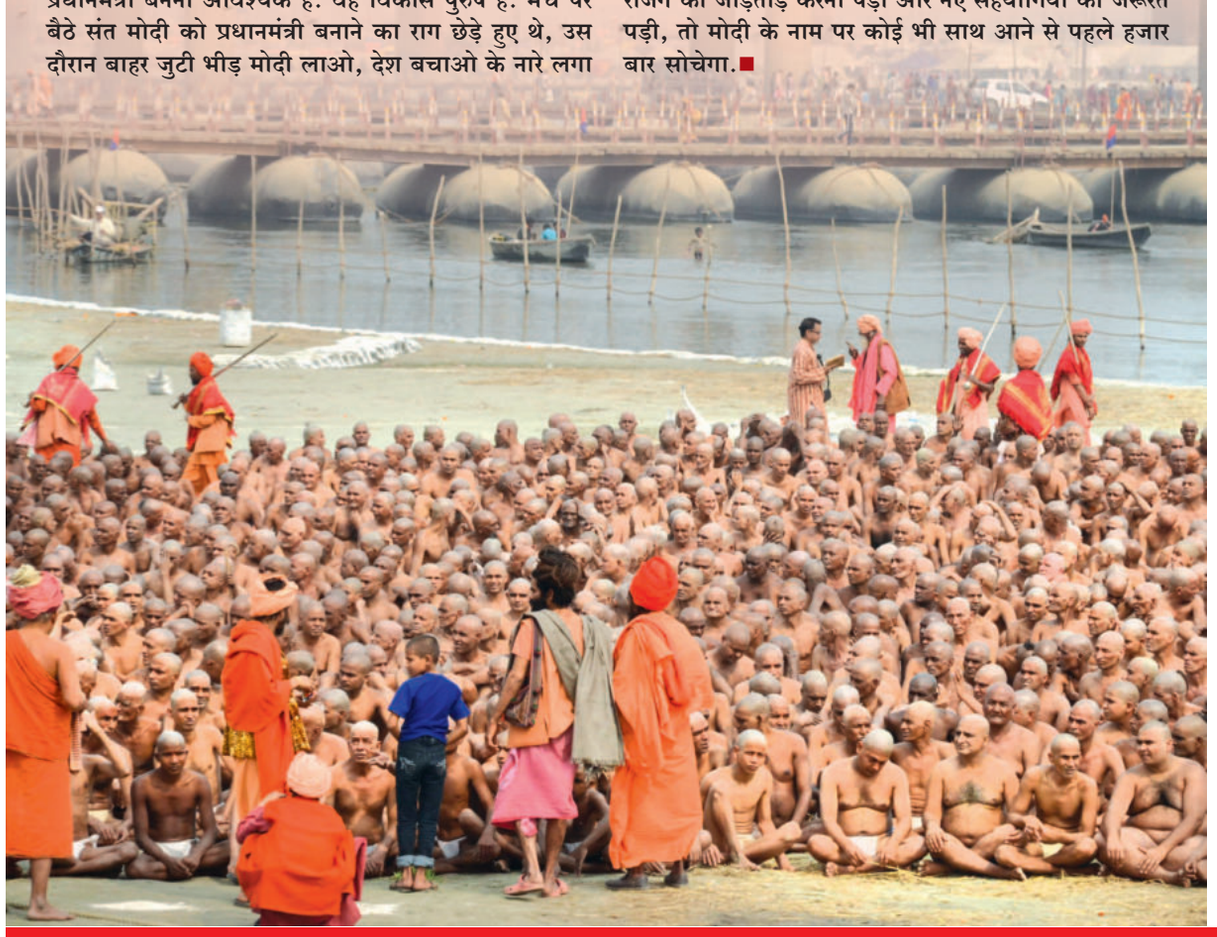

करीब आ सकते हैं खंडूरी-कोश्यारी

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं. इस कुर्सी पर उन्हें बैठाने में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों भुवन चंद्र खंडूरी एवं डॉ. रमेश पोखरियाल ने अहम भूमिका अदा की है. तीरथ सिंह रावत के हाथों में प्रदेश भाजपा की कमान सौंपना खंडूरी एवं निशंक की बढ़ती घनिष्ठता का ही परिणाम है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खंडूरी-निशंक की यह एकता कितने दिनों तक चल पाएगी. यह सवाल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही उठाने लगे हैं. दरअसल, इसे राजनाथ सिंह की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हुई ताजपोशी के परिणाम के रूप में भी देखा जा रहा है. इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक संबंध अतीत में कैसे रहे हैं, यह बात उत्तराखंड में सबको मालूम है.

प्रदेश अध्यक्ष के चयन के दौरान दोनों ने मिलकर जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पटखनी दी है, उसे उत्तराखंड में भाजपा के लिए शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है. खंडूरी-निशंक के साथ यदि कोश्यारी भी आ जाते हैं, तो आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश भाजपा को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा. प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं, इससे यह साफ है कि कोश्यारी के लिए निशंक-खंडूरी के साथ मिलकर काम करना सहज नहीं होगा. हालांकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अभी से यह कोशिश कर रहा है कि तीनों आपस में मिलकर काम करें. प्रदेश भाजपा मुख्यालय से मिल रही सूचनाओं के मुताबिक, ऐसा होना कतई संभव नहीं है. पहले तो लोगों को खंडूरी-निशंक गठजोड़ लंबे समय तक बने रहने की आशा नहीं है, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं है. इसलिए किसी भी समय दोनों का मिजाज बदल सकता है. ऐसे में पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि निकाय एवं पंचायत चुनावों के टिकट बंटवारे के समय ही दोनों के बीच खींचतान बढ़ सकती है. क्योंकि दोनों ही अपने-अपने समर्थकों को प्रत्याशी बनते देखना चाहेंगे. दोनों के बीच समन्वय स्थापित करवाने में नए अध्यक्ष की भूमिका भी देखने लायक होगी. वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं की लड़ाई पूरी तरह से स्वार्थ की है. ऐसे में खंडूरी के कोश्यारी के साथ गठजोड़ करने की संभावना भी जताई जा रही है. बताते चलें कि विधान सभा चुनाव के पहले जब दूसरी बार प्रदेश की कमान खंडूरी के हाथों में आई थी, तब कोश्यारी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. खंडूरी-कोश्यारी गठजोड़ के बाद भाजपा को प्रदेश की सत्ता जरूर गंवानी पड़ी, लेकिन उनके लिए परिणाम ज्यादा निराशाजनक नहीं रहे थे. कांटे की टक्कर के बाद भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा. यदि भाजपा हाईकमान द्वारा हरी झंडी दिखाई गई होती, तो संभवत: भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करती. गौरतलब है कि हाईकमान ने उस समय कन्नी काट ली थी.

बहरहाल, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह रावत पर विश्वास करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. अब तीरथ प्रदेश भाजपा को नई गति एवं दिशा किसके इशारे पर देते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. भाजपा ने पहले ही नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक ब्राह्मण को बैठा रखा है, अब अध्यक्ष पद एक राजपूत को सौंपकर उसने जातीय गणित को साधने की कोशिश की गई है.■

राजनाथ के इशारे पर रावत की ताजपोशी

राजनाथ सिंह के इशारे पर चौबट्टाखाल विधायक तीरथ सिंह रावत की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई है. ताजपोशी के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश में मार्च-अप्रैल में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, यह भाजपा के लिए एक सियासी चुनौती है. गौरतलब हो कि पंचायत चुनाव पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं लड़ती हैं. दरअसल इसमें अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत से वह पंचायत स्तर पर अपनी सियासी पकड़ की नाप-जोख करती हैं. वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने होती हैं.

इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी जिस तरह कोश्यारी और खंडूरी-निशंक खेमों में बंटी नजर आ रही थी, इसका खमियाजा उसे इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है. प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भाजपा निर्वाचक मंडल के अधिकांश नेता तीरथ सिंह रावत के पक्ष में थे. आगामी चुनाव को देखते हुए उसने पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपना फैसला थोपने से परहेज किया और तीरथ सिंह रावत के नाम पर तुरंत मुहर लगा दी. वैसे भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ कि उसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जिसके पक्ष में बहुमत था. ■ -रेनू शर्मा

विश्व बैंक के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आएंगे

संजय सक्सेना feedback@chauthiduniya.com

विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम मार्च में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. वह यहां विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाली विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं के प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग 15 दिन के अंदर भारत सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को प्रस्तुत कराए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष मार्च में तीन दिवसीय दौरे पर भारत आयेंगे. उस दौरान 12 मार्च को वह लखनऊ आएंगे. वह कानपुर नगर में प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे. उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर आजकल भारत में हैं. वह 12 फरवरी को लखनऊ में तैयारियों का जायजा लेने आए थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने प्रदेश की योजनाओं के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2 मिलियन डॉलर की धन राशि स्वीकृत की है. दरअसल इसी राशि से नई परियोजनाएं तैयार की जाएंगी. मुख्यमंत्री से कंट्री डायरेक्टर की मुलाक़ात के बाद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने बताया कि पर्यटन, ऊर्जा, लोक निर्माण, सिंचाई आदि विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि विश्व बैंक द्वारा नामित सदस्यों से समन्वय स्थापित कर विभागीय परियोजनाएं तैयार करें. उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को तत्काल भेजें. उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि विभागवार कार्यों को समय से निष्पादित कराने के लिए समय सारिणी बनाकर कार्ययोजना में तेजी लाई जाए. वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओनो रूहल से मुख्यमंत्री के मुलाक़ात के दौरान मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य एवं संबंधित विभागों के सचिव भी उपस्थित थे.■

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366